



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

xxxGIDHxxx

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08022023-243522

CG-DL-E-08022023-243522

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 7, 2023/माघ 18, 1944

No. 46]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 7, 2023/MAGHA 18, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2023

अंतिम जांच परिणाम

विषय: इंडोनेशिया, मलेशिया, और थाइलैंड से “सेचुरेटेड फैटी एल्कोहल” के आयातों से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क/सब्सिडीरोधी जांच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 6/18/2021-डीजीटीआर - समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं की पहचान उन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए:

- मैसर्स वीवीएफ इंडिया लिमिटेड (जिसे इसके बाद “याचिकार्कर्ता” या “आवेदक” भी कहा गया है) ने समय समय पर यथासंशोधित (जिसे इसके बाद “प्राधिकारी” भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं की पहचान उन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “नियमावली” भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से एक आवेदन दायर किया है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड (जिन्हें आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) से “सेचुरेटेड फैटी एल्कोहल” जिनकी कार्बन शुब्खला की लंबाई सी 10, सी 12, सी 14, सी 16 या सी 18 है (जिनमें ब्रांच आइसोमर्स शामिल नहीं हैं) सिंगजल सेचुरेटेड फैटी एल्कोहल

(जिन्हें 'सिंगल कट्स भी कहा जाता है) और उनके मिश्रण शामिल हैं (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "पीयूसी" या "एसएफए" भी कहा गया है) के आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. और, यतः, प्राधिकारी ने नियम 6 के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर संबद्ध जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. 6/18/2021- डीजीटीआर दिनांक 8 फरवरी, 2022 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की ताकि कथित सब्सिडी की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित किया जा सके तथा सब्सिडीरोधी/प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. प्रक्रिया

3. संबद्ध जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

- क) प्राधिकारी ने संबंधित नियम 6 के उप नियम (5) के अनुसार जांच की शुरुआत से पहले वर्तमान सब्सिडीरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों को दूतावासों को अधिसूचित किया।
- ख) प्राधिकारी ने स्थिति को स्पष्ट करने और सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क उपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 13 के अनुसार परस्पर सहमत समाधान निकालने के उद्देश्य से इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड की सरकार को आमंत्रित किया। यह परामर्श थाइलैंड की सरकार के साथ 21.01.2022 को और इंडोनेशिया की सरकार तथा मलेशिया की सरकार के साथ 28.01.2022 को कोविड-19 महामारी के कारण वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए थे। इन विचार-विमर्शों में इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड की सरकारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संबंधित सरकारों ने सब्सिडी कार्यक्रम की मौजूदगी से इंकार किया, तथापि इसका कोई साक्ष्य नहीं दिया था।
- ग) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क/सब्सिडीरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 8 फरवरी, 2022 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
- घ) प्राधिकारी ने दिनांक 8 फरवरी, 2022 की जांच शुरुआत अधिसूचना की एक एक प्रति संबद्ध देशों के दूतावासों, याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग तथा अन्य घरेलू उत्पादकों को भेजी थी और उनसे विहित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया था।
- ङ.) जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी ने उचित तुलना के लिए हितबद्ध पक्षकारों से प्रस्तावित पीसीएन पद्धति के संबंध में टिप्पणियां भी मंगाई थीं। हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों पर विचार किया गया था और तत्पश्चात दिनांक 10 मार्च, 2022 के पत्र द्वारा हितबद्ध पक्षकारों से पीसीएन पद्धति के अनुसार प्रश्नावली का उत्तर देने का अनुरोध किया गया था।
- च) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 7(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक-एक प्रति उपलब्ध कराई थी।
- छ) भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से उनके देश से निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध भी किया गया था। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति तथा संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम तथा पते भी दूतावासों को भेजे गए थे।
- ज) प्राधिकारी ने विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों जिनमें संभवतः सरकारों द्वारा प्रतिसंतुलन योग्य लाभ दिया गया हो, के संबंध में संगत तथ्य/सूचना मंगाने के लिए संबद्ध देशों की सरकारों को प्रश्नावलियां भेजी थीं।
- झ) प्राधिकारी ने नियमावली नियम 7(4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थीं:
 - i. पीटी. मुजिम मास, इंडोनेशिया
 - ii. पीटी. इकोग्रीन ओलियो केमिकल्स, इंडोनेशिया

- iii. पीटी. एनर्जिसेजाटेरा मास, इंडोनेशिया
- iv. पीटी. विलमर नाबाती, इंडोनेशिया
- v. इमर्जी ओलियोकेमिकल्स एसडीएनद्व बीएचडी, मलेशिया
- vi. केएलके ओलिया, मलेशिया
- vii. एफजीपी ओलियोकेमिकल्स एसडीएन बीएचडी, मलेशिया
- viii. थाई फैटी एल्कोहल कं. लिमि., थाइलैंड

ज.) इसके उत्तर में संबद्ध देशों से निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों में विहित प्रपत्र में निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया:

- i. पीटी. मुजिम मास, इंडोनेशिया
इंटर-कॉन्टीनेटल ऑयल्स एंड फैट्स पीटीई लिमि. सिंगापुर
- ii. पीटी. इकोग्रीन ओलियोकेमिकल्स, इंडोनेशिया
इकोग्रीन ओलियोकेमिकल्स (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड
- iii. पीटी. एनर्जिसेजाटेरा मास, इंडोनेशिया
सिनारमाससेपसा पीटीई. लिमिटेड. सिंगापुर
- iv. पीटी. विलमार नाबाती, इंडोनेशिया
नैचुरल ओलियोकेमिकल्स एसडीएन बीएचडी, मलेशिया
विलमार ट्रेडिंग पीटीई लिमिटेड सिंगापुर
- v. ऐमेरी ओलियोकेमिकल्स (एम) एसडीएन. बीएचडी., मलेशिया
ऐमेरी ओलियोकेमिकल्स रिका (एम) एसडीएन बीएचडी
- vi. केएलके ओलियो, मलेशिया
- vii. एफपीजी ओलियोकेमिकल्स एसडीएन बीएचडी, मलेशिया
प्रोक्टर एंड गैम्बल इंटरनेशनल ऑपरेशंस एसए सिंगापुर
- viii. थाई फैटी एल्कोहल्स कंपनी लिमिटेड, थाइलैंड
ग्लोबल ग्रीन केमिकल्स पब्लिक कं. लिमिटेड, थाइलैंड
- ix) यूनिलीवर एशिया प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर

ट) जांच शुरुआत अधिसूचना के अनुपालन में संबद्ध देशों से उक्त उत्पादकों/निर्यातकों के अलावा, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड की सरकार ने भी प्रश्नावली का उत्तर दिया है।

ठ) प्राधिकारी ने नियम 7(4) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं को आवश्यक सूचना मंगाते हुए आयातक प्रश्नावलियां भेजी थीं:

- i. मैसर्स ग्लैक्सी सरफैक्टेंट्स लिमिटेड
- ii. विस्वाट केमिकल्स लिमिटेड
- iii. रहोडिया स्पेशिलिटी केमिकल्स इंडिया लिमिटेड
- iv. इंडियन ग्लाइकोल लिमिटेड
- v. स्टलिंग ऑक्सलियरिज प्राइवेट लिमिटेड
- vi. माटंगी इंडस्ट्रीज

- vii. वीनस एथोक्सीलेट्स प्राइवेट लिमिटेड
- viii. गुजरात केमिकल्स
- ix. आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- x. कुसा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
- xi. कृष्णा आंटिओक्सीडेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
- xii. बीएएसएफ इंडिया

ड) इसके उत्तर में निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने उत्तर दिया है और आयातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।

- i. गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- ii. ग्लैक्सी सरफैक्टेंट्स लिमिटेड
- iii. विस्वाट केमिकल्स लिमिटेड
- iv. इंडियन ग्लाइकोल्स लिमिटेड
- v. क्लियरेंट आईजीएल स्पेशिलिटी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
- vi. हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड
- vii. आरती करफैक्टेंट्स लिमिटेड

ड) ऊपर उल्लिखित प्रतिवादी निर्यातकों और आयातकों के अलावा, इस जांच की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित पक्षकारों की ओर से कुछ कानूनी अनुरोध प्राप्त हुए हैं:

- (i) इंडियन सरफैक्टेंट एसोसिएशन

ण) आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी।

त) कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण सभी हितबद्ध पक्षकारों से उनके सभी अनुरोधों के अगोपनीय अंश को ई-मेल के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा करने के लिए कहा गया था। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर संगत समझी गई सीमा तक इन अंतिम जांच परिणामों में विचार किया गया है।

थ) यह याचिका वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से 2018-19 से मई, 2021 तक की अवधि के लिए प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। याचिकाकर्ता ने बताया था कि जून, 2021 से सितंबर, 2021 तक की अवधि के लिए बार-बार अनुरोध करने के बावजूद उन्हें आंकड़े नहीं दिए गए थे। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने जांच अवधि अर्थात् अक्टूबर, 2020 – सितंबर, 2021 के लिए आंकड़े प्रस्तुत करने हेतु अक्टूबर, 2020 – मई, 2021 की अवधि के आंकड़ों का परिकलन किया था।

द) प्राधिकारियों द्वारा सिस्टम्स महानिदेशालय (डीजीएस) से पिछले तीन वर्षों और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के सौदावार व्यौरे प्रदान करने का अनुरोध किया गया था, जो प्राधिकारी को प्राप्त हुए थे। प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आंकड़ों पर अप्रैल 2018 से मई 2021 की अवधि के लिए विचार किया था (डीजीएस आंकड़ों से आमेलित) और सौदों की आवश्यक जांच के बाद आयात की मात्रा के परिकलन और अपेक्षित विश्लेषण के लिए जून, 2021 से सितंबर, 2021 की अवधि हेतु डीजीएस आंकड़ों पर विचार किया है।

ध) सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और उसे बनाने तथा बेचने की लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) ज्ञात की गई थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या सबिसडी मार्जिन से कम प्रतिसंतुलनकारी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

न) आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना का प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी गई सीमा तक मौके पर सत्यापन के ज़रिए वास्तविक निरीक्षण किया गया था। आवश्यक सुधार, जहां लागू हो, सहित केवल ऐसी सत्यापित सूचना पर वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ भरोसा किया गया है।

प) थाइलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया के उत्पादकों/निर्यातकों तथा उनकी सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना का प्राधिकारी द्वारा आवश्यक सीमा तक सत्यापन किया गया था और वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ ऐसी सत्यापित सूचना पर भरोसा किया गया है।

फ) वर्तमान सब्सिडीरोधी जांच के प्रयोजनार्थ, जांच की अवधि अक्टूबर 2020 से सितंबर 2021 (12 महीने) की है। तथापि क्षति जांच अवधि में 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा पीओआई की अवधि पर विचार किया गया है। क्षति विश्लेषण करते समय 2020-21 और पीओआई के बीच छह महीने की अतिव्यापी अवधि पर विचार किया गया है।

ब) सीवीडी नियमावली के नियम 7(6) और व्यापार सूचना सं. 01/2020 दिनांक 10 अप्रैल, 2020 के अनुसार प्राधिकारी ने बीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए 07 जुलाई, 2022 को मौखिक सुनवाई आयोजित की ताकि हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारी के समक्ष मौखिक रूप से संगत सूचना प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा सके। मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी पक्षकारों को मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को लिखित में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। लिखित अनुरोधों का अगोपनीय अंश ईमेल द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया था और खंडन अनुरोध, यदि कोई हों, करने का अवसर दिया गया था।

भ) हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त लिखित अनुरोधों/खंडन में दिए गए तर्कों पर वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है।

म) इस जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का, जहां उन्हें संगत पाया गया, प्राधिकारी द्वारा इन अंतिम जांच परिणामों में समाधान किया गया है।

य) गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रदान करने का निर्देश दिया है।

कक्ष) जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराया है या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इन अंतिम जांच परिणामों को दर्ज किया है।

खख) नियमावली के नियम 18 के अनुसार, जांच के आवश्यक तथ्यों को, दिनांक 22 सितंबर, 2022 के प्रकटीकरण विवरण के तहत, ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट कर दिया गया था और उनके संबंध में प्राप्त टिप्पणियों को प्राधिकारी द्वारा संगत पाए गए अनुसार, इन अंतिम जांच परिणामों में शामिल किया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटीकरण विवरणों के उपरांत की अधिकांश टिप्पणियां केवल उनके पिछले अनुरोधों की पुनरावृत्ति ही है। तथापि, प्रकटीकरण विवरणों के उपरांत की टिप्पणियों के लिए उनके संगत पाए जाने के अनुसार इन अंतिम जांच परिणामों में जांच की जा रही है।

गग) संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर=74.6 रु. है।

घघ) इन अंतिम जांच परिणामों में ***चिन्ह किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत और नियमावली के अन्तर्गत, प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच शुरुआत के समय विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “सेचुरेटेड फैटी एल्कोहल”, सी 10, सी12, सी14, सी16 या सी 18 की कार्बन श्रृंखला चेन लेंथ (जिसमें ब्रांच आइसोर्मर्स शामिल नहीं हैं) हैं जिसमें सिंग सेचुरेटेड फैटी एल्कोहल (जिसे ‘सिंगल कट’ भी कहा जाता है) और उनके मिश्रण शामिल हैं।

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में नियातिकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- क) याचिकाकर्ता प्योर कट्स अर्थात् सी 10, सी12, और सी 14 का उत्पादन नहीं करता है और इसलिए इन्हें पीयूसी के दायरे से बाहर रखना चाहिए।
- ख) सी 12 और उसके मिश्रण याचिकाकर्ता द्वारा विनिर्मित उच्चतर कट्स (सी1618) से वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं, उनकी कच्ची सामग्री, उत्पादन प्रक्रिया और अंतिम उपयोग अलग हैं।
- ग) याचिकाकर्ता आयातित डिस्टिल्ड फैटी एसिड से सी 12-14 एल्कोहल का निर्माण कर रहा है जिसमें कोई खास मूल्यवर्धन शामिल नहीं है। अतः याचिकाकर्ता को सी1214 का उत्पादक नहीं माना जा सकता है और इसलिए उसे पीयूसी के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
- घ) सी 12 और उसके मिश्रणों को याचिकाकर्ता द्वारा निर्मित किए जा रहे हायर कट (सी 1618) के साथ वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। वे अलग कच्ची सामग्री हैं, उनकी उत्पादन प्रक्रिया और अंतिम उपयोग अलग हैं।
- ड.) याचिकाकर्ता आयातित डिस्टिल्ड फैटी एसिड से सी 12-14 एल्कोहल का निर्माण कर रहा है, जो कि मूल्यवर्धन में शामिल नहीं होता। अतः याचिकाकर्ता पर सी 1214 के एक उत्पादक के रूप में विचार नहीं किया जा सकता और इसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए।
- च) यह भी दावा किया गया है कि विशुद्ध सी 12 और सी 14 के मिश्रण से उत्पन्न सी 1214 का भिन्न रासायनिक विनिर्देशन है और इसलिए यह आयात किए जा रहे सी 1214 से समान वस्तु नहीं हैं।
- छ) पाटनरोधी अन्तिम जांच परिणाम दिनांक 23.04.2018 की फाइल सं. 14/51/2016-डीजीएडी पर भरोसा किया गया है, जहां सी 10 (विशुद्ध) को याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तुओं के “समान वस्तु” के रूप में नहीं पाया गया था। यह अनुरोध किया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता वाणिज्यिक मात्रा में सी 10 का निर्माण नहीं करता, अतः इसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- ज) याचिकाकर्ता विशुद्ध सी 10 का उत्पादन करने के लिए संबद्ध देशों और अन्य देशों से मूल इनपुट अर्थात् सी 8-10 फैटी एसिड का आयात कर रहा है। चूंकि वे मूल इनपुट का आयात कर रहे हैं, अतः उन्हें हाल की जांच में अपनाई गई डीजीटीआर की प्रक्रिया के तहत उस उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना जा सकता।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- क) वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद कार्बन चेन लेंथ सी 10 से सी 18 के “सेचुरेटेड फैटी एल्कोहल” (एसएफए) और उनके मिश्रण हैं। पीयूसी का प्रयोग मुख्यतः फैटी एल्कोहल सल्फेट्स, फैटी एल्कोहल एथेक्सीलेट्स और फैटी एल्कोहल इथर सल्फेट्स, जिसे सरफैक्टेंट्स भी कहा जाता है, में आगे प्रसंस्करण के लिए मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में किया जाता है।
- ख) फैटी एल्कोहल का प्रयोग प्राथमिक रूप से सरफैक्टेंट्स के निर्माण, परसनल केयर, होम केयर, और भेषज तथा कुषि संबंधित अंतिम अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग चमड़े, वस्त्र, फर, पल्प, पेपर, पैट्रोलियम उत्पाद, फाइल केमिकल्स, रबड़ उत्पाद, प्लास्टिक और फैब्रिकेटेड धातु उत्पाद की वस्तुओं के प्रसंस्करण के संबंध में भी किया जाता है। अन्य अनुप्रयोगों में खनन, आफसोर प्रचालन, विनिर्माण कार्य तथा डी-ग्रीसिंग प्रयोजनों के लिए विलायक के रूप में शामिल हैं। पीयूसी का प्रयोग सिंथेटिक इंटरमीडिएट या एंटी-फ्रीज या इमलीफाइंग एंजेंट के रूप में भी होता है। इसका प्रयोग पेंट, लुब्रिकेंट,

कॉस्मेटिक, खाद्य निर्मितियों आदि के उत्पादन में भी होता है। फैटी एल्कोहल के विभिन्न ग्रेड एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। उपभोक्ता विस्कोसिटी, विलेयकता, फोमिंग विशेषताओं आदि के संबंध में अपनी जरूरत के आधार पर विशेष कार्बन चेन लेथ के फैटी एल्कोहल का चयन करता है।

- ग) एसएफए के विभिन्न ग्रेडों का उत्पादन (कार्बन चेन लंबाई) सीपीकेओ के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए होता है। सीपीकेओ में अंतर-निहित रूप से विभिन्न कार्बन चेन लंबाई शामिल होती है, जिसे उत्पादक द्वारा निकाले जाने वाले वांछित ग्रेड (कार्बन चेन लंबाई) के आधार पर विभाजित किया जाता है।
- घ) याचिकाकर्ता विगारोल सी10 पंजीकृत व्यापारी नाम के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता के प्राकृति सेचुरेटेड फैटी एल्कोहल का उत्पादन करता है। उसके पास लघु श्रृंखला वेगारोल सी10 (डिसाइल एल्कोहल) से वेगारोल सी22 (बहनाइल एल्कोहल) से फैटी एल्कोहल की संपूर्ण रेंज का निर्माण करने की क्षमता है और कौन से ग्रेड का निर्माण करना है, इसका निर्णय उपभोक्ता की वरीयताओं और मांग के अनुसार किया जाता है।
- इ.) भारत में अधिकांश आयात सी1214/सी1216 ग्रेड के हैं, क्योंकि उक्त ग्रेड की भारत में सर्वाधिक मांग है। इसके विपरीत, वर्तमान में प्योर कट सी12 और सी14 ग्रेडों के लिए मांग काफी सीमित है। प्योर कट सी12 और सी14, सी1214 मिश्रण से प्रतिस्थापनीय हैं।
- च) याचिकाकर्ता द्वारा वैकल्पिक उत्पादन माध्यमों में से एक उत्पाद माध्यम में, सी1214 ग्रेड का निर्माण स्पिलिट फैटी एसिड का उपयोग करके किया है। स्पिलिट फैटी एसिड (एससीपीकेओ) का उत्पादन पाम कर्नेल ऑयल से किया जाता है। याचिकाकर्ता अपेक्षित मिश्रण (अर्थात् सी1214 फैटी एसिड, इस मामले में) के डिस्टिल किए गए फैटी एसिड का उत्पादन करने के लिए एससीपीकेओ का आंशिक डिस्टिलेशन करता है। उसके बाद सी1214 फैटी एसिड को वेक्स इस्टर हाइड्रोजन लिसिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके सी1214 फैटी अल्कोहल हासिल करने के लिए परिवर्तित किया जाता है। एक विकल्प के रूप में, सी1214 के मिश्रण को पहले विशुद्ध सी12 और सी14 ग्रेडों का उत्पादन करके भी उत्पादित किया जा सकता है और उसके बाद किसी अतिरिक्त लागत को व्यय किए बिना सामान्य मिश्रण की प्रक्रिया का ज़रिए मिश्रित किया जाता है।
- छ) प्योर सी12 और सी14 एल्कोहल के उत्पादन और उसके बाद उन्हें मिलाने या सी1214 ग्रेड का सीधे निर्माण करने का विकल्प गतिशील है और उसका बाजार मांग तथा मार्जिन के प्रचलित कारकों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। इसके अलावा, अंतिम प्रयोग के अनुसार सी12, सी14 प्योर कट ग्रेड और उनके मिश्रण अंतर परिवर्तनीय हैं। इसके अलावा, किसी टंकी में किसी अतिरिक्त लागत के बिना दोनों प्यारे कट को केवल मिलाना तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य है। इसलिए प्योर सी12 और सी14 को विचाराधीन उत्पाद से बाहर रखने से पीयूसी पर शुल्क लगाने का पूरा प्रयोजन विफल हो जाएगा। इस संबंध में याचिकाकर्ता भी संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पूर्ववर्ती पाटनरोधी जांच में अंतिम जांच परिणाम फाइल सं. 14/51/2016-डीजीएडी दिनांक 23.04.2018 पर भी भरोसा करता है जिसमें सी12 और सी14 प्योर ग्रेड को बाहर रखने के दावे को प्राधिकारी ने अस्वीकृत किया था।
- ज) याचिकाकर्ता ने यह भी बताया था कि उसने वाणिज्यिक मात्राओं में सी10 ग्रेड का उत्पादन और बिक्री की थी, इसलिए उसे बाहर नहीं रखा जा सकता है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे और घरेलू उद्योग द्वारा बेची गई समान वस्तु के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है। विचाराधीन उत्पाद के संबंध में, प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:

- क. जांच में सबसे पहला कदम विचाराधीन उत्पाद की पहचान करना है। विचाराधीन उत्पाद वह आयातित उत्पाद है जो कथित रूप से घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है। विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और आयात आंकड़ों की जांच के आधार पर प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद कार्बन चेन लंबाई सी 10 से सी18 का सेचुरेटेड फैटी एल्कोहल और उसके मिश्रण हैं। विचाराधीन उत्पाद में प्योर सी10, सी12, सी14, सी16 और सी18 तथा उनके मिश्रण शामिल हैं। विचाराधीन उत्पाद सीटीएच 2905 17 (प्योर कट) और 3823 70 (मिश्रण) के अन्तर्गत वर्गीकरण योग्य हैं। टैरिफ वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ख. जहां तक विशुद्ध सी12 और सी14 को इस आधार पर अलग करने के लिए दावे का संबंध है कि उसे घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित नहीं किया गया था, यह नोट किया जाता है कि इस मामले की संबद्ध वस्तुओं के संबंध में आयोजित पाटनरोधी अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना फा. सं. 14/51/2016-डीजीएडी, दिनांक 23.04.2018 के अनुसार जांच की गई है, जिसमें कि यह पाया गया था:-

“ सी12 और सी14 अल्कोहल के विशुद्ध रूप को बाहर करने के संबंध में, प्राधिकारी घरेलू उद्योग के तर्क में बल पाते हैं कि उसने सी12सी14 अल्कोहल का उत्पादन और बिक्री की है। वास्तव में, सी12सी14 के पास भारत में सबसे अधिक मांग है। जब घरेलू उद्योग इन अल्कोहल के मिश्रित रूप की बिक्री की है, तो विशुद्ध रूप को बाहर नहीं किया जा सकता, अतः इसे बाहर करने से शुल्क का असल प्रयोजन ही समाप्त हो जाएगा.....।”

प्राधिकारी के उपरोक्त जांच परिणामों की माननीय सेस्टेट, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 06.01.2023 के अंतिम आदेश सं. 50010-50013/2023 के तहत पुष्टि की गई है, जिसमें कि यह पाया गया था:-

“ 34. अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विचाराधीन उत्पाद में विशुद्ध कट सी12 और सी14 सहित दर्ज किए गए जांच परिणाम में कोई त्रुटि नहीं है।”

ग. याचिकाकर्ता ने आँन साइट सत्यापन के दौरान यह प्रदर्शित किया था कि सी1214 का कोई अतिरिक्त लागत व्यय किए बिना विशुद्ध सी12 और सी14 के मिश्रण की एक सामान्य प्रक्रिया द्वारा उत्पादन किया जा सकता है। यह नोट किया जाता है कि यह निर्णय कि क्या सी12-14 मिश्रण का सीधे या विशुद्ध सी12 और सी14 का मिश्रण करके बाजार की मांग और ग्राहक की पसंद के आधार पर निर्भर होने का निर्णय लिया गया है। यदि केवल सी1214 मिश्रण के आयातों पर शुल्क लगाया जाता है न कि विशुद्ध सी12 और सी14 पर, तो सी1214 मिश्रण की बजाय विशुद्ध कट सी12 और सी14 का आयात करके शुल्क की प्रवंचना करना संभव नहीं होगा, जिससे शुल्क लगाने का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है। तदनुसार, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विशुद्ध सी12, सी14 और उनके मिश्रण परस्पर बदले जा सकते हैं और इसीलिए उसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता।

घ. इसके अलावा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा कि विशुद्ध सी12 और सी14 को मिलाकर उत्पादित सी1214 के पास भिन्न रासायनिक विनिर्देशन है और इसीलिए, आयात किए जा रहे सी1214 को समान उत्पाद नहीं है, इसमें कोई गुण नहीं है। हितबद्ध पक्षकार ने यह अनुरोध किया है कि आयातित सी1214 का तकनीकी विनिर्देशन, जो यह दर्शाता है कि उसके पास 70-77 प्रतिशत की रेंज में विशुद्ध सी12 और 21-30 प्रतिशत के रेंज में विशुद्ध सी14 है और संचित रूप से अन्य कार्बन चेन लेंथ सी8 और कमतर, सी10 या सी16 या सी16 या अधिक के अन्य विशुद्ध कट (अधिकतम 2 प्रतिशत तक) के ट्रेस हैं। इस संबंध में, प्राधिकारी अंत में यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों का दावा अभी तक केवल यह रहा है कि सी1214 मिश्रण के निर्यात के लिए सी12 और सी14 (विशुद्ध कट) का मिश्रण तकनीकी या वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। तथापि, ऐसे दावे के समर्थन के लिए रिकार्ड पर कोई साक्ष्य नहीं रखा गया है। यह केवल इस विलंबित अवस्था में कि एक नया तर्क यह दिया जा रहा है कि सी12 और सी14 (विशुद्ध कट) का मिश्रण करके उत्पादित सी1214 का भारत में आयात किए जा रहे सी1214 की तुलना में भिन्न रासायनिक विनिर्देशन होगा। यद्यपि, सी1214 (आयात किया गया बताया गया है) का एक रासायनिक विनिर्देशन प्रदान किया गया है, लेकिन सी1214 (सी12 और सी14 का मिश्रण करके उत्पादित) के लिए ऐसा कोई विनिर्देशन प्रदान नहीं किया गया है। अतः बिना समर्थक साक्ष्य के मात्र अनुरोध किए जाने को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

ड. उपरोक्त के बावजूद, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकार का यह दावा है कि भारत में आयात किए जा रहे सी 1214 में अन्य कार्बन चेन लेंथ के एसएफए का ट्रेस है, जो विशुद्ध सी 12 और सी 14 के मिश्रण से तैयार किए गए सी 1214 में नहीं होगा। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जैसा कि अधिकांश रिफाइनरी उत्पादों में होता है, किसी विशुद्ध ग्रेड में कतिपय अवशिष्ट घटक मौजूद होंगे। जांच में यह दर्शाया गया है कि यहां तक कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित विशुद्ध ग्रेड, जैसे सी 1698 अथवा सी 1898 में अन्य कार्बन चेन लेंथ के एसएफए के 2% तक ट्रेस मौजूद हैं और इसीलिए यह घरेलू उद्योग द्वारा स्वीकृत था, जो कि सी 1698 अर्थात् सी 16 - 98% विशुद्ध के साथ था। यह नोट किया जाता है कि विभिन्न कार्बन चेन लेंथ के एसएफए के इन ट्रेस की मौजूदगी का उत्पाद की गुणवत्ता पर

कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। इसके साथ ही, यह नोट किया जाता है कि यहां तक विशुद्ध सी 12 और विशुद्ध सी 14 के मिश्रण से उत्पादित किए गए सी 1214 में इस विशुद्ध ग्रेड में अन्य कार्बन चेन लेंथ के ट्रेस मौजूद होंगे।

च. इसके अलावा, इस दावे के संबंध में कि याचिकाकर्ता सी 1214 एल्कोहल का केवल टोल विनिर्माण करता है जिसमें वह सी 1214 फैटी एसिड का आयात करता है और उसके बाद केवल सी 1214 फैटी एसिड को सी 1214 एल्कोहल में बदलता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त तर्क वास्तव में गलत है। याचिकाकर्ता ने मूल कच्ची सामग्री अर्थात् पॉम करनेल ऑयल स्रोत से सी 1214 के विनिर्माण का साक्ष्य दिया है। किसी भी तरह याचिकाकर्ता ने सी 1214 का भारी मात्रा में उत्पादन और बिक्री की है, इसलिए उसे बाहर रखने की जरूरत नहीं है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति

घ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

8. जांच की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क) भारत में संबद्ध वस्तु के केवल दो उत्पादक अर्थात् वीवीएफ (इंडिया) लिमिटेड (यहां याचिकाकर्ता) और गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड (“गोदरेज”) हैं।
- ख) याचिकाकर्ता के पास कुल भारतीय उत्पादन का 65 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है और इसलिए सीवीडी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार “घरेलू उद्योग” के रूप में वर्तमान याचिकाकर्ता भारत में पीयूसी के समस्त पात्र घरेलू उत्पादन का प्रतिनिधि होगा और उसके पास घरेलू उद्योग की स्थिति है।
- ग) इस मामले में, गोदरेज ने पिछले कुछ वर्षों से संबद्ध देशों से पीयूसी का आयात किया है। इस प्रकार, नियम 2(ख) के अनुसार उसे घरेलू उद्योग के रूप में याचिकाकर्ता की स्थिति के निर्धारण से बाहर रखना चाहिए। गोदरेज को बाहर रखने पर वर्तमान याचिकाकर्ता भारत में पीयूसी के समस्त पात्र घरेलू उत्पादन का प्रतिनिधि होगा और उसके पास घरेलू उद्योग की स्थिति है।
- घ) याचिकाकर्ता ने न तो संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वह संबद्ध वस्तु के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

9. “घरेलू उद्योग” के रूप में याचिकाकर्ता की स्थिति पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा आपत्ति नहीं की गई है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

10. नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

“घरेलू उद्योग से तात्पर्य समग्र रूप से समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों से है या ऐसे घरेलू उत्पादक जिनका उक्त वस्तु का संयुक्त उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता हो, ऐसी स्थिति को छोड़कर, जबकि ऐसे उत्पादक कथित समिक्षीय प्राप्त वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों या स्वयं उसके आयातक हों, ऐसे मामलों में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जाएगा।”

11. यह याचिका मैसर्स वीवीएफ इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर की गई है। भारत में संबद्ध वस्तु के दो उत्पादक अर्थात् मैसर्स वीवीएफ इंडिया लिमिटेड और मैसर्स गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि गोदरेज ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का महत्वपूर्ण मात्रा में आयात किया है और इस प्रकार वह घरेलू उद्योग होने का पात्र नहीं है। अतः एकमात्र पात्र घरेलू उत्पादक होने के नाते वीवीएफ इंडिया लिमिटेड के पास घरेलू उद्योग की स्थिति है। किसी भी तरह, याचिकाकर्ता के पास कुल भारतीय उत्पादन में लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा है। अतः, गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा संबद्ध वस्तु के उत्पादन को शामिल करने के बाद भी याचिकाकर्ता मै. वीवीएफ इंडिया लिमिटेड के पास भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है और इसलिए इस जांच के प्रयोजनार्थ वह स्थिति संबंधी अपेक्षा को पूरा करता है और नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के अनुसार घरेलू उद्योग है।

ड. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे

ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

12. गोपनीयता संबंधी मुद्दों के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क) संबद्ध देशों के निर्यातकों और सरकारों द्वारा अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है।
- ख) उत्पादकों/निर्यातकों और सरकारों ने प्रश्नावली प्रस्तुत करते समय प्राधिकारी द्वारा जारी अनुदेशों का पालन नहीं किया है।
- ग) निर्यातकों ने सूचीबद्ध रूप में भी संगत आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं।
- घ) केवल इसलिए कि घरेलू उद्योग को उस पद्धति की जानकारी नहीं है, जिसमें ये स्कीमें प्रचालित होती हैं, पात्रता मापदंड, आवेदन प्रक्रिया आदि होते हैं, का यह अर्थ नहीं है कि उनके गोपनीय होने का दावा किया जा सकता है।

उ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

13. गोपनीयता संबंधी मुद्दों के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क) याचिका का अगोपनीय अंश सीवीडी नियमावली के नियम 7 और 8 और डीजीटीआर द्वारा जारी व्यापार सूचना सं. 1/2013 दिनांक 09 दिसंबर, 2013 में निर्धारित अपेक्षाओं और मानकों का उल्लंघन करती है।
- ख) यह याचिका व्यापार सूचना सं. 10/2018 दिनांक 7 सितंबर, 2018 का अनुपालन नहीं करती है, जो घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर उत्तरों के गोपनीय अंश/अगोपनीय अंश में सूचना के प्रकटन के लिए जांच प्रक्रिया को सुचारू बनाने के महेनजर मानक निर्धारित करती है।
- ग) याचिकाकर्ता ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और अधूरी याचिका प्रस्तुत की है।
- घ) याचिकाकर्ता बिक्री मात्रा और मूल्य, आबद्ध खपत और लागत निर्धारण आंकड़ों के रुझान के अनुसार हुई क्षति के दावों को सत्य सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है।
- ड.) याचिकाकर्ता ने अगोपनीय सारांश में न्यूनतम सूचना प्रस्तुत नहीं की है या कीमत कठौती और स्टॉक के लिए संकेतक रूप में सूचना नहीं दी है ताकि उचित बचाव के लिए एक सार्थक समझ बन सके।
- च) याचिकाकर्ता द्वारा उसके आवेदन में प्रदत्त सूचना से सब्सिडी मार्जिन की मात्रा और स्थानीय उद्योग को हुई क्षति की तर्कसंगत समझ नहीं बनती है।
- छ) याचिका में आवश्यक सूचना नहीं है और इसलिए वर्तमान जांच की शुरुआत वैध नहीं है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

14. सूचना की गोपनीयता के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली के नियम 8 में निम्नलिखित प्रावधान है :

“गोपनीय सूचना। (1) नियम 7 के, उपनियम (1), (2), (3) और (7), नियम 14 का उप नियम (2), नियम 17 का उपनियम (4) और नियम 19 का उपनियम (3) में निहित किन्हीं तथ्यों के बावजूद, नियम 6 के उप नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों अथवा जांच की प्रक्रिया में किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई कोई अन्य सूचना की प्रतियों को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इसकी गोपनीयता के संबंध में संतुष्ट होने पर इसके द्वारा ऐसा माना जायेगा और इस प्रकार की किसी सूचना को ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार के विशिष्ट अधिकरण के बिना किसी अन्य पक्षकार को प्रकट नहीं किया जायेगा।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को यह कह सकते हैं कि वे गोपनीय सूचना के तथ्य को उचित तरीके से समझने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त विवरण में उसका अगोपनीय सार प्रस्तुत करें और यदि ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार की राय में, इस प्रकार की सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता है तब ऐसे पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को उन कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि क्यों संक्षेपण संभव नहीं है।

(3) उपनियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा इस सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने के

लिए या तो इच्छुक नहीं है अथवा सामान्य या सारांश रूप में इसके प्रकटन का अधिकार देने के लिए इच्छुक नहीं है, तब यह इस प्रकार की सूचना की उपेक्षा कर सकता है।”

15. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ईमेल कर दें क्योंकि चल रही कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं थी।
16. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की संगत समझी गई सीमा तक प्राधिकारी द्वारा जांच और तदनुसार समाधान किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्यासिता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों से गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना का पर्यास अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने व्यापार से संबंधित अपनी संवेदनशील सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है।

17. गणना की प्रणाली

गणना की प्रणाली एएससीएम के अनुच्छेद 14 के तहत अनुबंध 1 के पैरा 1 के अनुसरण में प्राप्तकर्ता को प्रदान किए गए लाभ की गणना करने के लिए दिशा-निर्देशन और प्रणाली प्रदान की गई है और यह भी प्रदान किया गया है कि जांच प्राधिकारी द्वारा प्राप्तकर्ता के लाभ की गणना करने के लिए प्रयोग की गई कोई भी प्रणाली पारदर्शी होगी और पर्यास रूप से स्पष्ट की जाएगी। इसके अलावा, प्राप्तकर्ता के लाभ की गणना करने के लिए जांच प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की गई कोई भी प्रणाली संबंधित सदस्य के राष्ट्रीय कानून अथवा कार्यान्वयन विनियमों में प्रदान की जाएगी और प्रत्येक मामला विशेष के लिए इसका प्रयोग पारदर्शी होगा और पर्यास रूप से स्पष्ट किया जाएगा। इस अपेक्षा के अनुसार (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं पर प्रवर्चना शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा अधिकारी की निर्धारण) नियमावली, 1995 में सब्सिडी की मात्रा के निर्धारण की प्रणाली दी गई है। इस जांच में निर्धारण इन दिशा-निर्देशों के अनुसार है।

च. सब्सिडी और सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण

18. घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका में वर्तमान जांच की शुरुआत के लिए संबद्ध देशों में प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडियों की मौजूदगी के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड की सरकार को स्थिति स्पष्ट करने और सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी करार के अनुच्छेद 13 के अनुसार परस्पर सहमत समाधान तक पहुंचने के उद्देश्य से विचार-विमर्श हेतु आमंत्रित किया गया था। यह विचार-विमर्श थाइलैंड सरकार के साथ 21.01.2022 को हुए थे और इंडोनेशिया सरकार तथा मलेशिया सरकार के साथ 28.01.2022 को हुए थे। इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड से उत्पादकों और निर्यातकों को प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी और कथित सब्सिडी कार्यक्रम की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव के संबंध में सत्यापन योग्य साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्यास अवसर दिया गया था ताकि ऐसी सब्सिडियां, यदि कोई हों, की मौजूदगी और राशि का उचित निर्धारण हो सके। यथासंगत अतिरिक्त सूचना हितबद्ध पक्षकारों से मांगी गई थी। संबद्ध देशों की सरकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन 07.09.2022 को किया गया था।

19. इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड की सरकारों के अलावा, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है।

- i. पीटी. विलमार नबाटि, इंडोनेशिया
 - नैचुरल ओलियोकेमिकल्स एसडीएन बीएचडी, मलेशिया
 - विलमर ट्रेडिंग पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर
- ii. पीटी. मुजिम मास, इंडोनेशिया
 - इंटर-कॉन्टीनेटल ऑयल्स एंड फैट्स पीटीई लिमि. सिंगापुर
- iii. पीटी. इकोग्रीन ओलियोकेमिकल्स, इंडोनेशिया
 - इकोग्रीन ओलियोकेमिकल्स (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड
- iv. पीटी. एनर्जी सेजाहटेरा मास, इंडोनेशिया

सिनारमास सेपसा पीटीई. लिमिटेड. सिंगापुर

- v. केएल-केपेंग ओलियोमास एसडीएन बीएचडी
- vi. ऐमरी ओलियोकेमिकल्स (एम) एसडीएन. बीएचडी.
- ऐमरी ओलियोकेमिकल्स रिका (एम) एसडीएन बीएचडी निर्यातक प्रश्नावली
- vii. एफपीजी ओलियोकेमिकल्स एसडीएन बीएचडी
- प्रोक्टर एंड गैम्बल इंटरनेशनल ऑपरेशंस एसए सिंगापुर
- viii. थार्ड फैटी एल्कोहल्स कंपनी लिमिटेड
- ग्लोबल ग्रीन केमिकल्स पब्लिक कं. लिमिटेड, थाइलैंड
- ix. यूनिलीवर एशिया प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर

कथित सब्सिडी कार्यक्रमों का सामान्य विहंगावलोकन

च.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

20. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. निर्यातकों ने इन आधारों पर सभी स्कीमों के संबंध में “लागू नहीं” बताया है कि कंपनी विशिष्ट कार्यक्रमों का लाभ नहीं लेती है। तथापि, जब कोई कंपनी किसी कार्यक्रम की पात्र होती है तो यह मानने का कोई कारण नहीं है कि वह उस कार्यक्रम का लाभ नहीं लेगी। इस प्रकार, या तो कंपनी को पात्रता का अभाव दर्शाना चाहिए या यह दर्शाना चाहिए कि उसने कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध लाभ क्यों नहीं लिया है।
- ii. पर्याप्त से कम कीमत (एलटीएआर) पर कच्ची सामग्री के प्रावधान द्वारा दी गई सब्सिडी के संदर्भ में संबद्ध देशों तथा निर्यातकों ने केवल यह तर्क दिया है कि निर्यात शुल्क लगाना डब्ल्यूटीओ के अनुपालन में है और इसलिए सब्सिडी नहीं है। हितबद्ध पक्षकार यह बताने में विफल हैं कि याचिकार्ता का आरोप यह नहीं है कि कच्ची सामग्री पर लागू निर्यात शुल्क एक सब्सिडी है बल्कि यह है कि “कच्ची सामग्री” जैसे सीपीकेओ का विश्व बाजार कीमत से कम पर मिलना एक सब्सिडी है। इंडोनेशिया और मलेशिया सरकार द्वारा निर्यात शुल्क लगाने का उद्देश्य स्वीकृत रूप से विश्व बाजार कीमतों से कम पर अपने घरेलू उत्पादकों को कच्ची सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, उक्त सरकारें सीधे बाजार में भागीदारी करती हैं और कच्ची सामग्री की कीमत निर्धारित करती हैं। इस प्रकार, संबद्ध सरकारों ने कच्ची सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं को एलटीएआर पर स्थानीय विनिर्माताओं को कच्ची सामग्री उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा है या ऐसा निदेश दिया है।
- iii. आयात शुल्कों और करों से छूट प्रदान करने की स्कीम के संबंध में संबद्ध देश की सरकारों और उनके निर्यातकों ने केवल यह दलील दी है कि उक्त छूट निर्यातों के लिए वस्तुओं के विनिर्माण हेतु था और इसलिए एससीएम करार के अनुच्छेद 1 के फटनोट 1 के अनुसार प्रतिसंतुलन योग्य नहीं है। तथापि, हितबद्ध पक्षकार इस बात का कोई साक्ष्य उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं कि एक सत्यापन तंत्र है जो यह सुनिश्चित करता है कि यह छूट निर्यात के लिए वस्तुओं के उत्पादन हेतु आवश्यकता से अधिक है। रिकॉर्ड में ऐसे साक्ष्य के अभाव में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ली गई समूची छूट प्रतिसंतुलन योग्य है।
- iv. एलटीएआर पर कच्ची सामग्री के प्रावधान से इतर याचिका में कथित अधिकांश स्कीमें पूर्ववर्ती जांचों में प्राथिकारी द्वारा प्रतिसंतुलित की गई हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शाने के लिए रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य नहीं रखा है कि उक्त स्कीमों में कोई बदलाव हुआ है। इस प्रकार, इसके विपरीत किसी साक्ष्य के अभाव में ऐसी स्कीमों के तहत प्राप्त लाभ प्रतिसंतुलित किया जाना चाहिए।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

21. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. एससीएम करार के अनुच्छेद 11.3 में जांचकर्ता प्राथिकारी के लिए यह निर्धारित करने हेतु किसी याचिका में प्रदत्त साक्ष्य की सटीकता और पर्याप्तता की समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या वह जांच की शुरुआत को उचित

ठहराने के लिए “पर्यास” है। याचिकाकर्ता ऐसा “पर्यास साक्ष्य” उपलब्ध कराने में विफल रहा है। अतः, वर्तमान जांच शुरूआत एसीएम करार के अनुपालन में नहीं है।

- ii. एलटीएआर पर प्राथमिक कद्दी सामग्री (सीपीकेओ) के प्रावधान से संबंधित स्कीम के बारे में याचिकाकर्ता ने यह सिद्ध नहीं किया है कि कौन सा वित्तीय अंशदान किया गया है; कौन सा सार्वजनिक या सरकारी निकाय है जो उक्त कार्यक्रम का प्रशासन कर रहा है; और वो कानूनी या अधिकारिक दस्तावेज कौन से हैं जिनके तहत उक्त कार्यक्रम बनाया गया है।
- iii. संबद्ध देशों ने केवल सीपीकेओ के निर्यात पर शुल्क और कर लागू करने का अपना प्रभुमत्ता का कार्य किया है। निर्यात कर लगाना या किसी अन्य प्रकार का शुल्क लगाना या निर्यात पर प्रभार गैट, 1995 के अंतर्गत प्रत्येक डब्ल्यूटीओ सदस्य के लिए प्रयोग योग्य विधिसंम्मत साधन है।
- iv. ऐसा कोई कार्य या निदेश नहीं है जो संबंधित सरकारों द्वारा “वित्तीय अंशदान” के निष्कर्ष को आवश्यक बताता हो। इस संबंध में निर्यातकों ने अन्य बातों के साथ-साथ, **अमेरिका - निर्यात बाधाओं को सब्सिडी मानने संबंधी उपायों (यूएस निर्यात बाधा उपाय)** में डब्ल्यूटीओ पैनल के निर्णय पर यह अनुरोध करने हेतु भरोसा किया है कि केवल किसी निर्यात बाधा उपाय को लागू करने के परिणामस्वरूप या किसी वस्तु की घरेलू आपूर्ति में वृद्धि प्रभावित होने पर यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता है कि सरकार ने किसी निजी निकाय को घरेलू बाजार में सब्सिडी प्राप्त कीमत पर ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति करने का ‘कार्य सौंपा है’ या ‘निदेश’ दिया है।
- v. निर्यातकों द्वारा यह भी दावा किया गया है कि यदि प्राधिकारी निर्यात बाधाओं को लागू करना सब्सिडी मानते हैं तो स्थानीय उत्पादकों को लाभ की गणना निर्यात कर और/या लेवी को हटाने के बाद कद्दी सामग्री की एफओबी निर्यात कीमत होगी।

22. प्रत्येक सब्सिडी स्कीम के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के उत्तर का सारांश नीचे दिया गया है और संबंधित शीर्षों के अंतर्गत उसकी जांच की गई है।

च.3 याचिकाकर्ता द्वारा आरोपित सब्सिडी कार्यक्रमों की जांच

इंडोनेशिया

23. प्राधिकारी ने इंडोनेशिया सरकार द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित कार्यक्रमों की जांच की है:

- i. कार्यक्रम सं. 1 -पर्यास से कम मूल्य (“एलटीएआर”) पर कद्दी सामग्री का प्रावधान।
- ii. कार्यक्रम सं. 2 -एनटीएआर पर कोयले और बिजली का प्रावधान।
- iii. कार्यक्रम सं. 3 -अग्रणी उद्योग का दर्जा।
- iv. कार्यक्रम सं. 4 -विशेष आर्थिक जोन से संबंधित स्कीम।
- v. कार्यक्रम सं. 5 -इंडोनेशिया एक्जिम बैंक और एसुरांसीएसई द्वारा अधिमानी शर्तों पर निर्यात वित्त पोषण और गारंटी।
- vi. कार्यक्रम सं. 6(क) -बॉडेड जोन
- vii. कार्यक्रम सं. 6(घ) और (ड.) -आयात शुल्क छूट और ड्राबैक (केआईटीई)
- viii. कार्यक्रम सं. 7 - मुक्त व्यापार जोन
- ix. कार्यक्रम सं. 8 - सूचीबद्ध निवेशों के लिए आय कर लाभ।
- x. कार्यक्रम सं. 9 - कोविड-19 राहत पैकेज।
- xi. कार्यक्रम सं. 10 - एलटीएआर पर प्राकृति गैस का प्रावधान।
- xii. कार्यक्रम सं. 11 - अधिमानी ऋण दरें

(i) **कार्यक्रम 1: पर्यास से कम मूल्य (“एलटीएआर”) पर कद्दी सामग्री का प्रावधान**

क. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध

24. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि क्रूड पॉम करनेल ऑयल (जिसमें उसकी व्युत्पत्तियां जैसे परिष्कृत ब्लीच्ड डियोडोराइज्ड पॉम करनेल ऑयल (आरबीडीपीकेओ), स्पिलट सीपीकेओ आदि, शामिल हैं जिन्हें आगे संयुक्त रूप से "सीपीकेओ" कहा गया है), संबद्ध वस्तु के विनिर्माण में प्रयुक्त एक प्राथमिक सामग्री है और उत्पादन की कुल लागत में उसका हिस्सा 70 प्रतिशत से अधिक है। वह स्थानीय कीमत जिस पर सीपीकेओ इंडोनेशिया में उपलब्ध होता है, विकृत है क्योंकि बाजार में इंडोनेशिया सरकार ("जीओआई") द्वारा सीधे हस्तक्षेप किया जाता है। विशेष रूप से याचिकाकर्ता ने पाया है कि जीओआई ने सीपीकेओ पर उच्च निर्यात कर और लेवी लगाने की नीति यह सुनिश्चित करने के लिए लागू की है कि इंडोनेशियाई घरेलू उत्पादकों को बाजार कीमत से कम पर कड़ी सामग्री उपलब्ध हो। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि इंडोनेशिया सरकार एलटीएआर पर प्रमुख कड़ी सामग्री की व्यवस्था के माध्यम से "विनीय अंशदान" के रूप में सब्सिडी प्रदान करती है। वैकल्पिक रूप से याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि एलटीएआर पर कड़ी सामग्री का प्रावधान "कीमत या आय सहायता" के दायरे में भी आता है क्योंकि निर्यात बाधा लागू करने का मूल प्रयोजन एलटीएआर पर कड़ी सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करना है और इसलिए यह सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 के अन्तर्गत यथा-परिभाषित एक सब्सिडी है।

25. मलेशिया के साथ इंडोनेशिया सीपीकेओ का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है जो सीपीकेओ की वैश्विक मांग के 90 प्रतिशत से अधिक की पूर्ति करता है। अकेले इंडोनेशिया का विश्व सीपीकेओ उत्पादन में 65 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है और इसलिए उसकी नीतियों का सीपीकेओ की वैश्विक बाजार कीमत पर बड़ा प्रभाव पड़ता है।

26. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि जीओआई ने सीपीकेओ और उसके व्युत्पत्तियों के निर्यातों पर निर्यात कर और निर्यात लेवी लगाई है ताकि विश्व बाजार कीमत से कम पर घरेलू डाउनस्ट्रीम उत्पादकों (जैसे एसएफए उत्पादकों) को उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो। यह तर्क दिया गया है कि निर्यात कर और लेवी में दिसंबर, 2020 के बाद से भारी वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, कड़ी सामग्री की वैश्विक कीमत में भी भारी वृद्धि हुई है। तथापि, इंडोनेशिया में कड़ी सामग्री की स्थानीय कीमत वैश्विक कीमतों से काफी कम रही है।

27. याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि जीओआई एक पूर्ण स्वामित्व वाले निकाय पीटी परकेबुनान नुसानतारा ("पीटीपीएन"), जो सीपीओ/सीपीकेओ का एक उत्पादक है, के ज़रिए बाजार में सीधे भागीदारी करता है और इंडोनेशिया में सीपीकेओ और उसकी व्युत्पत्तियों की बिक्री और खरीद के लिए कीमत निर्धारक के रूप में कार्य करता है। पीटीपीएन सीड स्टॉक की घरेलू कीमतें निर्धारित करता है और इंडोनेशिया में सीपीकेओ की सभी स्थानीय बिक्रियां पीटीपीएन द्वारा निर्धारित कीमतों या उससे कम कीमत पर अनन्य रूप से होती हैं, जो विश्व बाजार कीमत से काफी कम हैं। अतः, यह अनुरोध किया गया है कि इंडोनेशिया में कड़ी सामग्री की लागत काफी अधिक सब्सिडी प्राप्त है। याचिकाकर्ता ने अपने आरोपों के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजों पर भरोसा किया है:

- संशोधन विनियम सं. 128/पीएमके.011/2011
- प्रैसिडेंशियल विनियम सं.61/2015
- इंडोनेशिया की डब्ल्यूटीओ व्यापार नीति समीक्षा 2020

ख. इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

28. जीओआई ने अनुरोध किया है कि निर्यात कर/लेवी लगाना सरकार का शासन कार्य है। इसके अलावा, निर्यात करों में वृद्धि के परिणामस्वरूप इंडोनेशिया में सीपीकेओ की अति-आपूर्ति का कोई साक्ष्य नहीं है क्योंकि वह घरेलू और निर्यात बाजार में पूर्णतः खप जाती है।

29. सीपीकेओ पर निर्यात कर और लेवी लगाना स्थानीय उद्योगों के लिए सीपीकेओ की उपलब्धता सुनिश्चित करके इंडोनेशिया के जनहित को सुरक्षित करना है और इसका इंडोनेशिया में सीपीकेओ की कीमत नीति से कोई लेना-देना नहीं है।

30. सीपीकेओ के निर्यात के लिए इंडोनेशिया द्वारा लागू निर्यात कर और लेवी कोई विनीय अंशदान नहीं देता है और न ही सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी डब्ल्यूटीओ करार (एससीएम करार/एएससीएम) के अर्थ के भीतर यह कोई सरकारी प्रदत्त निधि है।

31. पीटीपीएन के लिए इंडोनेशिया में सीपीकेओ की कीमत नियंत्रित करना असंभव है क्योंकि उसके पास इंडोनेशिया में सीपीकेओ के कुल उत्पादन का केवल 3 प्रतिशत है। इसके अलावा, इंडोनेशिया में सीपीकेओ को उचित और पारदर्शी नीलामी के आधार पर बेचा जाता है और यह कि शेष सीपीकेओ उत्पादक अर्थात् सीपीकेओ के कुल उत्पादन का 97

प्रतिशत उत्पादन लागत और उनके बीच प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए, अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर इसकी कीमत निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

32. उनके अनुसार, इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि पीटीपीएन कच्ची सामग्री की कीमत तय करता है। पीटीपीएन की निविदा कीमत विभिन्न कारकों पर विचार करते हुए तय की जाती है। पीटीपीएन उच्चतम बोलीदाता बिक्री करता है और पीटीपीएन को सार्वजनिक निविदा से प्राप्त कीमतें न केवल उस कीमत पर निर्भर करती हैं, जिस पर पीटीपीएन बिक्री करना चाहेगा बल्कि उस कीमत पर भी निर्भर करती हैं, जो खरीदार देना चाहता है।
33. निर्यातकों ने यह भी दावा किया है कि यदि लाभ की गणना की भी जाती है तो उसे ऐसे आयातों पर लागू निर्यात शुल्क और लेवी को अलग करने के बाद सीपीकेओ की निर्यात कीमत पर विचार करते हुए किया जाना चाहिए।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीपीकेओ भारत को निर्यात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रयुक्त प्राथमिक कच्ची सामग्री है। याचिकार्ता द्वारा यह दावा किया गया है कि सीपीकेओ की कीमत सरकारी हस्तक्षेप के कारण इंडोनेशिया में विकृत है। विशेष रूप से याचिकार्ता ने यह दावा किया गया है कि कच्ची सामग्री की कीमत की विकृति निर्यात करने को लगाने और सीपीकेओ और उसके डेरिवेटिव के निर्यातों पर निर्यात उपकर लगाए जाने के प्रत्यक्ष परिणाम से है। यह दावा किया गया है कि सीपीकेओ पर उच्च निर्यात करने और उपकरों को लगाकर, भारत सरकार के पास इंडोनेशिया में घरेलू सीपीकेओ कीमत पर एक निराशाजनक प्रभाव है, जिसमें संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया है, जो सीपीकेओ को उनकी प्राथमिक कच्ची सामग्री के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा, यह अनुरोध किया गया है कि सीपीकेओ के निर्यातों पर करों को लगाकर भारत सरकार निजी सीपीकेओ उत्पादकों को अपने उत्पाद इंडोनेशियाई फैटी अल्कोहल के उत्पादकों के वैश्विक बाजार कीमत से कम कीमत पर बेचने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा, याचिकार्ता ने यह आरोप लगाया है कि भारत सरकार एक राज्य निकाय, पीटीपीएन के माध्यम से बाजार में सीधे हस्तक्षेप करती है, जो सीपीकेओ की घरेलू बाजार कीमत का निर्धारण करता है। इसके परिणामस्वरूप याचिकार्ता ने यह आरोप लगाया है कि भारत सरकार पर्याप्त पारिश्रामिक से कम पर ऐसएफए उत्पादकों को सीपीकेओ प्रदान करने के लिए इंडोनेशियाई पाम ऑयल उत्पादों को सौंपती है या निर्देश देती है।
35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल सीपीकेओ में ही संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत की करीब 70 प्रतिशत लागत शामिल है। इंडोनेशिया और मलेशिया मिलकर सीपीकेओ की करीब 90 प्रतिशत वैश्विक मांग को पूरा करते हैं, जिसमें इंडोनेशिया के पास बड़ा हिस्सा शामिल है। अतः ये देश कच्ची सामग्री के लगभग विशिष्ट आपूर्तिकर्ता हैं, जिनका सीपीकेओ और उसके डेरिवेटिव की वैश्विक बाजार कीमत पर एकाधिकार रहता है।
36. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि भारत सरकार ने पाम ऑयल, पाम कर्नेल ऑयल और उनके डेरिवेटिव पर निर्यात कर लगाने के लिए एक प्रणाली बढ़ा और संरचनात्मक निर्यात टैरिफ प्रणाली कार्यान्वित की है। इन उत्पादों पर निर्यात कर पहले 1994 में लगाया गया था। इसके उत्पादन से लेकर अब तक इसमें अनेक बार संशोधित किया गया है और उसके बाद वर्ष 2011 में पर्याप्त रूप से पुनःसंरचित किया गया था। इस नई कर संस्था में कच्चे और रिफाइंड तेल के बीच काफी बड़ा शुल्क का अंतर प्रदान किया गया है ताकि अधिक रिफाइन और मूल्यवर्धन ऑनशोर को प्रोत्साहित किया जा सके। विधान में विशेष से यह कहा गया है कि 'मूल्यवर्धित डाउनस्ट्रीम में वृद्धि करने के लिए पाम ऑयल उद्योग के डाउनस्ट्रीम प्रचालनों में समर्थन के प्रसंग में, यह आवश्यक है कि निर्यात शुल्क को पुनःसंरचित किया जाए।'
37. जांच की अवधि के दौरान सीपीकेओ पर निर्यात कर को डिक्री सं. 166/पीएमके.010/2020 द्वारा विनिर्मित किया गया था, जिससे विनियमन पीएमके सं. 13/पीएमके.010/2017 को संशोधित किया गया है। यह नोट किया जाता है कि उपरोक्त निर्यात कर के अतिरिक्त, सीपीकेओ और उसके डेरिवेटिव का निर्यात भी पीएमके 76/पीएमके.05/2021 द्वारा यथा संशोधित विनियमन पीएमके 57/पीएमके.05/2020 के तहत निर्यात उप कर लगाए जाने के अध्यधीन हैं। संशोधित विनियमन के तहत सीपीकेओ का निर्यात यूएसडी 55 – यूएसडी 175 प्रति टन की रेंज में निर्यात उपकर के अध्यधीन है, जोकि सीपीकेओ की संदर्भ निर्यात कीमत के आधार पर है। भारत सरकार द्वारा दाखिल किए गए प्रश्नावली उत्तर के अनुसार, सीपीकेओ की संदर्भ निर्यात कीमत एक भारित कीमत है, जो (i) सीआईएफ रोटरडम के लिए औसत सीपीकेओ कीमत, (ii) मलेशियाई बरसा की औसत सीपीकेओ कीमत, (iii) इंडोनेशियाई बरसा की औसत सीपीकेओ कीमत के आधार पर परिकलित की गई है, जिसमें प्रत्येक का क्रमशः 20 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 60 प्रतिशत भार शामिल है। इस प्रकार निर्धारित संदर्भ कीमत के अनुसार माह के लिए लागू निर्यात कर और उपकर निर्धारित किया गया है। जैसा कि अनुच्छेद 5(1) पीएमके सं. 13/पीएमके.010/2017 में प्रदान किया गया है, जिसके बारह कॉलम का निर्धारण, टैरिफ अनुसूची में

किया गया है जो शामिल उत्पाद की संदर्भ निर्यात कीमत पर निर्भर करता है। भारत सरकार द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि निर्यात कर प्रगतिशील प्रकृति के होते हैं, अर्थात् उच्चतर निर्यात कीमत की उच्चतर टैरिफ़ दर होती है।

38. उपरोक्त, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत सरकार ने निर्यात कर और उपकर को सूपष्ट रूप से “संदर्भ कीमत” से लिंक किया है, जो सीपीकेओ की अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर आधारित है। ये निर्यात कर और उपकर किसी अन्य सरोकार से संबद्ध नहीं हैं, जैसे लोक हित, उत्पादन स्तर या पर्यावरणीय प्रभाव।

39. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि इंडोनेशियाई निर्यात कर व्यवस्था में वर्ष 2011 से कई बदलाव किए गए हैं, तथापि, निर्यात करों को लगाने का प्रयोजन और उद्देश्य घरेलू रूप से तैयार उत्पादों के डाउनस्ट्रीम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उसे जारी रखा गया है। इस प्रसंग में, यह नोट किया जाता है कि इंडोनेशिया की डब्ल्यूटीओ व्यापार नीति समीक्षा, 2020 में भी यह निष्कर्ष दिया गया था कि इंडोनेशियाई सरकार द्वारा निर्यात करों (निर्यात उपकर सहित) को लगाने का प्रयोजन वैश्विक बाजार कीमतों से कम कीमत पर मध्यवर्ती इनपुट की घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास को संपोषित करना है। इस प्रकार, सूपष्ट रूप से, भारत सरकार द्वारा निर्यात करों को लगाने के पीछे प्रयोजन और उद्देश्य इसके घरेलू उद्योगों का कच्ची सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है।

40. यह भी नोट किया जाता है कि भारत सरकार निर्यात करों को लगाने के अलावा, इंडोनेशियाई बाजार में कच्ची सामग्री की बिक्री और खरीद में सीधे तौर पर भागीदार भी है। राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी पीटीपीएन, अपनी विपणन शाखा, “केपीबीएन” के माध्यम से “कीमत विचार” पर इसके सीपीकेओ की बिक्री के लिए खुली नीलामी करती है। निविदा कीमत या पीटीपीएन द्वारा निर्धारित कीमत विचार एक सार्वजनिक कीमत है, जिसकी सभी बाजार ऑपरेटरों को जानकारी है। यह पाया गया था कि निजी कंपनियों के बीच अनुबंध में भी पीटीपीएन द्वारा निर्धारित “कीमत विचार” का प्रयोग किया गया है। जांच में यह भी पाया गया है कि यहां तक कि संगत पक्षकारों के बीच अनुबंध भी व्यापक रूप से पीटीपीएन द्वारा निर्धारित कीमत पर है। यह पाया गया है कि प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा सीपीकेओ आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई कीमत कमतर थी या पीटीपीएन कीमत के समान रेंज में थी। अतः यह पाया गया है कि इंडोनेशिया में सीपीकेओ और इसके डेरिवेटिव की बिक्री और खरीद संबंधी लेन देन पीटीपीएन द्वारा निर्धारित “कीमत विचार” पर या उसके समीप किए गए हैं। यह भी नोट किया जाता है कि यह “कीमत विचार” सीपीकेओ की विश्व बाजार कीमत से काफी कम कीमत पर है, जैसे इंडोनेशिया से निर्यात कीमत या सीआईएफ रोटरडम कीमतें (मालभाड़ा या बीमा के लिए समायोजित)। वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने औसत सीपीकेओ सीआईएफ रोटरडम कीमतों (मालभाड़ा और बीमा के लिए समायोजित) पर सीपीकेओ की अविकृत बाजार कीमत के प्रतिनिधिक के रूप में विचार किया है और “विश्व बाजार कीमत” के रूप में नीचे उल्लेख किया गया है।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय अंशदान

41. सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपाय संबंधी करार (“एएससीएम”) के अनुच्छेद 1.1 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9(1) के स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि किसी “सब्सिडी” को तभी मौजूद माना जाता है यदि निर्यातक या उत्पादक देश या क्षेत्र में सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा “वित्तीय अंशदान” दिया जाता है या जब ऐसी सरकार “आय या कीमत सहायता” के किसी रूप को प्रदान करती है या बनाए रखती है और इस प्रकार लाभ दिया जाता है। किसी सरकारी या सार्वजनिक निकाय द्वारा वित्तीय अंशदान वहां मौजूद होता है जहां:

- सरकारी प्रक्रिया में निधियों का प्रत्यक्ष (या संभावित) हस्तांतरण शामिल होता है,
- सरकार का राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, वह नहीं लिया जाता या एकत्रित नहीं होता है,
- सामान्य अवसंरचना के अलावा, वस्तुओं या सेवाओं का प्रावधान या सरकार द्वारा वस्तुओं की खरीद, या
- सरकार किसी वित्त पोषण तंत्र को भुगतान करती है या किसी निजी निकाय को ऊपर खंड (i) से (iii) में विनिर्दिष्ट एक या उससे अधिक कार्य सौंपती है या करने का निदेश देती है।

42. सरकार या सार्वजनिक निकाय द्वारा “वित्तीय अंशदान” धारा 9 के अंतर्गत किसी “सब्सिडी” का एक अनिवार्य घटक है। तथापि कोई वित्तीय अंशदान हमेशा जरूरी नहीं कि सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अंशदान हो बल्कि यह तब भी मौजूद हो सकता है जब सरकार अप्रत्यक्ष रूप से अपने नीतिगत उपायों के ज़रिए विश्व बाजार से कम कीमत पर वस्तुओं (कच्ची सामग्री) की आपूर्ति करने के लिए निजी पक्षकारों को कार्य सौंपती है या सीधे ऐसा करती है। प्राधिकारी ने अनेक पूर्व जांचों में जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम से “कन्टीनिवस कास्ट कॉपर वायर रॉड” और चीन से “कंपिय हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पाद” के आयातों से संबंधित सब्सिडीरोधी जांच में यह माना था कि “वित्तीय अंशदान” के रूप में कोई प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडी मौजूद होगी, जहां पर कच्ची सामग्री पर

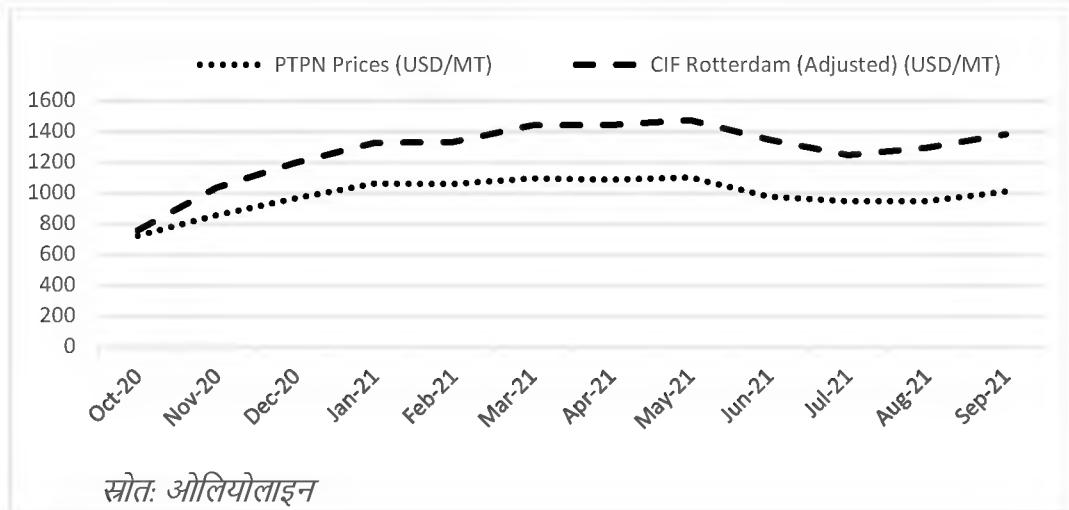
निर्यात प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य और इरादा एलटीएआर पर डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए ऐसी कड़ी सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना हो।

43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यात कर और निर्यात लेवी प्रणाली जीओआई द्वारा ऐसे डाउनस्ट्रीम उद्योगों की सहायता के लिए बनाई और तैयार की गई थी जो सीपीकेओ का प्रयोग करते हैं, जैसे कि संबद्ध वस्तु के उत्पादक। यद्यपि इन निर्यात नियंत्रणों को लगाकर जीओआई, सीपीकेओ के आपूर्तिकर्ताओं को आर्थिक रूप से एक अयुक्तिसंगत स्थिति में डाल देती है जिससे वे उस कीमत से कम कीमत पर घरेलू रूप से अपनी वस्तुओं को बेचने में प्रेरित होते हैं जिस पर इन निर्यात नियंत्रणों की अनुपस्थिति में वे बिक्री कर सकते थे। जीओआई, सीपीकेओ के आपूर्तिकर्ताओं के उनके उत्पाद को किस कीमत पर और कहां बेचने के व्यावसायिक निर्णय को वास्तव में सीमित करके उनकी कार्य करने की स्वतंत्रता को कारगर ढंग से सीमित करती है। इन उपायों के नहीं होने पर, युक्तिसंगत ढंग से कार्य करते हुए सीपीकेओ के आपूर्तिकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी दरों पर बिक्री करने और अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास किया होता।
44. इसके अलावा, चूंकि इंडोनेशिया दो प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक और सीपीकेओ का कीमत निर्धारिक है, इसलिए इन निर्यात बाधाओं से यह सुनिश्चित करने का उद्देश्य प्राप्त हुआ है कि इंडोनेशिया में जिस कीमत पर सीपीकेओ को उपलब्ध कराया गया है, वह वैश्विक बाजार कीमत से काफी कम है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जीओआई के नीतिगत उपायों के माध्यम से सीपीकेओ को एसएफए के इंडोनेशियाई उत्पादकों को पर्याप्त से कम मूल्य पर प्रदान किया जा रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडोनेशियाई एसएफए उत्पादकों द्वारा दी गई कड़ी सामग्री की कम कीमत अचानक नहीं है बल्कि जीओआई द्वारा डिजाइन किए गए उपायों का प्रत्यक्ष और लक्षित परिणाम है।
45. जीओआई तथा प्रतिवादी निर्यातकों ने भी यूएस - निर्यात बाधाओं में डब्ल्यूटीओ पैनल के निर्णय पर यह तर्क देने के लिए भरोसा किया है कि सरकार द्वारा केवल "निर्यात नियंत्रण" लागू करना सब्सिडी नहीं है क्योंकि उसमें कोई "वित्तीय अंशदान" नहीं है। इसी प्रकार, यह तर्क दिया गया है कि यदि जीओआई की निर्यात कर नीति से सीपीकेओ की घरेलू बिक्री कीमत कम होती भी है तो वह "वित्तीय अंशदान" नहीं है क्योंकि निजी सीपीकेओ आपूर्तिकर्ताओं को पर्याप्त से कम कीमत पर स्थानीय एसएफए के उत्पादकों को सीपीकेओ की आपूर्ति करने के लिए जीओआई द्वारा कोई कार्य या निदेश नहीं दिया गया है। यह अनुरोध किया गया है कि निर्यात कर लगाना सन्ता का एक संप्रभु प्रयोग है और इसलिए इसे सब्सिडी नहीं माना जा सकता है। उन्होंने अपने इस तर्क को सही सिद्ध करने के लिए विभिन्न अन्य डब्ल्यूटीओ मामला कानूनों पर भी भरोसा किया है कि निर्यात नियंत्रण प्रतिसंतुलनयोग्य सब्सिडी नहीं है।
46. उक्त तर्क के पहले चरण के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि वह निर्यात नियंत्रण लागू करने को प्रतिसंतुलनयोग्य सब्सिडी नहीं मानते हैं। तथापि, जांच से पता चला है कि निर्यात कर और निर्यात लेवी लगाना वास्तव में जीओआई द्वारा अपने घरेलू डाउनस्ट्रीम उद्योग को पर्याप्त से कम कीमत पर सीपीकेओ प्रदान करने का एक साधन या तरीका रहा है। पर्याप्त से कम कीमत पर सीपीकेओ प्रदान करने का प्रावधान जो निर्यात कर और निर्यात लेवी के व्यवस्थिति और लक्षित कार्यान्वयन के ज़रिए होता है, प्रतिसंतुलनयोग्य पाया गया है।
47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह निर्धारण कि क्या एएससीएम के अनुच्छेद 1.1(क)(1) के अंतर्गत 'वित्तीय अंशदान' सरकारी कार्यवाही के प्रभाव या परिणामों के बजाए सरकारी कार्यवाही की प्रकृति पर केन्द्रित होना चाहिए। "दूसरे शब्दों में, नियमित प्रक्रिया में घरेलू बाजार में हस्तक्षेप करने के सरकार के संप्रभु और विनियामक शक्तियों के अधिकार को" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है", चाहे ऐसे हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादकों को कोई लाभ मिला हो। इस प्रकार से, कोई सरकार राजस्व अर्जित करने के लिए कानूनी रूप से निर्यात कर लगा सकती है। इसके विपरीत, निर्यात प्रतिबंधों को लागू करना तब उचित नहीं होता है जब यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्य तंत्रों के साथ ऐसे साधन का प्रयोग प्राथमिक रूप से किसी वस्तु को घरेलू बाजार में रखना है या आपूर्तिकर्ताओं को वैश्विक बाजार कीमतों से कम पर बिक्री करने को बाध्य करना है। इस बात की जांच करना संगत है कि क्या सरकारी नीति इस प्रकार से बनाई गई है कि वह किसी उद्योग या उद्योगों के समूह विशेष की घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सहायता देने पर केन्द्रित है। इस प्रकार, इस संदर्भ, उद्देश्य और प्रयोजन सहित सरकारी की कार्यवाही की प्रवृत्ति इस बात के आकलन में संगत है कि क्या यह 'वित्तीय अंशदान' के दायरे में आएगा।
48. जैसा ऊपर नोट किया गया है, जीओआई द्वारा निर्यात कर की स्कीम और कार्यान्वयन लेवी इस प्रकार से बनाई गई है कि वह एलटीएआर पर इंडोनेशियाई डाउनस्ट्रीम उद्योगों की उपलब्धता सुनिश्चित करती है और यह एक राजस्व सुजन उपाय नहीं है। वास्तव में, 2011 में निर्यात करों के पुर्नगठन का उद्देश्य इंडोनेशिया में घरेलू प्रसंस्करण उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना ही था। डाकुटडाक्टर चू युएन मे (तक्कालीन महानिदेशक, मलेशियन पॉम ऑयल कन्ट्रोल बोर्ड, बागान उद्योग और वस्तु मंत्रालय) द्वारा 2 फरवरी, 2016¹ को दिए गए एक प्रस्तुतिकरण में

¹ <http://www.mpoec.org.my/upload/Domestic-Measures-to-Enhance-the-Competitiveness-of-the-Palm-Oil-Industry.pdf>

भी यह दर्ज है कि इंडोनेशिया द्वारा निर्यात करों का पुनर्गठन डाउनस्ट्रीम उद्योगों को सस्ती कच्ची सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने और ऐसे डाउनस्ट्रीम उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए था। इस प्रकार, प्राधिकारी पाते हैं कि जीओआई की कार्यवाही की प्रकृति, संदर्भ और उद्देश्य ऐसा है कि वह स्पष्ट रूप से 'वित्तीय अंशदान' के दायरे में आता है।

49. दिए गए तर्क के दूसरे चरण के संबंध में यह देखने की जरूरत है कि क्या उक्त कार्यवाही के माध्यम से जीओआई ने अपने एसएफए के उत्पादकों को एलटीएआर पर वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए सीपीकेओ के निजी आपूर्तिकर्ताओं को कार्य सौंपा या निदेश दिया है। इस संदर्भ में हितबद्ध पक्षकारों ने यूस - निर्यात नियंत्रण में डब्ल्यूटीओ पैनल के निर्णय पर भरोसा किया है जिसमें यह माना गया था कि एएससीएम के अनुच्छेद 1.1(क)(1)(iv) में 'कार्य सौंपने' और 'निदेश' इन दो शब्दों के साधारण अर्थ में अपेक्षित है कि सरकार की कार्यवाही में प्रत्यायोजन (कार्य सौंपने के मामले में) या आदेश (निदेश के मामले में) की धारणा शामिल होनी चाहिए। उसने यूएस 'कारण और प्रभाव तर्क' को अस्वीकार किया है और प्रत्यायोजन या आदेश की स्पष्ट और सकारात्मक कार्यवाही की मांग की है। तथापि, यह नोट किया गया है कि **कोरिया से डायनेमिक रेंडम एसेस मेमोरी सेमिकंडक्टर (डीआरएएमएस) संबंधी संयुक्त राज्य - प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच** के उत्तरवर्ती मामले में अपीली निकाय ने यूएस - निर्यात नियंत्रण में पैनल से असहमत होते हुए यह माना था कि 'कार्य सौंपने' और 'निदेश' शब्दों को 'प्रत्यायोजन' और 'आदेश' से बदलना एक मानक के रूप में काफी कठोर है। यह माना गया था कि यूएस - निर्यात नियंत्रण मामले में 'कार्य सौंपने' या 'निदेश' की पैनल की व्याख्या अनावश्यक रूप से सीमित थी।
50. अपीलीय निकाय की रिपोर्ट को पढ़कर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि "कार्य सौंपे" या "निदेशक" सिद्ध करने के लिए सरकारी द्वारा कोई सकारात्मक कार्यवाही या भूमिका होनी चाहिए। यह नोट किया गया है कि यद्यपि सामान्यतः कोई किसी निजी निकाय पर कार्य सौंपने या निदेश में किसी ढंग की या प्रेरणा के रूप को शामिल समझेगा जो बाद में ऐसे कार्य सौंपने या निदेश का साक्ष्य बन सकती है, तथापि, वर्तमान में ऐसे स्पष्ट साधनों का प्रयोग नहीं हो सकता है क्योंकि सरकारों के पास निजी निकाय पर प्राधिकार के प्रयोग के लिए अन्य साधन मौजूद होते हैं जिसमें से कुछ किसी आदेश की तुलना में "अधिक युक्तिसंगत" हो सकते हैं या उनमें समान स्तर की बाध्यता हो सकती है। ऐसे मामलों में कार्य सौंपना या निदेश परिवीक्षा और बाध्यकारी परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा सिद्ध हो सकता है। तथापि, सरकारी कार्यवाही और निजी निकाय के आचरण के बीच 'एक स्पष्ट संबंध' होना चाहिए। अपीलीय निकाय ने वास्तव में माना था कि कुछ परिस्थितियों में सरकार द्वारा "मार्गदर्शन" को भी निदेश माना जा सकता है।
51. उक्त अपीलीय निकाय रिपोर्ट के अनुसार, यह जांच करना जरूरी है कि क्या जारी उपाय और निजी निकाय के आचरण के बीच कोई स्पष्ट संबंध है अर्थात् क्या जीओआई द्वारा निर्यात कर और लेवी लगाने और निजी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा स्थानीय रूप से आपूर्ति किए गए सीपीकेओ की कीमत के बीच कोई संबंध है। इस संबंध में इस तथ्य के होते हुए भी कि जीओआई अपने राज्य निकाय पीटीपीएन, जो घरेलू बाजार में सीपीकेओ की कीमत निर्धारक के रूप में प्रभावी रूप से कार्य करता है, के ज़रिए बाजार में सीधे भागीदारी करती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू बाजार में कच्ची सामग्री की कीमत को कम करने के उद्देश्य के साथ निर्यात कर लगाना अपने आप में कार्य सौंपने या निदेश का पर्याप्त साक्ष्य है। इसके अलावा, यह नोट किया गया है कि इंडोनेशिया में सीपीकेओ की कम घरेलू कीमत केवल निर्यात नियंत्रणों का अनुवर्ती परिणाम नहीं है बल्कि वास्तव में इन निर्यात नियंत्रणों को लगाने का मूल उद्देश्य और लक्षित परिणाम है।
52. इसके अलावा, जांच से पता चलता है कि व्यवहार में निर्यात कर और लेवी ने घरेलू सीपीकेओ कीमतों को कम करने के अपने लक्षित उद्देश्य को प्राप्त किया है। यह पाया गया है कि भागीदार निर्यातकों की सीपीकेओ खरीद कीमत और सीपीकेओ की विश्व बाजार कीमत के बीच भारी कीमत अंतर है। अतः प्राधिकारी, नोट करते हैं कि लागू निर्यात नियंत्रणों और निजी निकायों के आचरण के बीच एक स्पष्ट संबंध है। इस प्रकार, तथ्यों की जांच से साफतौर पर पता चलता है कि निर्यात पर टैरिफ लगाने के कारण सीपीकेओ की घरेलू कीमतों में वास्तव में कमी आई है। यह इस तथ्य को भी स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अपने नीतिगत उपायों के ज़रिए, जीओआई ने सीपीकेओ के आपूर्तिकर्ताओं को घरेलू बाजार में कम कीमत पर विक्री करने की आर्थिक रूप से अनुचित स्थिति में डाल दिया है।



53. इसके अलावा, जांच से पता चला है कि जीओआई, पीटीपीएन के ज़रिए बाजार में सीधे भागीदारी करती है और कञ्ची सामग्री की घरेलू कीमत निर्धारित करती है। पीटीपीएन द्वारा निर्धारित कीमत विकृत है और वैश्विक बाजार कीमत से कम है।
54. इन तथ्यों को देखते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यात कर और लेवी के रूप में निर्यात नियंत्रण लागू करने के ज़रिए जीओआई ने निजी सीपीकेओ आपूर्तिकर्ताओं को वैश्विक बाजार से कम कीमत अर्थात् एलटीएआर पर डाउनस्ट्रीम उत्पादकों को कञ्ची सामग्री(सीपीकेओ और व्युत्पन्नियों) की आपूर्ति करने का 'कार्य सौंपा' और 'निदेश' दिया है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय अंशदान मिला है।
55. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह केवल कञ्ची सामग्री के रूप में सीपीकेओ या उसकी व्युत्पन्नियों का प्रयोग करने वाले उद्योगों पर लागू होता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि ऐसे वित्तीय अंशदान से एक स्पष्ट लाभ प्राप्त हुआ है क्योंकि इससे प्रत्यक्ष रूप से इंडोनेशियाई उत्पादकों की कञ्ची सामग्री की कीमत कम हो जाती है। अतः, प्राधिकारी इस कार्य को प्रतिसंतुलनकारी योग्य मानते हैं।

सब्सिडी की गणना

56. सब्सिडी मार्जिन को प्रतिवादी निर्यातक द्वारा प्रदत्त सीपीकेओ की खरीद कीमत के साथ अंतर्राष्ट्रीय बैंचमार्क कीमत की तुलना करके परिकलित किया गया है। प्रकटन विवरण में प्राधिकारी ने इंडोनेशिया से शेष विश्व को सीपीकेओ की निर्यात कीमत को बैंचमार्क के रूप में माना है क्योंकि इसे मुक्त बाजार सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित किया जाता है और यह इंडोनेशिया में प्रचलित बाजार दशाओं को दर्शाती है तथा यह सरकार के हस्तक्षेप से विकृत नहीं है। इस बैंचमार्क पर सब्सिडी को 20-50 प्रतिशत की रेंज में पाया गया था। तथापि, चूंकि सीपीकेओ सीआईएफ रोटरडम कीमतें वर्तमान जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ मलेशिया सरकार द्वारा प्रदत्त सब्सिडी की गणना के लिए बैंचमार्क मानी गई हैं, इसलिए प्राधिकारी इंडोनेशिया और मलेशिया, दोनों के लिए इन्हें साझा बैंचमार्क मानना उचित समझते हैं। यह नोट किया गया है कि सीपीकेओ रोटरडम कीमत पाँच गिरि तेल में व्यापार के लिए एक वैश्विक बैंचमार्क है। रोटरडम कीमत सीपीकेओ की अविकृत कीमत दर्शाती है और यह धातु उत्पादों के लिए लंडन मेटल एक्सचेंज के समान इंडेक्स है। यहां तक कि जीओआई निर्यात शुल्क लगाने के लिए 'संदर्भ कीमत' निर्धारित करने हेतु सीआईएफ रोटरडम कीमतों पर विचार करती है। इसके महेनजर, तथा इंडोनेशिया और मलेशिया, दोनों के लिए एक समान बैंचमार्क अपनाने हेतु प्राधिकारी ने मालभाड़ा और बीमा के समायोजन के पश्चात सीपीकेओ रोटरडम कीमत पर इंडोनेशिया और मलेशिया, दोनों के लिए उचित बैंचमार्क के रूप में विचार किया है और तदनुसार उस पर सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किया गया है।
57. अनेक हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि निर्यात कर और निर्यात लेवी को बैंचमार्क कीमत के निर्धारण हेतु सीआईएफ कीमत से बाहर रखना चाहिए। प्राधिकारी को उक्त अनुरोध में कोई सञ्चार्य नहीं दिखती है क्योंकि तुलना के लिए सीपीकेओ की विश्व बाजार कीमत (माला भाड़ा और बीमा के लिए यथा समायोजित) और ऑनशोर इंडोनेशिया की स्थानीय कीमत ली गई है। अपनाया गया वैंचमार्क सीपीकेओ की अविकृत बाजार कीमत को दर्शाता है। यह नोट किया गया है कि इंडोनेशिया सरकार ने निर्यात और निर्यात लेवी लगाकर सीपीकेओ की स्थानीय कीमत को विश्व बाजार कीमत से कम कर दिया है। यह नोट किया गया है कि सीपीकेओ की विश्व बाजार कीमत और स्थानीय इंडोनेशियाई

कीमत में अंतर इस निर्यात पर और निर्यात लेवी की वजह से प्राथमिक रूप से हुआ है। इस प्रकार, निर्यात कर और निर्यात लेवी को घटाने से इस तुलना का मूल प्रयोजन ही विफल हो जाएगा।

एलटीएआर पर सीपीकेओ की आपूर्ति से इतर स्कीमें

58. यह नोट किया गया है कि इंडोनेशिया के मामले में याचिकाकर्ता ने कुल 12 सब्सिडी स्कीमों का आरोप लगाया है और तदनुसार उनके संबंध में संबंधित उत्पादकों/निर्यातकों से तथा इंडोनेशिया सरकार से उत्तर प्राप्त हुए हैं। तथापि, जांच के दौरान यह देखा गया है कि कार्यक्रम 1 अर्थात् पर्याप्त से कम मूल्य पर कद्दी सामग्री के प्रावधान के लिए सब्सिडी मार्जिन स्वयं ही इंडोनेशिया से भागीदार और गैर-भागीदार उत्पादकों/निर्यातकों के लिए ज्ञात क्षति मार्जिन से अधिक है। चूंकि, भारत कमतर शुल्क के नियम अर्थात् अनुशंसित सब्सिडी मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कम के बराबर शुल्क के सिद्धांत का पालन करता है इसलिए, यदि अन्य स्कीमों की विस्तार से जांच की जाती है और उन्हें प्रतिसंतुलनयोग्य पाया जाता है और उसके बाद सब्सिडी मार्जिन ज्ञात किया जाता है तो भी प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित किए जाने वाले शुल्क की राशि पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि वह वर्तमान जांच के तथ्यों और परिस्थितियों की केवल एक शैक्षिक प्रक्रिया होगी। उक्त तथ्य के मद्देनजर, न्यायाचिक किफायत के सिद्धांत को लागू किया गया है और जांच को केवल पूर्वोक्त पहली स्कीम तक सीमित रखा गया है।

इंडोनेशिया से उत्पादक/निर्यातक

पीटी विलमार नबाटी, इंडोनेशिया, नैचुरल ओलियोकेमिकल्स एसडीएन बीएचडी, मलेशिया और विलमार ट्रेडिंग पीटीई लिमिटेड सिंगापुर (डब्ल्यूआईएनए ग्रुप)

59. पीटी विलमार नबाटी ("विलमार") संबद्ध वस्तु का उत्पादक-निर्यातक है। उसने संबंधित व्यापारी विलमार ट्रेडिंग पीटीई लिमिटेड सिंगापुर के जरिए भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। विलमार ने दावा किया है कि उसे कोई सब्सिडी नहीं मिली है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि विलमार ने मिथाईल ईस्टर के निर्माण के लिए एलटीएआर पर घरेलू रूप से खरीदे गए सीपीकेओ का प्रयोग किया है जिसका प्रयोग पीयूसी के उत्पादन में हुआ है। विलमान द्वारा नी गई सब्सिडी निम्नानुसार है:

कार्यक्रम	सब्सिडी मार्जिन (%)	रेंज
एलटीएआर पर सीपीकेओ की आपूर्ति	***%	30-40%

पीटी. मुजिम, इंडोनेशिया और इंटर-कॉन्टिनेटल ऑयल्स एंड फैट्स पीटीई लिमिटेड सिंगापुर (पीटीएमएम ग्रुप)

60. पीटी. मुजिम मास ("पीटीएमएम") संबद्ध वस्तु का उत्पादक है। उसने इंटर-कॉन्टिनेटल ऑयल्स एंड फैट्स पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर के जरिए भारत को निर्यात किया है। यह नोट किया गया है कि पीटीएमएम ने संबद्ध वस्तु के विनिर्माण के लिए एलटीएआर पर घरेलू रूप से प्राप्त सीपीकेओ का प्रयोग किया है। कि पीटीएमएम ने निम्नानुसार लाभ प्राप्त किया है:

कार्यक्रम	सब्सिडी मार्जिन (%)	रेंज
एलटीएआर पर सीपीकेओ की आपूर्ति	***%	25-35%

पीटी. इकोग्रीन ओलियोकेमिकल्स, इंडोनेशिया और इकोग्रीन ओलियोकेमिकल्स (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड (पीटीईओ ग्रुप)

61. पीटी इकोग्रीन ओलियोकेमिकल्स ("पीटीईओ") संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है और उसने अपने संबंधित व्यापारी इकोग्रीन ओलियोकेमिकल्स (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड के जरिए भारत को निर्यात किया है। यह नोट किया गया है कि पीटीईओ ने एलटीएआर पर स्थानीय रूप से सीपीकेओ खरीदा है जिसे उसने संबद्ध वस्तु के उत्पादन में उपयोग किया है। पीटीईओ समूह के लिए निर्धारित सब्सिडी मार्जिन निम्नानुसार है:

कार्यक्रम	सब्सिडी मार्जिन (%)	रेंज
एलटीएआर पर सीपीकेओ	***%	20-30%

पीटी. एनर्जीसेजातेरा मास, इंडोनेशिया और सिनरमास केपसा पीटीई लिमिटेड सिंगापुर (ईएसएम)

62. पीटी. एनर्जी सेजातेरा मास ("ईएसएम") संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है और उसने अपने संबंधित व्यापारी सिनरमास सेप्मा पीटीई लिमिटेड (एससीपीएल) के जरिए भारत को निर्यात किया है। यह नोट किया गया है कि ईएसएम ने संबद्ध वस्तु के उत्पादन हेतु एलटीएआर पर सीपीकेओ की खरीद की है। ईएसएम समूह के लिए निर्धारित सब्सिडी मार्जिन निम्नानुसार है:

कार्यक्रम	सब्सिडी मार्जिन (%)	रेंज
एलटीएआर पर सीपीकेओ	***%	20-30%

इंडोनेशिया के लिए सब्सिडी कार्यक्रमों का सारांश

63. इंडोनेशिया से सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क सहयोगी पक्षकारों द्वारा प्राप्त सब्सिडियों के उच्चतम सब्सिडी मार्जिन के आधार पर और अन्य सब्सिडी कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है:

कार्यक्रम का नाम	सब्सिडी मार्जिन %	रेंज %
एलटीएआर पर सीपीकेओ का प्रावधान	***%	30-40%

*इंडोनेशिया के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए किसी निर्यात सब्सिडी पर विचार नहीं किया गया

मलेशिया

64. प्राधिकारी ने मलेशिया सरकार द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित कार्यक्रमों की जांच की है:

i.	कार्यक्रम सं. 1	पर्यास से कम मूल्य पर सीपीकेओ का प्रावधान
ii.	कार्यक्रम सं. 2	अनुदान के रूप में अभिज्ञात स्कीमें
		क) बाजार विकास अनुदान (एमडीजी)
		ख) निर्यात ऋण और निर्यात वित्त पोषण
		ग) क्रेता ऋण गारंटी
		घ) टेक्नो निधि
		ड.) इनो निधि
		च) क्रैडल निवेश कार्यक्रम
iii.	कार्यक्रम सं.. 3	व्यापार/उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार
iv.	कार्यक्रम सं. 4	कर प्रोत्साहन के रूप में अभिज्ञात स्कीमें
		क) अग्रणी दर्जा
		ख) निवेश कर नीतियां/भत्ते
		ग) पुनःनिवेश भत्ता
		घ) त्वरित पूंजी भत्ता
v.	कार्यक्रम सं. 5	समूह राहत

vi.	कार्यक्रम सं. 7	औद्योगिक भवन भत्ता
vii.	कार्यक्रम सं. 8	लघु और मध्यम उद्यम के लिए प्रोत्साहन
viii.	कार्यक्रम सं. 9	आंतरिक आरएंडडी के लिए कर प्रोत्साहन
ix.	कार्यक्रम सं. 10	अनुसंधान और विकास के लिए दोहरी कटौती
x.	कार्यक्रम सं. 11	मलेशियाई ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए दोहरी कटौती
xi.	कार्यक्रम सं. 17	निर्यात संवर्धन के लिए दोहरी कटौती
xii.	कार्यक्रम सं. 18	बढ़े हुए निर्यातों के लिए भत्ता
xiii.	कार्यक्रम सं. 19	मुक्त व्यापार जोन के लिए कर छूट
xiv.	कार्यक्रम सं. 20	ऋण के रूप में अभिज्ञात स्कीमें क) अनुसंधान और विकास निधि ख) लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए सरल ऋण
xv.	कार्यक्रम सं. 22	एलटीएआर पर भूमि के प्रावधान की स्कीम
xvi.	कार्यक्रम सं. 23	एलटीएआर पर विजली के प्रावधान की स्कीम
xvii.	कार्यक्रम सं. 24	कद्दी सामग्री/पैकेजिंग सामग्री पर बिक्री कर से छूट
xviii.	कार्यक्रम सं. 25	मशीनरी उपकरण और कलपुर्जों पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट
xix.	कार्यक्रम सं. 26	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरण का गुणवत्तायुक्त संयंत्र व्यय और लघु मूल्य परिसंपत्तियों के लिए विशेष भत्ता संबंधि त्वरित पूंजीगत भत्ता
xx.	कार्यक्रम सं. 27	लेखा परीक्षा व्यय, सचिवालयी शुल्क और फाइलिंग शुल्क के लिए कटौती
xxi.	कार्यक्रम सं. 28	संतुलन भत्ता
xxii.	कार्यक्रम सं. 29	ओलियो व्युत्पत्तियों के उत्पादन के संवर्धन हेतु अनुदान
xxiii.	कार्यक्रम सं. 30	कोविड-19 राहत उपाय
xxiv.	कार्यक्रम सं. 31	अधिमानी ऋण

च.4 याचिकाकर्ता द्वारा आरोपित सब्सिडी कार्यक्रमों की जांच

(i) कार्यक्रम सं. 1 – एलटीएआर पर कद्दी सामग्री (सीपीकेओ और उसकी व्युत्पत्तियाँ) का प्रावधान

क. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध

65. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि मलेशिया सरकार (“जीओएम”) सीपीकेओ के निर्यात पर निर्यात कर लगाती है। इन निर्यात करों का प्राथमिक उद्देश्य मलेशिया में सीपीकेओ की घरेलू कीमत को कम करना है। तदनुसार, यह बताया गया है कि मलेशिया में कद्दी सामग्री की कीमत विकृत है और बाजार कीमत से कम है। याचिकाकर्ता ने यह आरोप लगाया है कि कद्दी सामग्री पर निर्यात कर लगाने के पीछे का उद्देश्य मलेशियाई एसएफए उत्पादकों की उत्पादन लागत कम करना है ताकि वे इंडोनेशियाई निर्माताओं के सब्सिडी प्राप्त उत्पादन लागत से बराबरी करने में सक्षम हों। उक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जीओएम ने जनवरी, 2021 से सीपीकेओ के निर्यातों पर 10 प्रतिशत का निर्यात शुल्क लगा दिया है।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

66. जीओएम ने बताया है कि सीपीकेओ पर निर्यात शुल्क लगाने का उद्देश्य और प्रयोजन आम उद्योग की कंपनियों को उच्च मूल्यवर्धित डाउनस्ट्रीम उत्पाद उत्पादित करने तथा नई कंपनियों और मौजूदा उद्योग कंपनियों के जरिए अपने निर्यातों को बढ़ाना है। यह दावा किया गया है कि निर्यात शुल्क एक राजस्व संग्रह उपाय है, प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडी नहीं है।

67. जीओएम तथा प्रतिवादी निर्यातकों ने यूएस-निर्यात अवरोध में डब्ल्यूटीओ पैनल के निर्णय पर यह तर्क देने हेतु भरोसा किया है कि केवल 'निर्यात अवरोध' लगाना सब्सिडी नहीं है क्योंकि सरकार ने कोई 'वित्तीय अंशदान' नहीं दिया है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

68. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जीओएम सीपीकेओ और उसकी व्युत्पत्तियों के निर्यातों पर निर्यात शुल्क लगाता है। प्रश्नावली के अपने उत्तर में जीओएम ने स्वीकार किया है कि निर्यात शुल्क लगाने का उद्देश्य और प्रयोजन मूल्यवर्धित डाउनस्ट्रीम उत्पादों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडोनेशिया के बाद मलेशिया सीपीकेओ का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। जीओएम सीपीकेओ पर निर्यात कर लगाकर मलेशिया में कम्ब्री सामग्री की कीमत में गड़बड़ी करता है और इस प्रकार सुनिश्चित करता है कि वह बाजार कीमत से कम पर मलेशिया के एसएफए उत्पादकों को उपलब्ध हो।

69. यह नोट किया गया है कि मलेशिया में निर्यात कर व्यवस्था इंडोनेशिया के समतुल्य लाने के लिए पुनर्गठित की गई थी ताकि मलेशियाई डाउनस्ट्रीम उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि की जा सके और उन्हें इंडोनेशियाई डाउनस्ट्रीम उत्पादकों के बराबर लाभ दिया जा सके। तान श्री डाटुक डा. युसोफबेसिरोन, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मलेशियन पॉम ऑयल काउंसिल² द्वारा दिए गए प्रस्तुतिकरण में मलेशिया द्वारा लगाए गए निर्यात कर का उद्देश्य निम्नानुसार नोट किया गया था (स्लाइड 13 में) :

- i. मलेशियाई ओलियोकेमिकल (जिसमें एसएफए शामिल है) उद्योग को बेहतर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करने के लिए इंडोनेशियाई लाभ (निर्यात कर के कारण) को निष्क्रिय बनाया जाना चाहिए।
- ii. अल्पाधिकार बाजार में जिसमें कम आपूर्तिकर्ता (केवल दो) हैं, यदि एक कंपनी तीन क्षेत्रों में सब्सिडी प्राप्त है तो दूसरी कंपनी को भी बाजार हिस्सा बनाए रखने के लिए यही करना चाहिए।

70. इस प्रकार, स्पष्ट रूप से सीपीकेओ के निर्यात पर मलेशिया द्वारा लागू निर्यात कर का उद्देश्य जीओआई द्वारा उसके डाउनस्ट्रीम उत्पादकों को प्रदत्त सब्सिडी की नकल कना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मलेशियाई डाउनस्ट्रीम उत्पादकों को भी इंडोनेशियाई उत्पादकों जैसा ही लाभ प्राप्त हो। प्राधिकारी ने एलटीएआर पर सीपीकेओ की आपूर्ति द्वारा जीओआई द्वारा प्रदत्त 'वित्तीय अंशदान' की गहराई से जांच की है। प्राधिकारी मानते हैं कि इसके प्रदत्त कारण वर्तमान स्कीम पर लागू होते हैं और संचितता के लिए उन्हें यहां दोहराया नहीं गया है।

71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जीओएम द्वारा सीपीकेओ पर लागू निर्यात शुल्क वैश्विक बाजार से कम कीमत पर कम्ब्री सामग्री उपलब्ध कराकर डाउनस्ट्रीम उत्पादों जैसे एसएफए के विनिर्माताओं को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट रूप से डिजाइन किए गए हैं और यह एक आय बढ़ाने का उपाय नहीं है। निर्यात कर लागू करके जीओएम ने सीपीकेओ के अपने घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को वैश्विक बाजार से कम कीमत पर घरेलू विनिर्माताओं को सीपीकेओ बेचने की अनुचित स्थिति में डाल दिया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडोनेशिया की तरह निर्यात शुल्क लगाने और निजी निकायों द्वारा एसएफए उत्पादकों को बेचे जा रहे सीपीकेओ की कीमत के बीच एक स्पष्ट संबंध है। वैश्विक बाजार कीमत (सीआईएफ रोटरडम, माल भाड़ा और बीमा के लिए समायोजित) के साथ सीपीकेओ की खरीद कीमत की तुलना से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सीपीकेओ को पर्याप्त से कम मूल्य पर मलेशियाई उत्पादकों को बेचा जा रहा है। निजी सीपीकेओ आपूर्तिकर्ता का वैश्विक बाजार से कम कीमत पर सीपीकेओ की आपूर्ति का कार्य घरेलू डाउनस्ट्रीम उत्पादकों की प्रतिस्पर्धात्मकता में बड़ोतरी सुनिश्चित करने की जीओएम की नीति के क्रम में है। अतः यह नोट किया गया है कि निर्यात नियंत्रणों को लागू करके जीओएम सीपीकेओ के निजी आपूर्तिकर्ताओं को डाउनस्ट्रीम एसएफए के विनिर्माताओं के लिए पर्याप्त से कम मूल्य पर सीपीकेओ बेचने का कार्य सौंपता या निदेश देता है।

72. इसी संबंध में यूएस-निर्यात नियंत्रण, में डब्ल्यूटीओ पैनल के निर्णय पर हितबद्ध पक्षकारों ने भरोसा किया है, प्राधिकारी ने पहले ही ऊपर नोट किया है कि कोरिया से डाइनेमिक रेंडम ऐक्सस मेमोरी सेमिकंडक्टर्स (डीआरएएमएस) संबंधी संयुक्त राज्य - प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच में डब्ल्यूपीओ अपीलीय निकाय द्वारा इस पर विचार किया गया था जिसमें यह नोट किया गया था कि कार्य सौंपने या निदेश के लिए निजी निकायों का कार्य अनजाने में नहीं हो सकता है या केवल सरकारी विनियम का उप-उत्पाद नहीं हो सकता है। सरकार और निजी निकाय के आचरण के बीच स्पष्ट संबंध होना

² <http://www.mponc.org.my/upload/P1%20-%20Tan%20Sri%20Yusof%20Basiron.pdf>

चाहिए। अपीलीय निकाय द्वारा नोट किया गया था कि सरकार द्वारा “मार्गदर्शन” भी कार्य सौंपना हो सकता है। अपीलीय निकाय ने यह भी नोट किया था कि यूएस-निर्यात नियंत्रण मामले में पैनल की याचिका अनुचित रूप से “संकीर्ण” थी।

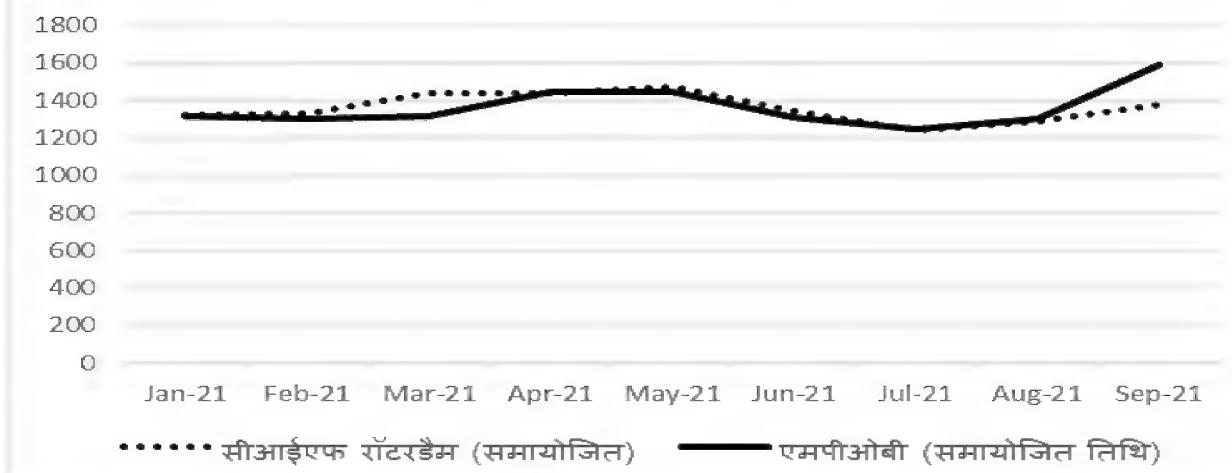
73. अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि जीओएम ने एनटीएआर पर सीपीकेओ के प्रावधान के रूप में वित्तीय अंशदान दिया है और इस प्रकार लाभ मिला है क्योंकि इससे मलेशियाई एसएफए उत्पादकों की कद्दी सामग्री की लागत में सीधे कमी आई है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह कद्दी सामग्री के रूप में सीपीकेओ का प्रयोग करने वाले उद्योगों पर लागू होता है। तदनुसार, प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलनयोग्य मानते हैं।

सब्सिडी की गणना

74. प्राधिकारी ने सब्सिडी की गणना के लिए उचित बैंचमार्क के रूप में सीपीकेओ रोटरडम कीमत पर विचार किया है। यह नोट किया गया है कि निर्यात करों को जनवरी, 2021 से मलेशिया में पुनः शुरू किया गया था। तदनुसार प्राधिकारी ने सब्सिडी मार्जिन की गणना के लिए मलेशियाई निर्यातकों द्वारा की गई सीपीकेओ की खरीद पर विचार किया है। यह नोट किया गया कि सीआईएफ रोटरडम पॉम गिरि तेल के व्यापार के लिए एक वैश्विक बैंचमार्क है। रोटरडम की कीमत सीपीकेओ के लिए अविकृत कीमत दर्शाती है और यह धातु उत्पादों के लिए लंडन मेटल एक्सचेंज के समान एक सूचकांक है। वास्तव में, घरेलू उद्योग तथा अनेक निर्यातकों ने बताया है कि वे व्यापार की नियमित प्रक्रिया में अपने अनुबंधों पर वार्ता के लिए सीआईएफ रोटरडम कीमतों का प्रयोग करते हैं।

75. इसके अलावा, प्राधिकरण नोट करता है कि सीआईएफ रॉटरडैम की कीमतें अनुबंध की तारीख की कीमतें हैं और इसलिए, यह देखते हुए कि मलेशिया में सीपीकेओ पर निर्यात कर पीओआई की शुरुआती अवधि में शून्य था, अधिक उपयुक्त बैंचमार्क हैं। चूंकि जनवरी, 2021 में ही निर्यात कर फिर से लगाया गया था, इसलिए शुरुआती अवधि में किए गए शिपमेंट को निर्यात कर घटक में शामिल नहीं किया जाएगा। जांच करने पर, यह पाया गया है कि अनुबंध को अंतिम रूप देने और इसके शिपमेंट के बीच आम तौर पर 30-45 दिनों का समय अंतराल होता है। सीआईएफ रॉटरडैम मूल्य (माल और बीमा के लिए समायोजित) और एमपीओबी निर्यात कीमतों की तुलना (अनुबंध महीने की कीमत पर पहुंचने के लिए एक महीने तक समायोजित, यानी फरवरी'21 निर्यात मूल्य को जनवरी'21 की दर के रूप में मानते हुए), यह नोट किया जाता है कि कहा कि कीमतें एक साथ चल रही हैं। समायोजित MPOB निर्यात मूल्य और CIF रॉटरडैम मूल्य (समायोजित) जनवरी-सितंबर 2021 के लिए नीचे दिए गए हैं:

सीपीकेओ मूल्य (यूएसडी/एमटी)



यह भी नोट किया जाता है कि जनवरी-सितंबर 2021 के लिए औसत समायोजित एमपीओबी निर्यात मूल्य और सीआईएफ रॉटरडैम क्रमशः 1361 अमेरिकी डॉलर/एमटी और 1364 अमेरिकी डॉलर/एमटी हैं। इसलिए प्राधिकरण ने सब्सिडी राशि निर्धारित करने के लिए खरीद आदेश महीने-वार घरेलू खरीद मूल्य की अनुबंध महीने-वार सीआईएफ रॉटरडैम कीमत के साथ तुलना करना उचित पाया है।

एलटीएआर पर कद्दी सामग्री की आपूर्ति से इतर स्कीम

76. याचिकाकर्ता ने कुल 31 सब्सिडी स्कीमों का आरोप लगाया है और तदनुसार संबंधित उत्पादकों/निर्यातकों तथा मलेशिया सरकार से उनके संबंध में उत्तर प्राप्त हुए हैं। यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता के दावे का सार यह है कि एलटीएआर पर कद्दी सामग्री दी गई है जिसकी यहां गहराई से जांच की गई है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने प्राथमिक रूप से इस आधार पर कतिपय अन्य सब्सिडी स्कीमों का भी आरोप लगाया है कि ये स्कीमें पूर्ववर्ती जांचों में प्रतिसंतुलनयोग्य पाई गई थी। तथापि, इन में से अधिकांश स्कीमों की जांच में यह पाया गया है कि या तो संबद्ध वस्तु के उत्पादकों को कोई लाभ नहीं मिला है या प्राप्त लाभ नगण्य/गैर माप योग्य हैं। तदनुसार, प्राधिकरण ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से निम्नलिखित योजनाओं की जांच की है:

कार्यक्रम संख्या	विवरण
कार्यक्रम 17	निर्यातों पर दोहरी कटौती
कार्यक्रम 23	एनटीएआर पर प्राकृतिक गैस और बिजली
कार्यक्रम 24	कद्दी सामग्रीपैकेजिंग सामग्री पर बिक्री कर से छूट/
कार्यक्रम 25	मशीनरी और उपकरण के आयात पर आयात शुल्क से छूट
कार्यक्रम 29	ओलेओ डेरिवेटिव्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनुदान

(ii) कार्यक्रम सं. 17- निर्यातों के संवर्धन हेतु दोहरी कटौती

क. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध

77. पीआईए की धारा 41 और आयकर (निर्यात संवर्धन) नियम, 1986 निर्यातों के संवर्धन पर हुए व्यय जैसे विदेश में कार्यालय रखने की लागत, प्रचार और निर्यात संवर्धन आदि के लिए मलेशिया से बाहर किसी माध्यम से विज्ञापन की लागत के लिए निर्यातकों को दोहरी कटौती प्रदान करते हैं। यह कार्यक्रम प्राधिकारी द्वारा 'कन्टीनिवस कॉस्ट कॉपर वायर रोड्स', 'एल्युमिनियम वायर/वायर रोड्स 4 मि.मी. व्यास से अधिक' 'क्लियर फ्लोट ग्लास' और 'फाइबर बोड्स' के आयातों से संबंधित अपने अंतिम जांच परिणाम में प्रतिसंतुलन योग्य माना था।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

78. यह कार्यक्रम आयकर (निर्यात संवर्धन) नियम, 1986 के 4(2) के साथ पठित निवेश संवर्धन अधिनियम (पीआईए) 1986 (अधि. 327) की धारा 41 के अन्तर्गत प्राथमिक रूप से आधार अवधि में और मुख्य रूप से अवसर प्राप्त करने या मलेशियाई उत्पादित वस्तुओं या कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए मांग सृजन या बढ़ाने में हुए व्यय के संबंध में सभी निवासी व्यापारी, विनिर्माण या कृषि कंपनियों पर लागू है।

79. यह कार्यक्रम मलेशियाई कंपनियों को निर्यात निष्पादन में उनकी वस्तु या घेरेलू वस्तुओं के प्रयोग संबंधी पात्र निर्यात संवर्धन कार्यकलाप में भागीदारी में सहायता करने पर केन्द्रित है। सभी फर्में, जो पात्रता मापदंडों को पूरा करती हैं, इस कार्यक्रम का लाभ ले सकती है। जांच के अधीन कंपनियां कटौती का दावा करने की पात्र होंगी। यदि वे मापदंडों को पूरा करती हैं। कार्यक्रम में कोई प्रत्याशित बदलाव नहीं हैं। यह कटौती आगे ले जाई जा सकती है। संबद्ध वस्तु के कुछ उत्पादकों ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया है।

80. आवेदक कंपनियों के लिए फार्म भरकर और विदेशी विज्ञापन, यात्रा और निर्यात संवर्धन खर्च से संबंधित व्यय के बारे में व्यापार प्राप्तियों की प्रतियों के साथ दावे को सिद्ध करते हुए प्रोत्साहन का दावा करना अपेक्षित है। मूल समर्थक दस्तावेज आईआरबी द्वारा लेखा परीक्षा प्रयोजनों के लिए कंपनी द्वारा रखे जाएंगे। संबद्ध वस्तु के कुछ उत्पादकों ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम निवेश संवर्धन अधिनियम (पीआईए) 1986 (अधि. 327) की धारा 41 और आयकर (निर्यात संवर्धन) नियम, 1986 के नियम 4(2) द्वारा शासित होता है। इस कार्यक्रम के तहत निर्यात के संवर्धन

पर आय खर्च के लिए विनिर्माण, व्यापार और कृषि कार्यकलापों में शामिल उद्यमों के लिए आय से दोहरी कटौती उपलब्ध है। निर्यात के लिए मांग बढ़ाने हेतु किसी कंपनी द्वारा किए गए व्यय पर दोहरी कटौती की अनुमति है।

82. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम ऐसे गंवाए गए राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इससे लाभ मिला है। यह लाभ प्रदत्त दोहरी कटौती के बाद प्रदत्त आयकर की राशि और ऐसी दोहरी कटौती के न होने पर देय आयकर की राशि का बीच का अंतर है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यात कार्य निष्पादन पर निर्भर है और निर्यात संवर्धन कार्यकलाप में शामिल उद्यम तक सीमित है। अतः प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन योग्य मानते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि केएल-केपोंग ओलियाकेमिकल्स को इस कार्यक्रम के तहत लाभ मिला है (निर्यात सब्सिडी)।

(iii) कार्यक्रम सं.23 – एलटीएआर पर प्राकृतिक गैस और बिजली का प्रावधान

क. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध

83. याचिकाकर्ता ने याचिका में दावा किया था कि मलेशिया में बिजली एलटीएआर पर दी जाती है। तत्पश्चात, मौखिक सुनवाई के बाद लिखित अनुरोध में याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि जीओएम, पैट्रोनास और गैस मलेशिया बेरहड के जरिए एलटीएआर पर औद्योगिक ग्राहकों को गैस की आपूर्ति करता है। गैस आपूर्ति अधिनियम, 1993 बिजली क्षेत्र सहित उद्योगों को विनियमित कम कीमतों पर प्राकृतिक गैस की विक्री करने का कंपनियों को निदेश देता है। बाजार कीमत और विनियमित कीमत में अंतर को उक्त कंपनियों द्वारा जीओएम से लिया जाता है। प्राकृतिक गैस, जो संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए जरूरी मुख्य उपभोज्य वस्तु है, एलटीएआर पर एसएफए के घरेलू विनिर्माताओं द्वारा आपूर्ति की जाती है।

84. याचिकाकर्ता ने यह भी बताया है कि मलेशिया में बिजली प्राकृतिक गैस से बनती है चूंकि मलेशिया में प्राकृतिक गैस सब्सिडी प्राप्त है, इसलिए यह सब्सिडी एलटीएआर पर बिजली के प्रावधान द्वारा एसएफए उत्पादकों को भी मिलती है।

85. याचिकाकर्ता ने मलेशिया से कॉपर ट्यूब और पाइपों से संबंधित जांच में जारी दिनांक 31 जनवरी, 2022 के अंतिम जांच परिणाम पर यह बताने के लिए भरोसा किया है कि मलेशिया में औद्योगिक ग्राहकों के लिए प्राकृतिक गैस और बिजली प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडी है।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

86. प्राधिकारी ने जीओएम और भागीदार निर्यातकों को प्राकृतिक गैस और बिजली की खरीद और आपूर्ति के ब्यारे देने के लिए पूरक प्रश्नावली जारी की थी। अपने पूरक उत्तर में जीओएम ने बताया है कि पैट्रोनास द्वारा प्राकृतिक गैस "इच्छुक क्रेता-इच्छुक विक्रेता" दरों पर दी जाती है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

87. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम गैस आपूर्ति अधिनियम, 1993 द्वारा शासित है। यह सब्सिडी कार्यक्रम बिजली क्षेत्र सहित औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्राकृतिक गैस विनियमित कीमतों पर उपलब्ध कराता है। यह नोट किया गया है कि जीओएम गैस आपूर्तिकर्ता कंपनियों अर्थात पैट्रोनास और गैस मलेशिया बेरहड (जीएमबी) को सब्सिडी देता है, जो बाद में कम दरों पर निर्यातकों को गैस की आपूर्ति करते हैं। जीओएम ने 07.09.2022 को हुई सत्यापन चर्चा के दौरान यह स्वीकार किया कि मलेशिया में प्राकृतिक गैस की कीमत जीओएम द्वारा विनियमित है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के उत्पादक अपनी विनिर्माण प्रक्रिया में उस प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं जो विनियमित दरों पर खरीदी गई है। अतः, प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन योग्य मानते हैं क्योंकि इससे बाजार कीमत से कम पर प्राकृतिक गैस का प्रावधान जीओएम द्वारा किया जाता है और इस प्रकार लाभ मिला है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह 'प्राकृतिक गैस' का प्रयोग करने वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं तक सीमित है।

88. प्राधिकरण आगे नोट करता है कि मलेशिया में बिजली का उत्पादन प्राकृतिक गैस से होता है। मलेशिया में बिजली वितरण को विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1990 के तहत विनियमित किया जाता है। अधिनियम के तहत केवल ऊर्जा आयोग द्वारा लाइसेंस प्राप्त संस्थाएं ही बिजली की आपूर्ति करेंगी। इसलिए, ऐसे निकायों को सरकारी कार्य सौंपे जाते हैं और वे सार्वजनिक निकायों के रूप में कार्य करते हैं। यह ध्यान दिया गया है कि ऐसे सार्वजनिक निकायों द्वारा बाजार मूल्य से कम कीमत पर बिजली की पेशकश की जा रही है। यह पाया गया है कि प्राकृतिक गैस पर लाभ आईसीपीटी

(असंतुलन लागत पास थे) शुल्क के रूप में बिजली उत्पादन के लिए पारित किया जा रहा है। इसलिए प्राधिकरण इस कार्यक्रम को प्रतिकारी मानता है।

अन्य कार्यक्रम

(iv) कार्यक्रम 24 – कच्ची सामग्रियों/पैकेजिंग सामग्री पर बिक्री कर की छूट

क. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध

89. इस कार्यक्रम के संबंध में याचिकाकर्ता ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

90. जीओएम द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने बताया है कि जीओएम ने बिक्री कर(कर से छूट प्राप्त वस्तुएं) आदेश, 2018 के माध्यम से संबद्ध वस्तु के विनिर्माण में प्रयुक्त अधिकांश कच्ची सामग्रियों पर बिक्री कर से छूट दी है। यह अनुरोध किया गया है कि उक्त छूट सभी आयातकों पर लागू सामान्य छूट जैसी है।

91. इसके अलावा, जीओएम ने बिक्री कर (कर के भुगतान से छूट प्राप्त व्यक्ति) आदेश, 2018 जारी किया है, उक्त आदेश की अनुसूची बी के क्र.सं.4 पर महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किसी विनिर्माता को तब कच्ची सामग्रियों, घटकों और पैकेजिंग सामग्री पर बिक्री कर से छूट दी गई है जब उसे किसी पंजीकृत विनिर्माता से आयातित या खरीदा जाए। इसमें निम्नलिखित शर्तें विहित हैं जिन्हें छूट प्राप्त करने के लिए पात्र होने हेतु पूरा करना अपेक्षित है -

- i. यह कि कच्ची सामग्री और घटक किसी पंजीकृत विनिर्माता से आयातित किए या खरीदे जाएं;
- ii. यह कि कच्ची सामग्री और घटक प्रयोग किए जाएं और उनसे निर्मित वस्तुएं आयात या खरीद की तारीख से 12 महीनों की अवधि या ऐसी अतिरिक्त अवधि जिसे महानिदेश द्वारा अनुमोदित किया जाए, के भीतर निर्यातित कर दी जाए;
- iii. यह कि कच्ची सामग्रियां और घटक और उनसे निर्मित वस्तुएं महानिदेशक की मंजूरी को छोड़कर और कर की उचित राशि के भुगतान पर मलेशिया में नहीं बेची जाएगी या अन्यथा नहीं निपटाई जाएगी;
- iv. यह कि कच्ची सामग्री और घटक केवल निर्यात के लिए छूट प्राप्त वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग की जाएंगी;
- v. यह कि अनुमोदित व्यक्ति ऐसी किसी कच्ची सामग्री और घटक पर बिक्री कर का भुगतान करेगा, जो लेखाबद्ध ना हो;
- vi. यह कि यदि कच्ची सामग्री और घटक का प्रयोग ना हो और उनसे निर्मित वस्तु का आयात या खरीद की तारीख से 12 महीनों के भीतर या ऐसी अन्य अवधि जो महानिदेशक द्वारा अनुमोदित हो, के भीतर निर्यात नहीं किया जाता है तो अनुमोदित व्यक्ति खरीदी गई या आयातित कच्ची सामग्री और घटकों पर बिक्री कर का भुगतान करेगा।

92. पंजीगत वस्तुओं पर बिक्री कर से छूट बिक्री कर (कर भुगतान से छूट प्राप्त व्यक्ति) आदेश, 2018 के क्रम 55 के अन्तर्गत पात्र उत्पादकों को भी प्रदान की जाती है।

93. यह छूट एससीएम करार के फुटनोट 1 के अनुसार प्रतिसंतुलन योग्य नहीं है क्योंकि यह केवल छूट प्राप्त वस्तु के उत्पादक के लिए है जो निर्यात हेतु लक्षित नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए उचित तंत्र मौजूद है कि किसी अतिरिक्त बिक्री कर से छूट न मिली हो।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

94. प्राधिकरण नोट करता है कि बिक्री कर (वस्तुओं को कर से छूट प्राप्त है) आदेश, 2018 वस्तुओं पर ही बिक्री कर की छूट प्रदान करता है और यह किसी के लिए भी सामान्य छूट है। इस प्रकार, कार्यक्रम विशिष्ट नहीं है और इसलिए प्रतिकार योग्य नहीं है।

95. दूसरी ओर (कर भुगतान से छूट प्राप्त व्यक्ति) आदेश, 2018 निर्यात वस्तुओं में प्रयुक्त कच्ची सामग्री/घटक पर पात्र उत्पादक को बिक्री कर से छूट देता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि (कर भुगतान से छूट प्राप्त व्यक्ति) आदेश, 2018 गंवाए गए राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि यह उन उद्यमों तक सीमित है जो पंजीकृत विनिर्माताओं से कच्ची सामग्रियां/पैकेजिंग सामग्री/कलपुर्जे खरीदते हैं। यह कार्यक्रम एससीएम करार के फुटनोट 1 के अंतर्गत अनुमति योग्य शुल्क प्रेषण कार्यक्रम नहीं है क्योंकि निर्यात के लिए

वस्तुओं के उत्पादन हेतु जरूरी निविष्टियों, पैकेजिंग सामग्री आदि की प्रकृति और मात्रा निर्धारित करने के लिए जीओएम द्वारा अपनाए गए सत्यापन तंत्र को दर्शने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है। इसके अलावा, पूँजीगत वस्तुओं को भी छूट प्रदान की गई है। प्राधिकारी मानते हैं कि इस समिस्डी कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

(v) कार्यक्रम 25 – मशीनरी उपकरण और कलपुर्जों पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट

क. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध

96. इस स्कीम के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

97. जीओएम द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने बताया है कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत जीओएम ने सीमा शुल्क (छूट) आदेश 2017 जारी किया था, जिसके अन्तर्गत उक्त आदेश में प्रदत्त अनुसूची में सूचीबद्ध पात्र विनिर्माता उस समय सीमा शुल्क से छूट के पात्र हैं जब वे कतिपय वस्तुओं का आयात करें।

98. अनुसूची के भाग I के क्रम सं. 112 में प्रमुख सीमा शुल्क थेट्र ("पीसीए") में विनिर्माताओं को सीमा शुल्क से छूट दी गई है जो मलेशियाई निवेश विकास प्राधिकरण ("एमडीए") द्वारा समर्पित है। ऐसी छूट मशीनरी और उपकरण के आयात पर उपलब्ध है जिसे राजकोष महासचिव द्वारा अनुमोदित किया गया है।

99. यह दावा किया गया है कि कार्यक्रम सामान्य प्रकृति के हैं। ये किसी उद्यम या उद्यम समूह या किसी उद्योग या उद्योग समूह या थेट्र के लिए विशिष्ट नहीं हैं। पीसीए में स्थिति कोई उत्पादक जो मिडा द्वारा समर्थित हो और मशीनरी और उपकरण का आयात/स्थानीय खरीद करना चाहता हो, इस शर्त के अधीन यह छूट प्राप्त कर सकता है कि वस्तुएं उस श्रेणी की हैं जिसे राजकोष महासचिव ने अनुमोदित किया गया है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

100. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीमा शुल्क (छूट) आदेश 2017 मशीनरी और उपकरण के आयात/खरीद पर ऐसे पात्र उत्पादकों को आयात शुल्क से छूट देता है, जिन्हें राजकोष महासचिव द्वारा अनुमोदित किया गया है।

101. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीमा शुल्क (छूट) आदेश 2017 के अन्तर्गत प्रदत्त छूट गंवाए गए ऐसे राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में विनिर्माता अंशदान प्रदान करती है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह केवल कतिपय प्राप्त विनिर्माताओं पर लागू है। यह कार्यक्रम अनुमति प्राप्त शुल्क प्रेषण कार्यक्रम भी नहीं है क्योंकि पूँजीगत वस्तुओं और मशीनरी को छूट प्रदान की गई है और इसलिए यह ऐसीसीएम करार के फुटनोट 1 में शामिल नहीं है। प्राधिकारी मानते हैं कि इस समिस्डी कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

(vi) कार्यक्रम 29- ओलियो व्युत्पत्तियों के उत्पादन के संबंधन हेतु अनुदान

क. याचिकाकर्ता द्वारा किया गया अनुरोध

102. याचिकाकर्ता द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

103. जीओएम द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि निष्पादन और प्रबंधन डिलीवरी इकाई ("पेमांडु"), प्रधान मंत्री विभाग द्वारा प्रदत्त एक अनुदान है, जो आर्थिक कायाकल्प कार्यक्रम ("ईटीपी") के अनुपालन में है, जो जीओएम का एक आर्थिक विकास कार्यक्रम है। ईटीपी का एक उद्देश्य वृद्धि के कतिपय थेट्रों में निवेश और सहायता को वरीयता देना है। वृद्धि के 12 थेट्र हैं अर्थात् राष्ट्रीय मुख्य आर्थिक थेट्र (एनकेर्इए) हैं जिनकी पहचान की गई है। एक एनकेर्इए "पॉम ऑयल" भी है। एनकेर्इए के अन्तर्गत ईटीपी में एक कार्य-बिंदु के रूप में पोलियो व्युत्पत्तियों के उत्पादन को बढ़ावा देने की पहचान की है।

104. पोलियो केमिकल उत्पादकों को ईटीपी के अन्तर्गत अनुदान दिया गया है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

105. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम आर्थिक कायाकल्प नीति के तहत अनुदान प्रदान करता है। यह अनुदान संबद्ध वस्तु के विनिर्माताओं के लिए उपलब्ध है क्योंकि पाँम ऑयल 12 अभिज्ञात राष्ट्रीय मुख्य आर्थिक थेट्रों में से

एक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता द्वारा, वित्तीय अंशदान द्वारा, क्षमता निर्माण के लिए परियोजनाओं में निवेश द्वारा संबद्ध वस्तु के उत्पादन को बढ़ावा देना है।

106. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम “वित्तीय अंशदान” प्रदान करता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह केवल 12 अभिज्ञात राष्ट्रीय प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में से एक के अन्तर्गत आने वाली कंपनी पर लागू है। अतः प्राधिकारी, इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन योग्य मानते हैं। मैसर्स केएलके ओलियो एसडीएन.बीएचडी को इस स्कीम के अन्तर्गत अनुदान मिला है।
107. प्राधिकरण नोट करते हैं कि ऊपर जांच की गई योजनाओं के अलावा, प्राधिकरण ने प्रकटीकरण विवरण जारी करते समय कुछ अन्य योजनाओं के तहत सब्सिडी की गणना की थी। प्रकटीकरण विवरण पर किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि अंतिम रूप से निर्धारित मार्जिन या तो ऋणात्मक या ऋणात्मक थे, इसलिए, प्राधिकरण ने सब्सिडी मार्जिन निर्धारण के लिए उन योजनाओं पर विचार नहीं किया है।

मलेशिया से उत्पादक/निर्यातक

एफपीजी ओलियोकेमिकल्स एसडीएन बीएचडी, मलेशिया और प्रोक्टर और गैम्बल इंटरनेशनल आपरेशंस एसए सिंगापुर (एफपीजी ग्रुप)

108. एफपीजी ओलियोकेमिकल्स एसडीएन बीएचडी(एफपीजी) भारत में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है, उसने संबंधित व्यापारी प्रोक्टर और गैम्बल इंटरनेशनल आपरेशंस एसए सिंगापुर (पीजीआईओ) के ज़रिए भारत को निर्यात किया है। यह नोट किया गया है कि एफपीजी मुख्य रूप से घरेलू तौर पर खरीदे गए सीपीकेओ का प्रयोग संबद्ध वस्तु के विनिर्माण में करता है। इसके अलावा, उसने संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए स्थानीय रूप से खरीदे गए आरबीडीपीकेओ और आयातित सीपीकेओ/आरबीडीपीकेओ का प्रयोग किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि स्थानीय रूप से खरीदी गई निविष्टियों से प्राप्त लाभ संबद्ध वस्तु के उत्पादन में प्रयोग की सीमा तक प्रतिसंतुलन योग्य है। एफपीजी ग्रुप के लिए निर्धारित सब्सिडी मार्जिन निम्नानुसार है:

कार्यक्रम	सब्सिडी मार्जिन %	रेंज
एलटीएआर पर सीपीकेओ	***	10-15%
कच्ची सामग्री पर बिक्री कर से छूट	***	0-5%
एलटीएआर पर प्राकृतिक गैस	***	0-5%
अधिमानी ऋण दरें	***	0-5%
सब्सिडी %	***	10-15%

* एफपीजी द्वारा कोई निर्यात सब्सिडी नहीं ली गई

केएल-केपोंग ओलियोमास एसडीएन. बीएचडी, मलेशिया (केएलके ग्रुप)

109. केएल-केपोंग ओलियोमास एसडीएन. बीएचडी (केएलके) संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक/निर्यातक है। भारत को सीधे निर्यातों के अलावा उसने असंबंधित व्यापारी यूनिलीवर एशिया प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर (“यूएपीएल”) के जरिए भी निर्यात किया है। केएलके ने दावा किया है कि उसे जीओएम से अनुदान मिला है। यह भी नोट किया जाता है कि केएलके ने स्थानीय रूप से खरीदे गए तथा आयातित आरबीडीपीकेओ, फैटी एसिड और स्पिलट पॉम करनेल फैटी एसिड के प्रयोग से संबद्ध वस्तु का उत्पादन किया है। प्राधिकारी एलटीएआर पर कच्ची सामग्री की स्थानीय खरीद पर लिए गए लाभ को प्रतिसंतुलन योग्य मानते हैं। केएलके समूह के लिए निर्धारित सब्सिडी मार्जिन निम्नानुसार है:

कार्यक्रम	सब्सिडी मार्जिन (%)	रेंज
एलटीएआर पर सीपीकेओ	***	10-15%
एलटीएआर पर प्राकृतिक गैस	***	0-5%

मशीनरी उपकरण के आयातों पर शुल्क और बिक्री कर से छूट	***	0-5%
निर्यातों के लिए दोहरी कटौती	***	0-5%
कच्ची सामग्री/पैकिंग सामग्री पर बिक्री कर से छूट	***	0-5%
ओलियो व्युत्पन्नियों के उत्पादन के संवर्धन हेतु अनुदान	***	0-5%
निर्यात सब्सिडी		
निर्यातों पर दोहरी कटौती	***	0-5%
सब्सिडी %	***	5-15%

एडेनोर ओलियोकेमिकल्स (एम) एसडीएन.बीएचडी. (पूर्ववर्ती, ऐमेरी ओलियोकेमिकल्स (एम) एसडीएन बीएचडी) और एडेनोर ओलियोकेमिकल्स रिका (एम) एसडीएन. बीएचडी. (पूर्ववर्ती, ऐमेरी ओलियोकेमिकल्स रिका (एम) एसडीएन.बीएचडी)

110. एडेनोर ओलियोकेमिकल्स (एम) एसडीएन.बीएचडी. ("ईओएम") भारत में संबद्ध वस्तु का उत्पादक-निर्यातक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ईओएम घरेलू रूप से उत्पादित सीपीकेओ के प्रयोग से संबद्ध वस्तु का उत्पादन करता है। इसके अलावा, यह नोट किया गया है कि उसने अन्य स्कीमों के तहत भी लाभ लिया है। एडेनोर ओलियोकेमिकल्स रिका (एम) एसडीएन. बीएचडी. ("रिका") ईओएम की एक संबंधित कंपनी है जो संबद्ध वस्तु का उत्पादन करती है। तथापि, रिका ने पीओआई के दौरान भारत को पीयूसी का निर्यात नहीं किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि ईओएम ने पीओआई के दौरान भारत को पीयूसी की काफी कम मात्रा का निर्यात किया है। ईडनॉर समूह के महत्वहीन निर्यात पर विचार करते हुए, पीयूसी (सी10 को छोड़कर) पर लगाए गए एंटी-डंपिंग शुल्क की समानांतर निर्णयिक समीक्षा जांच में, प्राधिकरण ने अंतिम जांच परिणाम दिनांक 02.02.2023 के द्वारा उक्त समूह के लिए अलग-अलग मार्जिन निर्धारित नहीं किया। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने एडेनॉर ग्रुप के लिए व्यक्तिगत सब्सिडी और क्षति मार्जिन का निर्धारण नहीं किया है।

अन्य

मलेशिया के लिए सब्सिडी कार्यक्रमों का सारांश

111. मलेशिया से सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क सहयोगी पक्षकारों के लिए उनके द्वारा प्राप्त सब्सिडियों हेतु और अन्य सब्सिडी कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उच्चतम सब्सिडी मार्जिन के अनुसार निर्धारित किया गया है।

कार्यक्रम सं.	अनुदान/कार्यक्रम का नाम	सब्सिडी मार्जिन (%)	रेंज % (%)
कार्यक्रम सं.1	पर्याप्त से कम मूल्य पर सीपीकेओ का प्रावधान	***	10-15%
कार्यक्रम सं.23	एलटीएआर पर प्राकृतिक गैस और बिजली के प्रावधान की स्कीम	***	0-5%
कार्यक्रम सं.24	कच्ची सामग्री/पैकिंग सामग्री पर बिक्री कर से छूट	***	0-5%
कार्यक्रम सं.25	मशीनरी, उपकरण और कलपुर्जों पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट	***	0-5%
कार्यक्रम सं. 29	ओलियो व्युत्पन्नियों के उत्पादन के संवर्धन हेतु अनुदान	***	0-5%
कार्यक्रम सं. 31	अधिमानी ऋण	***	0-5%
निर्यात सब्सिडी			

कार्यक्रम सं.17	निर्यात संवर्धन के लिए दोहरी कटौती	***	0-5%
	कुल	***	10-20%

थाइलैंड सरकार ("जीओटी")

112. थाइलैंड के लिए अभिज्ञात स्कीमों की सूची

- i. कार्यक्रम 1 कद्दी सामग्री की कीमतों के विनियमन संबंधी स्कीम
- ii. कार्यक्रम 2 पॉम ऑयल डाउनस्ट्रीम उद्योगों से संबंधित जैव – अर्थव्यवस्था नीति के अन्तर्गत स्कीम
- iii. कार्यक्रम 3 निवेश संवर्धन स्कीमें
- iv. कार्यक्रम 4 उत्पाद निर्यात संवर्धन के लिए स्कीमें (ऋण बीमा)
- v. कार्यक्रम 5 कर प्रतिपूर्ति या निर्यात पर कूपन
- vi. कार्यक्रम 6 शुल्क ड्राइवैक

च.5 याचिकाकर्ता द्वारा आरोपित सब्सिडी कार्यक्रमों की जांच

(i) कार्यक्रम सं. 1 और 2 -एलटीएआर पर कद्दी सामग्री और फैटी एल्कोहल तथा जैव-अर्थव्यवस्था नीति का निर्यात संवर्धन

क. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध

113. थाइलैंड ऑयल पॉम बोर्ड (दि "टीओपीबी") औसतन प्रत्येक वर्ष 15 मिलियन टन पॉम ऑयल के उत्पादन की कड़ी निगरानी और नियंत्रण करता है। अधिक उत्पाद परियोजना को कम करने के लिए पॉम ऑयल निर्यात बढ़ावा 2021 ("निर्यात प्रोत्साहन परियोजना") पाम आयल के उत्पादों के निर्यात को सब्सिडी देने के लिए डिजाइन किया गया था। "उप समिति" द्वारा यह प्रबंधित है जिसने 21.10.2019 को घोषित किया कि कोई न्यायिक व्यक्ति जिसका मुख्य व्यापार पॉम आयल या पॉम ऑयल उत्पादों के निर्माण, प्रयोग, बिक्री, भंडारण हो, सरकार से अतिरिक्त सहायता के लिए पात्र है।

114. दिनांक 07.06.2021 "दूसरी घोषणा" ने प्रदृढ़ लाभों को आगे बढ़ाया और दिसंबर, 2021 में और अधिक लाभों की अधिकारिक घोषण होने की उम्मीद थी। जैव-अर्थव्यवस्था केवल एक सामान्य अवधारणा/विज्ञन है जिसे जैव अर्थव्यवस्था के संवर्धन के लिए एक स्वतंत्र स्कीम के बजाए बारहवीं राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास योजना (2017-21) और जैव विविधता – आधारित अर्थव्यवस्था विकास कार्य-दांचा (2017-36) में शामिल किया गया है।

ख. थाइलैंड सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

115. इस स्कीम से संबंधित कोई विनियम या कानून नहीं है। इस स्कीम का उद्देश्य कद्दी सामग्री के निर्यात को बढ़ाना है और इसलिए एसएफए उत्पादकों को कोई लाभ नहीं मिला है।

क. प्राधिकारी द्वारा जांच

116. प्राधिकारी पाते हैं कि यह स्कीम पॉम ऑयल और उसकी उत्पत्तियों के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए केवल जीओटी की एक नीति है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के संबंध में इस स्कीम के प्रचालन के बारे में रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य नहीं रखा गया है। अतः प्राधिकारी ने इसकी विस्तार से जांच नहीं की है और तदनुसार इस स्कीम के प्रतिसंतुलन का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

(ii) कार्यक्रम सं. 3 – निवेश संवर्धन स्कीम

क. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध

117. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि जीओटी द्वारा प्रस्तावित निवेश संवर्धन प्रोत्साहन विभिन्न कारकों के आधार पर अलग-अलग होते हैं, जिनमें शामिल हैं (i) संवर्धित कार्यकलाप का प्रकार, (ii) परियोजना का स्थान और (iii) विशेष निवेश संवर्धन नीतियों की पात्रता। कतिपय व्यापार कार्यकलाप अतिरिक्त प्रोत्साहन हेतु आवेदन के लिए पात्र हो सकते हैं जिन पर परियोजना के तथ्यों, अनुसंधान और विकास ("आरएंडडी") में निवेश और परियोजना में उन्नत प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर विचार किया जाता है।

118. निवेश बोर्ड द्वारा प्रस्तावित दो मुख्य निवेश संवर्धन प्रोत्साहन के प्रकार कर प्रोत्साहन और गैर-कर प्रोत्साहन हैं। कर प्रोत्साहन में शामिल हैं:

- (i) 10 वर्ष तक की अवधि के लिए संवर्धित उत्पाद की विक्री से प्राप्त लाभ पर कारपोरेट आयकर ("सीआईटी") से छूट;
- (ii) संवर्धित परियोजना में प्रयुक्त मशीनरी पर आयात शुल्क से छूट; और
- (iii) निर्यात के लिए विनिर्मित उत्पादों में प्रयुक्त कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क से छूट।

119. गैर कर-प्रोत्साहन में शामिल हैं:

- (i) निवेश अवसरों के अध्ययन के प्रयोजनार्थ विदेशियों को थाइलैंड में प्रवेश की अनुमति;
- (ii) विदेशी कुशल कामगारों और विशेषज्ञों को थाइलैंड में प्रवेश और संवर्धित व्यापार में कार्य करने की अनुमति;
- (iii) विदेशी के लिए संवर्धित व्यापार के प्रचालन हेतु भूमि के स्वामित्व की अनुमति; और
- (iv) विदेशी मुद्रा में थाइलैंड से बाहर धन भेजने या प्रेषित करने की अनुमति।

120. प्राधिकारी ने पूर्व जांचों में इस स्कीम को प्रतिसंतुलित किया था।

ख. थाइलैंड सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

121. इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसी कतिपय आयातित मशीनरी पर आयात शुल्क से छूट देकर निवेश संवर्धन अधिनियम (आईपीए) की धारा 28 के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने की हकदारी के लिए कंपनी को सुविधा पहुंचाना है, जिनकी निवेश बोर्ड (बीओआई) – संवर्धित परियोजनाओं के लिए जरूरत है।

122. ऐसी कंपनियां जो बीओआई निवेश संवर्धन के लिए आवेदन करना चाहती हैं, को प्रत्येक परियोजना के लिए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि परियोजना अनुमोदन मापदंडों को पूरा करती है तो बीओआई एक पैकेज के रूप में अधिकार और लाभ प्रदान करेगा। बीओआई निवेश संवर्धन प्रोत्साहन कार्यक्रम आधार पर प्रदान नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, बीओआई कार्यक्रम-वार प्रोत्साहन प्रदान नहीं करता है बल्कि हकदार कंपनियों को आईपीए लाभों का एक पैकेज देता है। तथापि, जब (या यदि) कोई बीओआई-संवर्धित कंपनी आईपीए पैकेज के अधीन प्रदत्त विशेष लाभ का उपयोग करने का वास्तव में निर्णय लेती है तो कंपनी को एक लाभ के उपयोग के लिए अलग से अनुरोध प्रस्तुत करना होगा। थाई फैटी एल्कोहल कंपनी लिमिटेड (टीएफए) ने संबंध वस्तु के उत्पादन के लिए बीओआई निवेश संवर्धन हेतु आवेदन किया है कि यद्यपि वह कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र था, तथापि वर्ष के दौरान टीएफए द्वारा कोई लाभ नहीं लिए गए हैं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

123. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निवेश संवर्धन अधिनियम, 2002 (अधि.) संवर्धित कंपनियों/परियोजनाओं/कार्यकलापों को कतिपय अधिकार और लाभ प्रदान करता है (निवेश संवर्धन पैकेज स्कीम)। अधिनियम की धारा 16 में विहित है कि निवेश बोर्ड (बीओआई) अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लाभ के लिए पात्र निवेश कार्यकलापों के प्रकार और आकार की घोषणा करेगा।

124. अधिनियम की धारा 28 अनुमोदित निवेश परियोजनाओं के अन्तर्गत मशीनरी पर आयात शुल्क के भुगतान से छूट देती है और मशीनरी पर आयात शुल्क में कटौती नहीं करती है। अधिनियम की धारा 30 कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क से कटौती (90 प्रतिशत से अधिक नहीं) प्रदान करती है और मशीनरी पर आयात शुल्क से छूट/कटौती के लिए नहीं है।

125. यह कार्यक्रम गंवाए गए राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इस प्रकार लाभ मिला है। सबसिडी भी विशिष्ट है क्योंकि वह संवर्धित कार्यकलाप करने वाले संवर्धित उद्यम तक सीमित है। अतः, प्राधिकारी कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन योग्य मानते हैं।

(iii) कार्यक्रम सं. 4 - ऋण बीमा

क. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध

126. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ थाइलैंड ("एक्जिम थाइलैंड") वित्त मंत्रालय के पर्यवेक्षण के अधीन थाइलैंड देश के स्वामित्व वाला एक विशेष वित्तीय संस्थान है, जिसे राष्ट्रीय विकास के प्रयोजनार्थ थाई निर्यात, आयात और निवेश को गारंटी प्रदान करके, ऋण सुविधाएं और जोखिम के विरुद्ध बीमा प्रदान करके संवर्धन और सहायता के लिए डिजाइन किया गया है।

127. एक्जिम थाइलैंड अल्पावधिक तथा मध्य और दीर्घावधिक निर्यात ऋण बीमा का प्रस्ताव करता है (अर्थात् निर्यातकों को भुगतान न होने के जोखिम के विरुद्ध विदेशी प्राप्तियों से संरक्षण की सुविधा)।

128. एक्जिम थाइलैंड एसएमई और बड़े कारपोरेट निर्यातकों दोनों के लिए अनेक अल्पावधिक निर्यात ऋण बीमा नीतियां प्रदान करता है, जिनके द्वारा लेन-देन पर भुगतान के निबंधन नौवहन की तारीख के बाद 180 दिन से अधिक नहीं होने चाहिए। अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा विदेशी व्यापार लेन-देन जैसे वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात से संबंधित वाणिज्यिक और राजनैतिक दोनों घाटों के कारण भुगतान में चूक को कवर करता है। वाणिज्यिक घाटों के लिए क्षतिपूर्ति दर घाटे के 85 से 90 प्रतिशत तक है और राजनैतिक घाटों के लिए क्षतिपूर्ति दर घाटे के 90 प्रतिशत तक है। नीतियों में शामिल हैं:

- (i) एसएमई के लिए एक्जिम
- (ii) एक्जिम फ्लैक्सी
- (iii) एक्जिम स्प्रो
- (iv) एक्जिम स्मार्ट बीमा

अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा की तरह मध्यावधि और दीर्घावधि निर्यात ऋण बीमा विदेशी व्यापार सौदों से संबंधित वाणिज्यिक और राजनैतिक घाटों के कारण भुगतान में चूक को कवर करता है।

ख. थाइलैंड सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

129. निर्यात ऋण बीमा सुविधाएं निर्यातकों को भुगतान न होने के जोखिम के विरुद्ध विदेशी प्राप्तियों से संरक्षण की सुविधा देती है। यदि विदेशी क्रेता द्वारा भुगतान में चूक होती है तो एक्जिम थाइलैंड बीमा पालिसी में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार घाटे की भरपाई करता है।

130. संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों ने इस स्कीम के तहत कोई लाभ नहीं लिया है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

131. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम भुगतान न होने के जोखिम के विरुद्ध निर्यातकों को निर्यात ऋण बीमा प्रदान करता है। तथापि, चूंकि संबद्ध वस्तु के एकमात्र उत्पादक ने इस कार्यक्रम का लाभ नहीं लिया है, इसलिए प्राधिकारी ने इसे स्कीम की विस्तार से जांच नहीं की है।

(iv) कार्यक्रम सं. 5 - कर क्षतिपूर्ति और कूपन

क. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध

132. कर प्रतिपूर्ति निर्यात के लिए थाइलैंड में उत्पादित वस्तुओं की उत्पादन लागत को कम करने का एक उपाय है। यह प्रतिपूर्ति कतिपय मापदंडों और शर्तों के अधीन है तथा टैक्स एंड छ्यूटी कम्पनसेशन ऑफ एक्सपोर्टड गुड्स प्रोड्युस्ड इन दि किंडम एक्ट, बी.ई. 2524 (1981) के अन्तर्गत केवल पात्र उद्योगों को उपलब्ध है।

133. कर प्रतिपूर्ति निर्यात के लिए एफओबी कीमत और निर्यातित वस्तुओं के प्रत्येक प्रकार पर लागू दर के अनुसार निर्धारित की जाती है और कर कूपन के रूप में उसकी प्रतिपूर्ति होती है। कैटी एल्कोहल के निर्यात इस स्कीम के अन्तर्गत कर प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं।

ख. थाइलैंड सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

134. वित्त मंत्रालय ("एमओएफ") और थाई सीमा शुल्क विभाग निर्यातकों के लिए कर कूपन प्रणाली का प्रशासन करता है। टैक्स एंड ड्यूटी कम्पनसेशन ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स प्रोड्युस्ट इन दि किंगडम एक्ट 1981 के अन्तर्गत प्राधिकृत है। किसी कर कूपन का मूल्य किसी कंपनी की निर्यातित वस्तु के एफओबी मूल्य द्वारा उत्पाद विशिष्ट कूपन दर के गुणन द्वारा परिकलित किया जाता है। किसी विशेष निर्यातित वस्तु के लिए कूपन की दर ज्ञात करने हेतु एमओएफ निर्यातित वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्री और अन्य निविष्टियों के लिए प्रदत्त आयात शुल्कों और अप्रत्यक्ष कर की जांच करता है। कर कूपन प्रणाली निर्यातित वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों और अन्य निविष्टियों के लिए प्रदत्त आयात शुल्क और अप्रत्यक्ष कर को रिफंड करती है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

135. यह कार्यक्रम टैक्स एंड ड्यूटी कम्पनसेशन ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स प्रोड्युस्ट इन दि किंगडम एक्ट, बी.ई. 2524 (1981) के अनुपालन में स्थापित है और 15 अगस्त, 1981 को लागू हुआ। इस सम्बिडी कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्यातित वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्री और अन्य निविष्टियों के लिए आयात शुल्क और अप्रत्यक्ष कर के भुगतान को वापस किया जाता है।

136. इस कार्यक्रम के प्रशासन के लिए, वित्त मंत्रालय और थाई सीमा शुल्क विभाग निर्यातकों हेतु कर कूपन प्रणाली का प्रशासन करता है। किसी कर कूपन का मूल्य किसी कंपनी की निर्यातित वस्तु के एफओबी मूल्य द्वारा उत्पाद विशिष्ट कूपन दर के गुणन द्वारा परिकलित किया जाता है। किसी विशेष निर्यातित वस्तु के लिए कूपन की दर निर्यातित वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्री और अन्य वस्तुओं पर प्रदत्त आयात शुल्क और अप्रत्यक्ष कर द्वारा निर्धारित होता है। निर्यातक कंपनी भी कारपोरेट आयकर के तहत क्रेडिट के रूप में कर कूपन का प्रयोग कर सकती है।

137. प्राधिकारी नोट करते हैं कि थाइलैंड सरकार ने कोई साक्ष्य नहीं दिया है या यह सुनिश्चित करने के लिए किसी तंत्र की मौजूदगी सिद्ध नहीं की है कि कर कूपन का मूल्य निर्यातित वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्री पर प्रदत्त आयात शुल्कों और अन्य कर की राशि से अधिक नहीं होता है। अतः यह कार्यक्रम गंवाए गए राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान देता है और इस प्रकार लाभ दिया गया है। यह कार्यक्रम विशिष्ट माना गया है क्योंकि यह निर्यातों से संबंधित है।

138. प्राधिकारी पाते हैं कि एकमात्र उत्पादक/निर्यातक मैसर्स थाई फैटी एल्कोहल्स कंपनी लिमिटेड ने संबद्ध वस्तु के निर्यातों पर लाभ लिया है। अतः प्राधिकारी उक्त स्कीम के तहत प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लागू करना चाहते हैं।

(v) कार्यक्रम सं. 6 – सीमा शुल्क कानून की धारा 19 के अन्तर्गत शुल्क ड्राईवैक

क. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध

139. याचिकाकर्ता अनुरोध करता है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्यातक कंपनियों को आयातित वस्तुओं पर प्रदत्त सीमा शुल्क की वापसी होती है, जहां ऐसी वस्तुओं को उत्पादित, मिश्रित, संयोजित या पैकिंग और उसके बाद निर्यातित किया जाएगा।

ख. थाइलैंड सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

140. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत शुल्क ड्राईवैक का अर्थ आयातों पर दी गई गारंटी या पहले से प्रदत्त आयात शुल्क की वापसी है जो उत्पादन, मिश्रण, संयोजन या पैकिंग और उसके बाद निर्यात की गई हैं।

141. शुल्क ड्राईवैक के लिए पात्र वस्तुएँ हैं:

- कच्ची सामग्रियां जो स्पष्ट रूप से निर्यात में देखी जाती हैं, उदाहरण के लिए फैब्रिक, बटन, जीपर और परिधान में धागे, प्लास्टिक उत्पादों में प्लास्टिक शीट आदि।
- विनिर्माण प्रक्रिया और निर्यात में सीधे शामिल प्रयुक्त ऐसी कच्ची सामग्रियां जो स्पष्ट रूप से नहीं दिखती हैं, उदाहरण के लिए डिब्बाबंद खाद्य में पिजरवेटिव, परिधानों में स्टीफनी एजेंट, सेलफोन में ग्लू के लिए साल्वेट और इलैक्ट्रोनिक सर्किट में जंगरोधी एजेंट आदि।
- विनिर्माण प्रक्रिया में अपेक्षित कच्ची सामग्रियां जैसे वस्त्र उत्पादों में प्रयुक्त आकार सामग्री और ब्लीचिंग एजेंट, सेंड पेपर, स्कोरिंग पाउडर, वार्निंग, वैलवेट, स्कोरिंग एजेंट, चाक, कार्बन पेपर और पैटर्न।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

142. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 29 शुल्क ड्राबैक का प्रावधान करती है। सब्सिडी कार्यक्रम कद्दी सामग्री पर प्रदत्त आयात शुल्क की वापसी करता है जिनका उत्पादन, मिश्रण, संयोजन या पैकिंग और उसके बाद निर्यात किया गया है। प्राधिकारी ने सूचना मांगी है कि क्या जीओटी यह सुनिश्चित करने के लिए कोई सत्यापन तंत्र रखता है कि प्रदत्त शुल्क ड्राबैक निर्यात उत्पादन के लिए आवश्यकता से अधिक न हो। तथापि, प्राधिकारी के समक्ष ऐसे तंत्र के बारे में कोई साक्ष्य नहीं है जो यह सुनिश्चित करता हो कि आयात शुल्क का कोई अधिक प्रेषण नहीं हुआ है और यह कि शुल्क ड्राबैक की राशि निर्यातित वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त कद्दी सामग्री पर प्रदत्त शुल्क की राशि से अधिक नहीं हागी।

143. इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सब्सिडी कार्यक्रम गंवाए गए राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान देता है और इस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। यह सब्सिडी कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यात पर आधारित है। अतः प्राधिकारी इस सब्सिडी कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन योग्य मानते हैं।

अन्य कार्यक्रम

(vi) अधिमानी ऋण दर

क. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध

144. याचिकाकर्ता द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ख. थाइलैंड सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

145. पूरक प्रश्नावली के उत्तर में थाइलैंड सरकार ने औसत ऋण दरों तथा ग्लोबल ग्रीन केमिकल्स पब्लिक कंपनी ("जीजीसी") को सरकारी बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण के ब्यौरे, कद्दी सामग्री आपूर्ति और थाइलैंड में एसएफए के एकमात्र उत्पादक अर्थात् थाई फैटी एल्कोहल कंपनी लिमिटेड की कंपनी धारिता के ब्यौरे प्रदान किए हैं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

146. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक सरकारी बैंक द्वारा लागू ऋण दरों की तुलना में काफी कम दर पर जीजीसी को ऋण दिया गया है। यह कार्यक्रम गंवाए गए राजस्व (प्रदत्त ब्याज की कम दर) के रूप में वित्तीय अंशदान देता है। बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज और जीओटी द्वारा उसके उत्तर में प्रदत्त लागू ब्याज दर के बीच अंतर के रूप में प्राप्तकर्ता को लाभ मिला है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि रियायती ऋण दर केवल विशिष्ट कंपनी के लिए लागू है। अतः, प्राधिकारी कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन योग्य मानते हैं।

थाई फैटी एल्कोहल कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड और ग्लोबल ग्रीन केमिकल पब्लिक कं. लिमि. थाइलैंड टीएफए

147. थाई फैटी एल्कोहल कंपनी लिमिटेड (टीएफए) भारत में संबद्ध वस्तु का उत्पादक-निर्यातक है। ग्लोबल ग्रीन केमिकल्स पब्लिक कंपनी (जीसीसी) टीएफए की धारक कंपनी है। यह नोट किया गया है कि जीसीसी भी टीएफए को कद्दी सामग्री का आपूर्तिकर्ता है। टीएफए ने कर प्रतिपूर्ति तथा शुल्क ड्राबैक प्राप्त करना स्वीकार किया है। यह दावा किया गया है कि ड्राबैक एएससीएम के अनुच्छेद 1 के फुटनोट 1 के अनुसार प्रतिसंतुलन योग्य नहीं है। प्राधिकारी ने पूरक प्रश्नावली के उत्तर में टीएफए तथा जीओटी दोनों से यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए सत्यापन तंत्र संबंधी सूचना मांगी थी कि आयात प्रभारों से अधिक प्रेषण नहीं हुआ है। तथापि, ऐसे सत्यापन तंत्र का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में जीओटी द्वारा प्रदत्त किसी सत्यापन तंत्र के किसी साक्ष्य के अभाव में संपूर्ण ड्राबैक राशि को सब्सिडी के रूप में नोट किया था। तथापि, प्रकटन के बाद भागीदार निर्यातक (टीएफए) ने यह सिद्ध करने के लिए विस्तृत कार्यकरण प्रस्तुत किया था कि उन्हें कोई अधिक प्रेषण नहीं मिला है। प्राधिकारी ने भागीदार निर्यातक के अनुरोध पर विचार किया है और ड्राबैक स्कीम के अन्तर्गत सब्सिडी की राशि पुनः निर्धारित की है। अतः प्राधिकारी, इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन योग्य मानते हैं। टीएफए समूह के लिए निर्धारित सब्सिडी मार्जिन निम्नानुसार है:

कार्यक्रम	सब्सिडी मार्जिन %	रेंज
निवेश संवर्धन अधिनियम के अधीन घूट	***	0-5%

अधिमानी ऋण	***	0-5%
निर्यात सब्सिडी		
शुल्क ड्राईवैक	***	0-10%
कर क्षतिपूर्ति या निर्यात कूपन	***	0-5%
सब्सिडी %	***	0-10%

थाइलैंड के लिए सब्सिडी कार्यक्रमों का सारांश

148. थाइलैंड से सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क उपलब्ध तथ्यों और टीएफए के सब्सिडी मार्जिन के आधार पर निर्धारित किया गया है।

कार्यक्रम	सब्सिडी मार्जिन %	रेज
निवेश संवर्धन अधिनियम के अधीन छूट	***	0-5%
अधिमानी ऋण	***	0-5%
निर्यात सब्सिडी		
शुल्क ड्राईवैक	***	0-10%
कर क्षतिपूर्ति या निर्यात कूपन	***	0-5%
सब्सिडी %	***	0-10%

ज. क्षति आकलन और कारणात्मक संबंध

ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

149. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- क) इंडोनेशिया सरकार ने प्रमुख कच्ची सामग्री (कच्चा पाँप करनेल तेल) पर दिसंबर, 2020 से निर्यात कर में काफी वृद्धि कर दी है। वृद्धि का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि सितंबर, 2020 में शून्य के मुकाबले सितंबर, 2021 में सीपीकेओ के निर्यात पर लगभग 400 अम.डा. प्रति एमटी के निर्यात कर का भुगतान किया गया था। निर्यात कर में वृद्धि इंडोनेशिया में घरेलू विनिर्माताओं के लिए कच्ची सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्राथमिक उद्देश्य से की गई है और यह कि यह आपूर्ति उन्हें विश्व बाजार कीमतों से कम पर उपलब्ध हो। यह नोट किया जा सकता है कि सीपीकेओ संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत का 70 प्रतिशत से अधिक है, इसलिए केवल इस सब्सिडी से उनकी उत्पादन लागत में काफी कमी आई है।
- ख) इंडोनेशिया की नकल करते हुए, मलेशिया सरकार ने भी सीपीकेओ के निर्यात पर निर्यात कर को दिसंबर, 2020 में 0 प्रतिशत से बढ़ाकर जनवरी 2021 में 10 प्रतिशत कर दिया है। उक्त निर्यात कर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मलेशिया के घरेलू उत्पादकों को कम कीमत पर सीपीकेओ की आपूर्ति होती रहे ताकि वे इंडोनेशिया की सब्सिडी प्राप्त उत्पादन लागत की बराबरी कर सकें।
- ग) इस तथ्य को देखते हुए कि मलेशिया और इंडोनेशिया के पास वैश्विक सीपीकेओ के उत्पादन का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है, उक्त देशों ने निर्यात कर लागू करके वैश्विक बाजार में सीपीकेओ की उपलब्धता सीमित कर दी और अपनी विश्व बाजार कीमत को बढ़ा दिया है तथा अपने घरेलू उत्पादकों के लिए सस्ती कीमत पर सीपीकेओ की उपलब्धता भी सुनिश्चित की है। इस प्रकार, उक्त देशों में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत काफी सब्सिडी प्राप्त है और इस प्रकार यह भारतीय घरेलू उद्योग को गंभीर झंति पहुंचा रही है।

घ) क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों की बढ़ आ गई है जो आधार वर्ष की तुलना में 54 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। इसके विपरीत, याचिकाकर्ता का उत्पादन आधार वर्ष की तुलना में समान स्तर पर बना हुआ है।

इ) उत्पादन के संबंध संबद्ध आयातों में पूरी क्षति अवधि में वृद्धि हुई है और आधार वर्ष की तुलना में यह पीओआई में 154 सूचकांक बिंदुओं तक पहुंच गए हैं।

च) भारत में कुल आयातों और भारतीय मांग में संबद्ध देशों के हिस्से में पूरी क्षति अवधि में निरंतर और तीव्र वृद्धि देखी गई है। आयातों में न केवल समग्र रूप से बल्कि उत्पादन की दृष्टि से भी वृद्धि हुई है।

छ) संबद्ध वस्तु की मांग में पूरी क्षति अवधि में वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में मांग में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तथापि, मांग में संपूर्ण वृद्धि पर संबद्ध देशों के आयातों ने कब्जा कर लिया है जो आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में 30 सूचकांक बिंदुओं से अधिक बढ़ गए हैं। इसके विपरीत इसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने अपना लगभग 25 प्रतिशत बाजार हिस्सा गंवाया है।

ज) संबद्ध आयातों ने न केवल वृद्धिशील मांग पर कब्जा किया है बल्कि भारतीय उद्योग का बाजार हिस्सा भी हड्डप लिया है।

झ) घरेलू उद्योग के घाटे संबद्ध देशों से सब्सिडी प्राप्त आयातों में निरंतर वृद्धि के कारण उच्च स्तर पर बने हुए हैं।

ज) संबद्ध देशों से आयात कीमतें घरेलू कीमतों में ह्रास और न्यूनीकरण कर रही हैं।

ट) आयातों के परिणामस्वरूप कम कीमत पर भारी बिक्री हो रही है, जैसा कि क्षतिरहित कीमत और आयातों की पहुंच कीमत के बीच अंतर से स्पष्ट है।

ठ) भारतीय उत्पादकों के पास संपूर्ण घरेलू मांग को पूरा करने की क्षमता है, फिर भी, लगभग 75 प्रतिशत घरेलू मांग संबद्ध देशों से आयातों द्वारा उनकी कम कीमत के कारण पूरी की जा रही है।

ड) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और आरओआई याचिकाकर्ता द्वारा उसकी लागत में कमी और बिक्री में वृद्धि के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद निचले स्तर पर बनी हुई है।

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

150. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

क) याचिकाकर्ता ने केवल पीओआई के हिस्से (अर्थात मई, 2021 तक) के लिए आयात आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई कीमत, कीमत कटौती, कीमत ह्रास, कीमत न्यूनीकरण और क्षति मार्जिन जो पीयूसी के आयातों के बढ़ाए गए आंकड़ों पर आधारित है, उन पर क्षति विश्लेषण हेतु विचार नहीं किया जा सकता है।

ख) याचिकाकर्ता को क्षति निवेश के गलत निर्णयों के कारण हुई है। इंडोनेशिया में याचिकाकर्ता के भारी निवेश के कारण उच्च खरीद लागत और उच्च ब्याज लागत की वजह से याचिकाकर्ता को प्रतिकूल प्रभाव झेलना पड़ा है।

ग) विभिन्न उधारियों से (इंडोनेशियाई निवेश सहित) केवल ब्याज लागत के कारण निवल घाटे की स्थिति आई है। इंडोनेशियाई सरकार की अप्रत्याशित नीतियों के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को आई किसी अतिरिक्त लागत को क्षति और क्षतिरहित कीत निर्धारित करते समय शामिल नहीं किया जा सकता है।

घ) याचिकाकर्ता को क्षति कच्छ में अपने संयंत्र में किए गए निवेश के कारण भी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप 2200 रु./एमटी की अतिरिक्त लागत आई है। तत्पश्चात उक्त निवेश के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त वित्तीय लाभ वापस ले लिया गया था। 2020 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ बनाम मैसर्स वी.वी.एफ लिमिटेड [(2020) 20 एससीसी 57] मामले में निर्णय में वीवीएफ को प्रदत्त वित्तीय लाभ को संशोधित करने के भारत सरकार के निर्णय को सही माना था। इसकी वजह से याचिकाकर्ता के विरुद्ध 304 मिलियन रु. की संभावित देयता सृजित हो गई है।

ड) याचिकाकर्ता के लेखा परीक्षकों ने "चल रही कंपनी" के रूप में याचिकाकर्ता की क्षमता पर चिंताओं को नोट किया है।

च) याचिकाकर्ता इंडोनेशिया में स्थानीय उपस्थिति के ज़रिए स्वयं कच्ची सामग्री की खरीद पर प्रदत्त सब्सिडी, यदि कोई हो, का लाभ ले रहा है।

छ) कारणात्मक संबंध का अभाव है क्योंकि पीओआई के दौरान लाभप्रदता मापदंड पूर्ववर्ती वर्ष से लगभग दोगुने हो गए और संबद्ध आयातों के बावजूद आधार वर्ष के स्तर पर हैं।

ज) याचिकाकर्ता को क्षति इन्वरटेड शुल्क संरचना के कारण हुई है, अर्थात् कच्ची सामग्री (सीपीओ/सीपीकेओ) के आयातों पर 37.5 प्रतिशत का उच्च आयात शुल्क लागू है।

झ) याचिकाकर्ता के पास फीड स्टॉक पर पहुंच नहीं है और वह आयातों पर निर्भर है। इस प्रकार, उत्पादन की अव्यवहार्यता मुख्यतः कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता के कारण है।

ज) याचिकाकर्ता शुद्ध ग्रेड सी12 का विनिर्माण नहीं करता है और उसके पास सी1214 की सीमित आपूर्ति है।

ट) याचिकाकर्ता मांग में वृद्धि के बावजूद अपनी उत्पादन क्षमता और उत्पादन स्तर में वृद्धि करने में सक्षम नहीं रहा है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि याचिकाकर्ता को क्षति अपने स्वयं के कारण हुई है।

ठ) इसके अलावा, मात्रात्मक क्षति, यदि कोई हो, तो याचिकाकर्ता की स्वयं की आवद्ध खपत और निर्यातों के कारण हुई है।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

151. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से सब्सिडी प्राप्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच की है।

152. सब्सिडी नियमावली का नियम 13 क्षति के निर्धारण को शासित करने वाले सिद्धांतों से संबंधित है जिसमें निम्नानुसार व्यवस्था है:

13. क्षति का निर्धारण-

(1) निर्दिष्ट देशों से आयात के मामले में, नामित प्राधिकारी आगे यह पता लगाएगा कि भारत में इस प्रकार की सामग्री के आयात से भारत में स्थापित किसी भी उद्योग को सामग्री की क्षति होती है या खतरा होता है, या भारत में एक उद्योग की स्थापना को रोकता है।

(2) उप-नियम (3) के तहत क्षति का पता लगाया जाता है, तब अन्य बातों के साथ-साथ, नियम के अनुबंध में निर्धारित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, नामित प्राधिकारी क्षति, क्षति का खतरा, किसी उद्योग की स्थापना के लिए सामग्री की कमी और सब्सिडी के आयात और क्षति के बीच करणीय लिंक का निर्धारण करेगा।

(3) नामित प्राधिकारी, असाधारण मामलों में, उन स्थानों पर क्षति होने का परिणाम दे सकता है जहां घरेलू उद्योग का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है -

(i) वहाँ एक पृथक बाजार में सब्सिडी वाले आयात पर ध्यान केंद्रित है, और

(ii) रियायती आयात इस तरह के बाजार के भीतर लगभग सभी उत्पादन के उत्पादकों को क्षति पहुंचा रहे हैं।

153. एससीएम करार के अनुच्छेद 15.1 और सीवीडी नियमावली के अनुबंध । में इन दोनों की वस्तुनिष्ठ जांच का प्रावधान है, (क) सब्सिडी प्राप्त आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर सब्सिडी प्राप्त आयातों का प्रभाव और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव। प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या आयातों में समग्र रूप से या आयातक सदस्य में उत्पादन और खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। सब्सिडी प्राप्त आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या आयातक देश में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में सब्सिडी प्राप्त आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमत में काफी अधिक कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी अधिक बढ़ गई होती।

प्राधिकारी ने क्षति जांच पहलुओं संबंधी हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों को नोट किया है और उठाए गए मुद्दों का संगत सीमा तक इस जांच परिणाम के उचित स्थानों पर समाधान किया है।

I. सब्सिडी प्राप्त आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

i. मांग का आकलन

154. भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को सभी भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी अन्य देशों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। यह देखा गया है कि क्षति अवधि में मांग में वृद्धि हुई है। इस प्रकार आकलित मांग निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
1	घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
		प्रवृत्ति	100	126	98	92
2	अन्य उत्पादक की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
		प्रवृत्ति	100	120	119	134
3	संबद्ध देशों से आयात	एमटी	70,120	74,671	98,377	1,05,192
		प्रवृत्ति	100	106	140	150
4	अन्य देशों से आयात	एमटी	10,760	12,803	3,952	395
		प्रवृत्ति	100	119	37	4
5	कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
		प्रवृत्ति	100	113	119	122

ii. संबद्ध देश से आयात की मात्रा और आयातों का हिस्सा

155. संबद्ध आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या समग्र रूप से या भारत में उत्पादन अथवा खपत की दृष्टि से सब्सिडी प्राप्त आयातों में भारी वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा का निम्नानुसार विश्लेषण किया गया है:-

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
क	इंडोनेशिया	एमटी	18,085	27,169	46,907	55,273
ख	मलेशिया	एमटी	40,251	35,136	43,004	40,282
ग	थाइलैंड	एमटी	11,784	12,366	8,466	9,637
1	संबद्ध देश	एमटी	70,120	74,671	98,377	1,05,192
2	अन्य देश	एमटी	10,760	12,803	3,952	395
3	कुल	एमटी	80,880	87,473	1,02,329	1,05,587

156. यह देखा गया है कि:

क. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में समग्र रूप से आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में 50 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है।

ख. आयातों में 2018-19 में ***प्रतिशत से पीओआई में ***प्रतिशत तक घरेलू उद्योग के उत्पादन की दृष्टि से ज्ञाती से वृद्धि हुई है।

ग. पीओआई के दौरान, संबद्ध देशों से आयात भारत में कुल आयातों का लगभग 100 प्रतिशत है।

II. संबद्ध आयातों का कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

157. कीमत पर सब्सिडी प्राप्त आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी ने यह विचार किया है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में सब्सिडी प्राप्त आयातों द्वारा कोई भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे सब्सिडी प्राप्त आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में भारी कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी अधिक बढ़ गई होती।

i. कीमत कटौती

158. आयातों की पहुंच कीमत के साथ जांच अवधि के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना करके कीमत कटौती ज्ञात की गई है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित प्रत्येक पीसीएन के लिए अलग से और तत्पश्चात समग्र रूप से विचाराधीन उत्पाद के लिए कीमत कटौती निर्धारित की गई है। भारित औसत कीमत कटौती की गणना निम्नानुसार है:

पीओआई	मात्रा	एलवी रु./ किग्रा.	एनएसआर रु./ किग्रा.	कटौती (रु./ किग्रा.)
इंडोनेशिया	55,273	129	***	***
मलेशिया	40,282	129	***	***
थाइलैंड	9,637	139	***	***
संबद्ध देश	1,05,192	130	***	***

159. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कतिपय ग्रेडों के लिए कटौती सकारात्मक है। भारित औसत आधार पर शून्य/नगण्य कटौती हुई है। तथापि, नकारात्मक/नगण्य कटौती को इस दृष्टि से देखना अपेक्षित है कि घरेलू उद्योग की बिक्री उसकी उत्पादन लागत की तुलना में काफी कम कीमत पर हुई है और घरेलू उद्योग को घाटे में बिक्री करनी पड़ी है।

ii. कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन

160. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की क्षति रहित कीमत ज्ञात की है और उसकी तुलना कम कीमत पर बिक्री की मात्रा ज्ञात करने के लिए आयातित वस्तु के पहुंच मूल्य के साथ की है। प्रत्येक पीसीएन के लिए अलग से और उसके बाद समग्र रूप से विचाराधीन उत्पाद के लिए कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है।

जांच की अवधि	मात्रा	एलवी रु./ किग्रा.	एनआईपी रु./ किग्रा.	कम कीमत पर बिक्री रु./ किग्रा.	कम कीमत पर बिक्री %
इंडोनेशिया	55,273	129	***	***	20-30%
मलेशिया	40,282	129	***	***	20-30%
थाइलैंड	9,637	139	***	***	10-20%

161. नीचे तालिका से नोट किया गया है कि कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन सकारात्मक है जिससे पता चलता है कि आयातों ने क्षतिकारी कीमत पर घरेलू बाजार में प्रवेश किया है। सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का मूल्यांकन इस प्रकार है:-

देश	उत्पादक	एनआईपी	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
	भारित औसत	यूएसडॉ./एमटी	यूएसडॉ./एमटी	यूएसडॉ./एमटी	%	रेंज
इंडोनेशिया	पीटीआईओ	***	***	***	***	0-20%
	पीटीएमएम	***	***	***	***	5-25%
	डब्ल्यूआई	***	***	***	***	10-30%
	ईएसएम	***	***	***	***	0-10%
	अन्य	***	***	***	***	15-35%
मलेशिया	एफपीजी	***	***	***	***	0-10%
	केएलके	***	***	***	***	10-30%
	अन्य	***	***	***	***	10-30%
थाइलैंड	टीएफए	***	***	***	***	0-20%
	अन्य	***	***	***	***	0-20%

* ईओएम ने जांच की अवधि के दौरान नगण्य मात्रा में निर्यात किया है और इसलिए इसके लिए अलग से क्षति मार्जिन की गणना नहीं की गई है।

iii. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

162. यह निर्धारित करने के लिए क्या आयातों का प्रभाव कीमतों में अत्यधिक कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा हो गई होती, प्राधिकारी ने आयातों की पहुंच कीमत और घरेलू उद्योगी की लागत और कीमत में क्षति अवधि के दौरान हुए परिवर्तनों की जांच की है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
1	बिक्री लागत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	94	115
3	बिक्री कीमत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	96	115
5	पहुंच कीमत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	83	95	121

163. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत कम्बी सामग्री की लागत में भारी वृद्धि के कारण बढ़ी है। तथापि, संबद्ध आयातों के पहुंच मूल्य में कोई समतुल्य वृद्धि नहीं हुई है। पहुंच मूल्य पूरी क्षति अवधि में उत्पादन लागत से काफी कम रहा है।

III घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

164. नियमावली में अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी व्यवस्था है कि घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर

प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, जिनमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेशों पर आय या क्षमता उपयोग शामिल हैं; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता संबंधी वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तदनुसार, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन की निम्नानुसार जांच की है:

i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

165. क्षति अवधि के दौरान उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री और निर्यात के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
1	क्षमता	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	100	100	100
2	उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	112	103	100
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	112	103	100
4	घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	126	98	92
5	निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति		100	103	111	111

166. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:-

- क. घरेलू उद्योग की क्षमता और क्षमता उपयोग क्षति अवधि में समान स्तर पर रहे हैं क्योंकि वह भारतीय मांग में वृद्धि के बावजूद अपना उत्पादन बढ़ाने में असमर्थ था। बढ़ी हुई पूरी मांग को संबद्ध देशों से आयातों द्वारा पूरा कर लिया गया।
- ख. घरेलू उद्योग के पास भारी अप्रयुक्त क्षमता है तथापि वह आयातों के निरंतर कीमत दबाव के कारण अपना उत्पादन नहीं बढ़ा पाया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यद्यपि घरेलू उद्योग की क्षमताएं प्राथमिक रूप से सी1214 ग्रेड के लिए स्थापित थीं, जिसकी भारत में अधिकतम मांग है। तथापि, वर्तमान परिदृश्य में सी1214 की मांग को प्राथमिक रूप से आयातों द्वारा पूरा किया जा रहा है और सी1214 के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग बहुत मामूली है।

ii. बाजार हिस्सा

167. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग और घरेलू उत्पादकों का बाजार हिस्सा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	बाजार हिस्सा	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
1	घरेलू उद्योग की बिक्री	%	***	***	***	***
	रेंज		20-30	20-30	10-20	10-20
2	अन्य उत्पादकों की बिक्री	%	***	***	***	***
	रेंज		0-10	0-10	0-10	0-10

3	संबद्ध देश	%	59%	55%	69%	72%
	रेंज		50-60	50-60	60-70	70-80
4	अन्य देश	%	9%	9%	3%	0%
	रेंज		0-10	0-10	0-10	0-10
5	कुल मांग	%	100%	100%	100%	100%

168. संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में देश में मांग के *** प्रतिशत से *** प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है, जबकि याचिकाकर्ता के हिस्से में उसी अवधि के दौरान *** प्रतिशत से *** प्रतिशत की गिरावट आई है। यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा पीओआई में कम हुआ है जबकि संबद्ध देशों के आयातों के हिस्से में वृद्धि हुई है। अन्य देशों से आयातों के हिस्से में भी गिरावट आई है।

169. याचिकाकर्ता बड़ी हुई मांग का लाभ लेने में असमर्थ रहा है और भारी अप्रयुक्त क्षमता के बावजूद उसका उत्पादन समान स्तर पर रहा है।

iii. लाभ अथवा हानि, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

170. लाभ अथवा हानि, नकद लाभ और निवेश पर आय की दृष्टि से घरेलू उद्योग की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
1	बिक्री की लागत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	94	116
3	बिक्री कीमत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	96	115
5	लाभ/(हानि)	रु./किग्रा.	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(138)	(83)	(118)
7	लाभ/(हानि)	लाख रु.	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(173)	(83)	(106)
9	पीबीआईटी	लाख रु.	***	***	***	***
10	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(203)	(41)	(93)
11	नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
12	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(219)	(28)	(91)
13	आरओसीई	%	***	***	***	***
14	प्रवृत्ति	रेंज	(10-20)	(20-30)	(0-10)	(20-30)

171. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

क. घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए घाटे क्षति अवधि में बढ़ गए हैं। घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से सस्ते आयातों के कारण निरंतर घाटे में है। घरेलू उद्योग उसे प्रदत्त पाठनरोधी शुल्क का लाभ भी नहीं ले सका था।

ख. घरेलू उद्योग के नकद लाभ, पीबीआईटी और नियोजित पूंजी पर आय में भी यही प्रवृत्ति रही है।

iv. मालसूची

172. संबद्ध वस्तु की मालसूची से संबंधित आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
1	औसत स्टॉक	एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	115	113

173. यह नोट किया गया है कि इस अवधि के दौरान औसत मालसूची में वृद्धि हुई है।

v. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

174. क्षति अवधि के दौरान रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
1	मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	121	124
3	रोजगार	सं.	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	98	99
5	प्रतिदिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	103	100
7	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	प्रति सं.	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	105	101

175. यह देखा गया है कि मजदूरी, रोजगार और उत्पादकता समान स्तर पर बनी रही हैं।

vi. वृद्धि

176. घरेलू उद्योग के मात्रा और लाभ मापदंडों की प्रवृत्ति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
1	उत्पादन	%	-	12%	-8%	-3%
2	घरेलू बिक्रियां	%	-	26%	-22%	-6%
3	प्रति इकाई हानि	%	-	38%	-39%	36%

177. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू बिक्री में क्रृष्णात्मक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के घाटों में पूर्व वर्ष और आधार वर्ष की तुलना में भारी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में भी क्षति अवधि में गिरावट आई है।

vii. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

178. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को आयातों की कम कीमत से बराबरी करने के लिए अपनी लागत से काफी कम पर बिक्री के लिए मजबूर होना पड़ा है। संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में इस अवधि में वृद्धि हुई है जबकि घरेलू उद्योग के हिस्से में वृद्धि हुई है, यह दर्शाता है कि आयात कम कीमत पर बाजार में प्रवेश कर रहे हैं।

viii. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

179. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के पास काफी अप्रयुक्त क्षमता है और उसे लगातार घाटा हो रहा है। यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग को मात्रा और कीमत दोनों क्षति हुई है और इसलिए पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है।

180. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता को प्राथमिक रूप से उच्च व्याज लागत के कारण उच्च प्रति इकाई पूँजी और स्थिर लागत की बजह से संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान घाटा उठाना पड़ा है। यद्यपि याचिकाकर्ता के पास 80 प्रतिशत से अधिक मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त क्षमता है, परंतु कमतर पहुंच कीमत पर संबद्ध देशों से सम्बिडी प्राप्त आयातों के कारण याचिकाकर्ता प्रतिस्पर्धा करने और अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत से कम का उपयोग करने में भी असमर्थ है। कम क्षमता उपयोग उच्च व्याज लागत का मुख्य कारण है। यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग मौजूदा क्रृष्णों का समय पर भुगतान नहीं कर पाया है और इसलिए वह अपने दैनिक प्रचालनों के लिए कार्यशील पूँजी की व्यवस्था करने में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। अतः, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति सम्बिडी प्राप्त आयातों के कारण क्षति का कारण नहीं अपितु परिणाम है।

ज्ञ. क्षति के संबंध में निष्कर्ष

181. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयातों में भारत में उत्पादन और खपत के सापेक्ष और निरपेक्ष संदर्भ में काफी वृद्धि हुई है। आयात की कीमत पूरे क्षति विश्लेषण के दौरान उत्पाद की लागत से काफी कम रही है और कम कीमत पर बिक्री भी सकारात्मक है। जबकि संबद्ध आयातों के बाजार अंश में काफी वृद्धि हुई है, जबकि घरेलू उत्पादकों के अंश में गिरावट आई है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग अप्रयुक्त क्षमताओं का गंभीर सामना कर रहा है और यह यहां तक कि अपनी आधी स्थापित क्षमता का भी उपयोग नहीं कर पाया है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के पास इन्वेन्ट्री में आधार वर्ष की तुलना में काफी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान हुए व्यय में वृद्धि हुई है और इसके नकदी लाभों, पीबीआईटी और निवेश पर प्रतिफल में वही प्रवृत्ति रही है। तदनुसार, प्राधिकारी अनन्तिम रूप ये यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को पर्याप्त क्षति हुई है।

182. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग मात्रा और कीमत क्षति, दोनों का सामना कर रहा है।

I. कारणात्मक संबंध

183. प्राधिकारी ने निम्नानुसार जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात कारकों की बजह से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

184. अन्य देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है क्योंकि वे नगण्य हैं।

ख. मांग में संकुचन और/अथवा खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

185. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग में कोई संकुचन नहीं है। इसके अलावा खपत की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ग. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

186. कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं नहीं हैं।

घ. प्रौद्योगिकी में विकास

187. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में परिवर्तन दर्शाने वाला कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

इ. घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन

188. यह नोट किया गया है कि क्षति विश्लेषण याचिकाकर्ता के घरेलू निष्पादन पर आधारित है।

च. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन

189. प्राधिकारी ने केवल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है।

छ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कथित अन्य कारक

190. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग को हो रही क्षति, यदि कोई हो, इंडोनेशिया में या कच्चे में स्पिलिटिंग सुविधा की स्थापना में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेशों जैसे अन्य कारकों की वजह से हुई है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी बताया है कि घरेलू उद्योग को क्षति उच्च ब्याज लागत के कारण हुई है। इसके उत्तर में, घरेलू उद्योग ने बताया है कि इंडोनेशिया में उसके निवेश से कच्ची सामग्री की लागत को कम करने में काफी मदद मिली है। कच्चे में किए गए निवेश के संबंध में, यह बताया गया है कि कच्चे का संयंत्र 2011 से बंद है और इसलिए वर्तमान लागत पर व्यावहारिक रूप से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

191. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग को क्षति इन्वर्टिड शुल्क संरचना के कारण हुई है अर्थात् सीपीकेओ (कच्ची सामग्री) पर उच्च आयात टैरिफ, याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि वह इस समय विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण के लिए सीपीकेओ का आयात नहीं करता है, बीबीएफ को हो रही क्षति इन्वर्टिड शुल्क संरचना के कारण नहीं हुई है। याचिकाकर्ता ने बताया है कि उसके आयात स्पिलट सीपीकेओ, फैटी एसिड डिस्टिलेट्स आदि, जैसी कच्ची सामग्रियों के हैं, जिन पर आयात शुल्क 7.5 प्रतिशत है।

192. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों के उक्त अनुरोध मुख्यतः याचिकाकर्ता की ब्याज लागत से संबंधित है। प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए जा रहे ब्याज की जांच की है, और यथा तर्कसंगत केवल ऐसी ब्याज लागत पर ही एनआईपी के निर्धारण हेतु विचार किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एनआईपी को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी), पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के प्रावधान और डीजीटीआर की संगत प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया गया है। उक्त नियमों में यथा-प्रदत्त औचित्य के सिद्धांतों का यह सुनिश्चित करने के लिए पालन किया गया है कि एनआईपी के निर्धारण के लिए ब्याज राशि की अनुमति देते समय ब्याज पर हुए किसी असामान्य खर्च को शामिल न किया जाए। औचित्य के पहलू के अलावा, प्राधिकारी पीयूसी के विनिर्माण में लगी परिसंपत्तियों तथा प्रति इकाई ब्याज लागत के निर्धारण हेतु कारकों की ईष्टतम क्षमता की भी जांच करते हैं।

ट. प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियां

193. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए आवश्यक तथ्यों को प्रकट करते हुए दिनांक 22 सितंबर, 2022 को एक प्रकटीकरण विवरण जारी किया है। हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटीकरण के उपरांत अनुरोध प्राप्त हुए हैं। उठाए गए अधिकांश मामलों को पहले ही उठाया जा चुका है और उन पर पर्याप्त रूप से विचार किया जा चुका है। अतिरिक्त अनुरोधों की, जहां तक वे संगत पाए गए हैं, जांच की गई है, जो इस प्रकार है :

ट.1 याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध :

194. बिना किसी लाभ/ प्रतिफल की वसूली किए बिना बिक्रियों की लागत पर ही एनआईपी का निर्धारण कानूनी प्रावधानों और निदेशालय की विगत प्रक्रियाओं के प्रतिकूल है। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया है कि एक तर्कसंगत “प्रतिफल” के बाद एनआईपी का पुनः निर्धारण किया जाए। यह भी अनुरोध किया गया है कि ब्याज लागत में कटौती बिना किसी आधार के है और इसलिए न्यायोचित नहीं हो सकती।

195. सीपीकेओ की आपूर्ति पर पर्याप्त पारिश्रमिक से भी कम पारिश्रमिक पर सब्सिडी के निर्धारण के संबंध में, याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया है कि इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा सीपीकेओ आपूर्तिकर्ता है जो विश्व के कुल सीपीकेओ की मांग में से करीब 70% मांग पूरी कर रहा है। अतः इंडोनेशियाई निर्यात कीमत सीपीकेओ की अविकृत बाजार कीमत को दर्शाती है और उस पर इंडोनेशिया तथा मलेशिया, दोनों के लिए बैंचमार्क के रूप में विचार किया जाना चाहिए।

196. मलेशिया से निर्यात कीमत, मलेशिया में कुछेक सबसे बड़े बागानों से उत्पादित पाम कर्नेल ऑयल के आयातों पर यूएसए द्वारा (मलेशिया से पाम कर्नेल ऑयल के मुख्य खरीदारों में से एक) लगाए गए प्रतिबंध के कारण बाजार की स्थितियों पर आधारित नहीं थी।

ट.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

इंडोनेशियाई सब्सिडी कार्यक्रम

197. इंडोनेशियाई सरकार द्वारा निर्यात कर लगाना/ या वसूलना राजस्व संग्रहण का एकाधिकार का कार्य है और इसमें सब्सिडी शामिल नहीं है।

198. निजी भागीदारों के बीच सीपीकेओ और उसके उत्पादों की विक्री भारत सरकार के हस्तक्षेप के बिना बाजार कीमतों पर की जाती है। एलटीएआर पर सीपीकेओ की आपूर्ति करने के लिए निजी आपूर्तिकर्ताओं को भारत सरकार द्वारा कोई कार्य सौंपा या अनुदेश नहीं दिया गया है। ‘‘एनटीएआर के लिए सरकार द्वारा वस्तुओं की प्रत्यक्ष आपूर्ति’’, ‘‘निधियों के प्रत्यक्ष हस्तांतरण’’ किसी के साक्ष्य के अभाव में, ‘‘राजस्व छूट, जो अन्यथा देय होती’’ या ‘‘निजी भागीदारों को कार्य या अनुदेश देना’’ सब्सिडी नहीं हो सकता।

199. वैकल्पिक रूप से, यहां तक कि यदि यह निर्धारित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा एलटीएआर पर सीपीकेओ का प्रावधान करके सब्सिडी प्रदान की गई है, तो प्राप्त ‘‘लाभ’’ की गणना करने के लिए उपयुक्त बैंचमार्क के रूप में निर्यात कर और वसूली घटक की कटौती करने के बाद सीपीकेओ की ‘‘निर्यात कीमत’’ होगा क्योंकि यह सरकार द्वारा एकत्रित निर्यात शुल्क है न कि सीपीकेओ की खरीद के लिए भुगतान की गई प्रतिफल राशि है।

200. इंडोनेशिया में ब्याज दरें बाजार से निर्धारित हैं और प्रत्येक ग्राहक की क्रेडिट रेटिंग पर आधारित हैं। एक साख वाले ग्राहक को प्रायः सामान्य बैंक ऋण दर की बजाय एक बेहतर ऋण दर मिलेगी। सरकारी बैंकों से समान दर पर ऋण लिया गया है, क्योंकि निजी बैंक प्रति संतुलनकारी नहीं हो सकते।

201. एक हितवद्ध पक्षकार ने यह भी अनुरोध किया है कि प्रकटीकरण विवरण में उनके लिए विचार किया गया पहुंच सीआईएफ मूल्य उसमें दावा किए गए मूल्य से भिन्न है।

मलेशिया सब्सिडी कार्यक्रम

202. सीपीकेओ पर निर्यात शुल्क लगाना एक सब्सिडी नहीं है क्योंकि यह ‘‘निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण’’ नहीं है क्योंकि अनुदान के मामले की तरह निधियों का कोई आउटफ्लो नहीं है। यह ‘‘सरकारी राजस्व की छूट’’ भी नहीं है क्योंकि मलेशिया सरकार द्वारा कोई राजस्व छूट नहीं दी जा रही। दूसरी ओर, मलेशिया सरकार निर्यात कर लगाकर राजस्व वसूल रही है।

203. इसके अलावा, ‘‘वस्तुओं पर सेवाओं का सरकारी प्रावधान’’ नहीं है क्योंकि मलेशिया सरकार निर्यात कर लगाकर सीपीकेओ नहीं प्रदान कर रही है। ऐसी व्यवस्था, जिसके द्वारा निर्यात कर मलेशिया सरकार द्वारा लगाया जाता है, मलेशिया सरकार द्वारा सीपीकेओ की आपूर्ति या कोई व्यवस्था प्रदर्शित नहीं होती। इस प्रकार, कथित उपायों से किसी भी रूप में ‘‘वित्तीय योगदान’’ प्रदान नहीं किया जाता।

204. यह अनुरोध किया गया है कि यहां तक कि यदि प्राधिकारी एलटीएआर पर सीपीकेओ की आपूर्ति को प्रतिसंतुलनकारी रखता था, सब्सिडी की गणना के लिए उपयुक्त बैंचमार्क जैसा कि एमपीओबी वेबसाइट पर सूचित किया गया है, मलेशिया से निर्यात कीमत होगी। यह अनुरोध किया गया है कि सीवीडी नियमावली के तहत, यह निर्धारण करते हुए कि क्या वस्तुएं पर्याप्त पारिश्रमिक से भी कम पर बेची गई हैं, पारिश्रमिक की पर्याप्तता का निर्धारण प्रावधान या खरीद वाले देश में प्रश्नगत उत्पाद या सेवा के लिए प्रचलित बाजार स्थितियों के संबंध में है।

205. सीपीकेओ की सीआईएफ रोटरडम कीमत बैंचमार्क के रूप में काफी अविश्वसनीय है क्योंकि यह मलेशिया से सीपीकेओ की वास्तविक शिपमेंट पर आधारित नहीं है। यह दैनिक आधार पर विक्रेता के/ब्रोकर के कोटेशनों की जांचों पर आधारित है, जो नीदरलैंड (रोटरडम) के लिए वास्तविक निर्यात शिपमेंट में बदल सकती है या नहीं बदल सकती।

206. सीआईएफ रोटरडम कीमत एक और दो माह की आपूर्तियों के लिए आगे व्यापार में रोटरडम की आपूर्ति के लिए इंडोनेशिया और मलेशिया निर्यात कीमत कोटेशनों का एक मिश्रण है।

207. मलेशियाई उत्पादकों को इंडोनेशियाई सरकार द्वारा अधिक निर्यात शुल्क लगाने या वसूली के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। अतः यह मलेशिया से सीपीकेओ निर्यातों की वास्तविक कीमत को नहीं दर्शाता। इंडोनेशिया करीब 1.5 से 1.8 मिलियन टन पाम ऑयल (कच्चा/रिफाइंड) तथा केवल 0.3 मिलियन टन वार्षिक रूप से भेजता है।

208. प्राधिकारी मलेशिया के लिए सीपीकेओ बैंचमार्क के लिए विपरीत रुख नहीं रख सकता, जबकि उसने इंडोनेशिया के लिए एफओबी निर्यात कीमतें और मलेशिया से आरबीडीपीकेओ के लिए एफओबी निर्यात कीमतों को लिया है।

थाइलैंड सब्सिडी कार्यक्रम

209. थाइलैंड सरकार द्वारा प्रदान की गई छूट (ड्रॉबैक) पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जा सकता क्योंकि यह एससीएम के अनुच्छेद I के फुटनोट के संदर्भ में एक अनुमत शुल्क छूट है। यह अनुरोध किया गया है कि थाई

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रदान किया गया शुल्क ड्रॉबैक एक सब्सिडी नहीं है क्योंकि यह निर्यात उत्पादन के लिए प्रयुक्त इनपुट पर केवल शुल्क छूट प्रदान करता है।

210. यह दावा किया गया है कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह सुनिश्चित करने के लिए थाइलैंड सरकार द्वारा अपनाई गई सत्यापन की व्यवस्था की मौजूदगी को प्रदर्शित किया है कि कोई अतिरिक्त छूट नहीं है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

211. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकांश अनुरोधों पर पिछले पैराओं में पहले ही विचार किया जा चुका है। जहां तक याचिकाकर्ता के दावे का संबंध है कि एनआईपी के निर्धारण के लिए उन्हें एक “तर्कसंगत प्रतिफल” प्रदान किया जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एनआईपी का निर्धारण पाठनरोधी शुल्क नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार और निदेशालय की सतत प्रक्रिया के अनुसार किया गया है।

212. जहां तक इंडोनेशिया के लिए अपनाई गई बैंचमार्क कीमत के संबंध में अनुरोध का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने इंडोनेशिया से शेष विश्व के लिए एक उपयुक्त बैंचमार्क के रूप में सीपीकेओ निर्यात कीमतों पर विचार किया था, क्योंकि वे मुक्त बाजार सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित हैं, इंडोनेशिया में प्रचलित बाजार स्थितियों को दर्शाती हैं और सरकारी हस्तक्षेपों द्वारा विकृत नहीं हैं। कई हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि निर्यात कर और निर्यात वसूली जो, ऐसे निर्यातों पर लागू हैं, बैंचमार्क कीमत के निर्धारण के लिए निर्यात कीमत से बाहर की जानी चाहिए। प्राधिकारी इस अनुरोध में कोई गुण नहीं पाते कि इंडोनेशिया से सीपीकेओ की औसत “निर्यात कीमत” को बैंचमार्क के निर्धारण के लिए विचार में लिया गया है चूंकि वह ऐसी कीमत है, जिस पर सीपीकेओ की विदेशी ग्राहक को बिक्री की गई है। यह विदेशी ग्राहकों से वसूली गई इस कीमत और घरेलू ग्राहकों की खरीद कीमत के बीच का अंतर है, जिस पर सब्सिडी की गणना के लिए विचार किया गया है। सीपीकेओ के एक घरेलू खरीदार को प्राप्त लाभ उसकी सीपीकेओ की खरीद कीमत और अविकृत निर्यात कीमत के बीच का अंतर है।

213. प्राधिकरण नोट करता है कि पाम कर्नेल तेल में व्यापार के लिए रॉटरडैम मूल्य एक वैश्विक बैंचमार्क है। रॉटरडैम मूल्य CPKO के लिए अविकृत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, और धातु उत्पादों के लिए लंदन मेटल एक्सचेंज के समान एक सूचकांक है। निर्यातकों और घरेलू उद्योग दोनों का यह सामान्य निवेदन है कि “सीआईएफ रॉटरडैम मूल्य” उस कीमत को इंगित करता है जिस पर किसी विशेष तारीख को अनुबंध किए जा रहे हैं। यह देखा गया है कि कई निर्यातकों के साथ-साथ घरेलू उद्योग सीपीकेओ के लिए अनुबंध करने के लिए एक संदर्भ के रूप में सीआईएफ रॉटरडैम मूल्य का उपयोग करते हैं। भारत सरकार के निवेदन के अनुसार, सीपीकेओ के सीआईएफ रॉटरडैम मूल्य को सीपीकेओ पर निर्यात कर और निर्यात लेवी निर्धारित करने के लिए “संदर्भ मूल्य” निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाता है।

214. मलेशियाई निर्यातकों द्वारा यह दावा किया गया है कि एमपीओबी मूल्य पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह अविकृत मलेशियाई मूल्य का प्रतिनिधि है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जहां सीआईएफ रॉटरडैम मूल्य किसी विशेष तिथि पर मौजूद कीमत को इंगित करता है, इसके विपरीत, एमपीओबी मूल्य शिपमेंट तिथि, अर्थात् वह तिथि जिस पर निर्यात हुआ है, की कीमत है। यह देखा गया है कि आमतौर पर अनुबंध की तारीख (जब कीमत तय होती है) और शिपमेंट की तारीख के बीच कुछ महीनों का समय अंतर होता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जनवरी 2021 से मलेशिया द्वारा निर्यात शुल्क फिर से लगाया गया था, और इससे पहले सीपीकेओ के निर्यात पर कोई निर्यात कर नहीं था। नतीजतन, जनवरी 2021 से पहले किए गए अनुबंध, जिन्हें बाद के महीनों में भेज दिया जाएगा, निर्यात कर घटक में शामिल होने की संभावना नहीं है। यह एमपीओबी निर्यात मूल्य और सीआईएफ रॉटरडैम मूल्य की तुलना से भी स्पष्ट है, जिससे यह देखा जा सकता है कि शुरुआती कुछ महीनों के लिए एमपीओबी का सीपीकेओ निर्यात मूल्य सीआईएफ रॉटरडैम कीमतों से कम था, जबकि बाद के महीनों में यह या तो अधिक था या कम था। समान श्रेणी। इसलिए, उचित तुलना करने के लिए, CIF रॉटरडैम मूल्य (माल और बीमा के लिए समायोजित) को इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों के लिए उपयुक्त बैंचमार्क माना गया है और उस पर सब्सिडी मार्जिन तदनुसार निर्धारित किया गया है।

215. जहां तक रिफाइंड ब्लीच डिओडराइज़ याम कर्नेल ऑयल (“आरबीडीपीकेओ”) के लिए बैंचमार्क कीमत का संबंध है, याचिकाकर्ता ने मलेशिया से आरबीडीपीकेओ निर्यात कीमत प्रस्तुत की है, जैसा कि ओलियोलाइन द्वारा सूचित किया गया है। यह अनुरोध किया गया है कि इसके लिए कोई भी वैकल्पिक बैंचमार्क उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह न तो रोटरडैम में और न ही इंडोनेशिया में दर्ज है। हितबद्ध पक्षकारों ने भी इसके लिए कोई वैकल्पिक बैंचमार्क प्रदान

नहीं किया है। अतः प्राधिकारी ने आरबीडीपीकेओ की निर्यात कीमत पर सब्सिडी की गणना के लिए एक उपयुक्त बैंच मार्क के रूप में विचार किया है।

216. जहां तक सब्सिडी मार्जिन की गणना के संबंध में किए गए निवेदनों का संबंध है, इन अंतिम जांच परिणामों में उन पर विचार किया गया है और उपयुक्त पाए गए परिवर्तनों को ऊपर निर्धारित सब्सिडी मार्जिन में किया गया है।
217. पहुंच मूल्य में परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुतीकरण के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा पहुंच मूल्य पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार विचार किया गया है।
218. कुछ इच्छुक पार्टियों ने यह भी दावा किया है कि चूंकि उन्हें सरकारी बैंकों और निजी बैंकों द्वारा एक ही दर पर ऋण दिया गया है, इसलिए कोई सब्सिडी नहीं है। प्राधिकरण नोट करता है कि तथ्य यह है कि निजी बैंक भी लागू मूल उधार दर की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम उधार दर पर ऋण प्रदान कर रहे हैं, यह अपने आप में संबद्ध देशों की सरकारों द्वारा "सौंपने या निर्देश" का एक स्पष्ट संकेत है। निजी बैंक, अधिमान्य ऋण के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान करने के लिए। इसलिए इसे प्रतिकारी माना गया है।
219. बैंचमार्क प्रकटीकरण के जवाब में, इंडोनेशिया के कुछ भाग लेने वाले निर्यातकों द्वारा यह दावा किया गया है कि सीपीकेओ के बैंचमार्क मूल्य का निर्धारण करते समय, निर्यात कर, निर्यात लेवी और अन्य बंदरगाह खर्चों की कटौती की जानी आवश्यक है। प्राधिकरण ने पहले ही ऊपर उल्लेख किया है कि निर्यात कर और लेवी की कटौती से जांच का उद्देश्य विफल हो जाएगा। जहां तक पत्तन व्ययों की कटौती के दावे का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि रॉटरडैम में आयातकों को जिस कीमत पर सीपीकेओ की आपूर्ति की जा रही है, उस पर विचार किया गया है। शिपमेंट लागत से संबंधित सभी खर्चों को बाहर करने के लिए USD 50/MT की मानक कटौती की गई है। उक्त निर्यातकों द्वारा इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है कि ये बंदरगाह व्यय सीआईएफ मूल्य का हिस्सा हैं या वे 50 अमरीकी डालर/एमटी से अधिक हैं। इसके अभाव में, प्राधिकारी को हितबद्ध पक्षों द्वारा किए जा रहे दावे में कोई योग्यता नहीं मिलती है।
220. इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि मलेशिया के एक निर्यातक ने यह प्रमाणित करने के लिए अपना एक चालान प्रदान किया है कि मलेशिया से रॉटरडैम तक माल भाड़ा लगभग 70 अमेरिकी डॉलर/एमटी है। यह नोट किया जाता है कि उक्त चालान लगभग 1500-2000 मीट्रिक टन एसएफए के शिपमेंट का है और सीपीकेओ का नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एसएफए और सीपीकेओ के लिए माल ढुलाई लागत समान नहीं है, क्योंकि सबसे पहले, एसएफए एक रासायनिक उत्पाद है और इसलिए इसे अत्यधिक संरक्षित वातावरण में आयात किया जाता है जैसे स्टेनलेस स्टील टैंकों में नाइट्रोजन ब्लैकेटिंग के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि रासायनिक गुण प्राप्त नहीं होते हैं। प्रभावित। दूसरी ओर, सीपीकेओ कञ्चे प्राकृतिक तेल होने के कारण, इसे आमतौर पर हल्के स्टील के टैंकों में आयात किया जाता है। दूसरे, SFA का आयात कम मात्रा में किया जाता है, जबकि CPKO का आयात आमतौर पर 15,000 से 20,000 मीट्रिक टन की भारी मात्रा में किया जाता है। इसके अलावा, प्राधिकरण नोट करता है कि यूरोपीय रासायनिक एजेंसी (ECHA) REACH पंजीकरण के अनुसार, SFA को जलीय जीवन के लिए बहुत विषाक्त होने के रूप में खतरनाक मानती है और लंबे समय तक चलने वाले प्रभावों के साथ जलीय जीवन³ के लिए विषाक्त है। दूसरी ओर, CPKO को खतरनाक उत्पाद⁴ नहीं माना जाता है। इसलिए, CPKO की शिपमेंट लागत की तुलना SFA के साथ नहीं की जा सकती। तदनुसार, प्राधिकारी निर्यातक के उक्त दावे को अस्वीकार करते हैं।

ठ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मामले

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

221. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह दावा किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क, यदि कोई हो, लगाना निम्नलिखित कारणों से लोक हित में होगा:-
 - क. इसकी कञ्ची सामग्री पर निर्भरता, उच्च ब्याज लागत और अन्य अक्षमताओं के कारण, याचिकाकर्ता विचाराधीन उत्पाद के लिए भारतीय मांग को पूरा करने के लिए समर्थ नहीं होगा।
 - ख. विचाराधीन उत्पाद की लागत में वृद्धि होने से ऐसे उत्पादों जैसे साबुन, डिटरजेंट आदि की लागतों में वृद्धि होगी, जिनका बड़ी मात्रा में लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है।

³ <https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.105.704>

⁴ <https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.029.473>

ग. विचाराधीन उत्पाद पर शुल्क लगाने से विचाराधीन उत्पाद जैसे इथोजाइलेट, एसएलईएस और एसएलएस के डाउनस्ट्रीम उत्पादों के आयातों में वृद्धि होगी, जो वर्तमान में एशियन मुक्त व्यापार करार के तहत 0% बुनियादी सीमा शुल्क के अधीन हैं। शुल्क लगाए जाने से डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए उलट शुल्क संरचना होगी, जिससे डाउनस्ट्रीम वस्तुओं के आयातों में वृद्धि होगी। इसके कारण कारोबार और डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए रोजगार का नुकसान होगा।

घ. संबद्ध देशों में डाउनस्ट्रीम उत्पादों की उत्पादन क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। यह बिल्कुल ही संभावना है कि यदि एसएफए पर शुल्क लगाए जाते हैं, तो निर्यातक डाउनस्ट्रीम उत्पादों (एसएलएस/एसएलईएस या इथोलाइलेट) का निर्यात करना शुरू कर देंगे।

ड. याचिकाकर्ता की क्षमता भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और यदि शुल्क लगाया जाता है, तो इससे भारतीय बाजार में मांग आपूर्ति का अंतर हो जाएगा।

ठ.2 याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध

222. शुल्क लगाना डाउनस्ट्रीम उद्योगों और व्यापक रूप से आम जनता के हित में होगा।

223. अकेले याचिकाकर्ता की स्थापित क्षमता ही भारतीय मांग का करीब 80% पूरा करने के लिए पर्याप्त है। अतः शुल्क लगाए जाने से भारतीय बाजार में कोई भी मांग आपूर्ति अन्तर आने की संभावना नहीं है।

224. सामान्यतः प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने का प्रयोजन अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करना और भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कायम रखना है।

225. उपभोक्ता उत्पादों की लागत पर शुल्क का एक नगण्य (0.3%) प्रभाव पड़ेगा।

226. यदि घरेलू उद्योग को तत्काल शुल्कों का संरक्षण प्रदान नहीं किया गया, तो वह बच नहीं पाएगा और इसके परिणामस्वरूप समग्र डाउनस्ट्रीम उद्योग उनकी कञ्ची सामग्री (एसएफए) की जरूरत के लिए आयातों पर निर्भर होगा।

227. संबद्ध देशों में डाउनस्ट्रीम उत्पादों (एसएलएस/एसएलईएस) की क्षमता में वृद्धि, जो स्थानीय मांग से पर्याप्त अधिक है, स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि याचिकाकर्ता, जो कि भारतीय घरेलू उद्योग है, का सफाया हो जाता है, तो संबद्ध देश डाउनस्ट्रीम उत्पादों के निर्यातों को प्रोत्साहित करेंगे।

228. इसके अलावा, यदि याचिकाकर्ता का सफाया हो जाता है, तो डाउनस्ट्रीम उत्पादक अपनी कञ्ची सामग्री (एसएफए) की जरूरत के लिए केवल आयातों पर ही निर्भर हो जाएंगे, जो कि उनके व्यापक हित में नहीं होगा।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

229. प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर सब्सिडी रोधी शुल्क लगाने से यह व्यापक रूप से लोक हित के खिलाफ होगा। यह निर्धारण, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना पर विचार करने के आधार पर और घरेलू उद्योग, आयातकों तथा उत्पाद के उपभोक्ताओं सहित हितधारकों के हित में होगा।

230. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता की कुल उत्पादन क्षमता *** मी. टन है और गोदरेज इंडस्ट्रीज की क्षमता करीब *** मी. टन है, जबकि मांग करीब 1,45,000 मी. टन की है। स्पष्ट रूप से, भारतीय उत्पादन क्षमता समग्र भारतीय मांग को ही पूरा करने के लिए पर्याप्त है। अतः यहां मांग आपूर्ति का अन्तर होने का प्रश्न माले के वर्तमान तथ्यों को देखते हुए नहीं उठता। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा कि याचिकाकर्ता के पास मिश्रित सी 1214 का उत्पादन करने के लिए सीमित क्षमता है, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता के पास जांच की अवधि के दौरान पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता थी, जो कि सब्सिडी के आयातों के कारण वास्तविक क्षति के प्रभाव की बजाय और कोई कारण नहीं है। जहां तक घरेलू उद्योग की वित्तीय लागत अधिक होने के बारे में आरोप का संबंध है, उसे घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत का निर्धारण करते समय अलग किया गया है और ब्याज लागत एक तर्कसंगत ब्याज लागत पर पहुंचने के लिए कम की गई है।

231. प्राधिकारी ने यह भी पाया है कि विचाराधीन उत्पाद एक औद्योगिक कञ्ची सामग्री है, जो प्रमुख रूप से एसएलएस, एसएलईएस या इथोजाइलेट आदि के निर्माण में प्रयुक्त होती है, जिसका आगे एफएमसीजी उत्पादों जैसे साबुन, शेम्पू, डिटर्जेंट आदि के निर्माण में प्रयोग होता है। एक औद्योगिक कञ्ची सामग्री होने के कारण, यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद पर लगाया गया शुल्क वास्तविक अंतिम ग्राहक पर पहुंचेगा। अतः अंतिम ग्राहक पर

शुल्क का प्रभाव देखा जाएगा। याचिकाकर्ता ने अंतिम ग्राहक पर शुल्क के प्रभाव की एक मात्रात्मक कार्य-प्रणाली प्रदान की है, जिसका हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विरोध नहीं किया गया है। यह देखा गया है कि अंतिम उत्पाद की कीमत पर औसत शुल्कों का प्रभाव नगण्य होगा।

232. संबद्ध वस्तुओं के आयातकों/प्रयोक्ताओं ने यह दावा किया है कि शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उत्पादों जैसे एसएलएस, एसएलईएस और इथोजाइलेट के लिए उलट शुल्क संरचना होगी क्योंकि उन पर एशियन एफटीए के तहत शून्य आयात शुल्क है। उनके द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि संबद्ध देशों के निर्यातक एकीकृत हैं और अपनी डाउनस्ट्रीम उत्पादन क्षमता को स्थानीय मांग से काफी अधिक विस्तार कर रहे हैं। इन तथ्यों में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यदि घरेलू उद्योग का सफाया हो जाता है, तो डाउनस्ट्रीम उद्योग पूरी तरह से, अपनी कच्ची सामग्री की जरूरतों के लिए आयातों पर निर्भर हो जाएगा। चूंकि संबद्ध देशों से निर्यातक अपनी डाउनस्ट्रीम क्षमता का विस्तार कर रहे हैं, अतः यह संभावना है कि एसएफए के निर्यात घरेलू एसएफए आपूर्तिकर्ता के अभाव में मूल्य वर्धित डाउनस्ट्रीम उत्पादों जैसे एसएलएस, एसएलईएस और इथोजाइलेट के निर्यातों द्वारा प्रतिस्थापित होंगे। कच्ची सामग्री की जरूरत के लिए आयातों पर निर्भरता होने से डाउनस्ट्रीम उद्योग उसी स्थिति में होंगे जिस स्थिति में घरेलू उद्योग होगा, जहां पर वे संबद्ध देशों से सस्ते डाउनस्ट्रीम उत्पादों का मुकाबला करेंगे।
233. यह निर्विवाद सत्य है, जो जांच से प्रकट हुआ है कि घरेलू उद्योग तब तक बना नहीं रह पाएगा, जब तक कि उन्हें पर्याप्त संरक्षण नहीं मिलेगा। यह नोट किया जाता है कि यदि घरेलू उद्योग को कच्ची सामग्री के किसी स्थानीय स्रोत के अभाव में क्षति होती है, तो डाउनस्ट्रीम निर्यात निर्यातकों की दया पर ही रहेंगे, जो निर्यातक बाद में कीमतों पर अपनी पकड़ रखने की स्थिति में होंगे और आसानी से एसएफए की कीमतें बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को देखने हुए कि संबद्ध देश अमान्य सब्सिडी के प्रावधान के ज़रिए, मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यातों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहन दे रहे हैं, जिससे डाउनस्ट्रीम उद्योग पूरी तरह से, अपनी कच्ची सामग्री की जरूरत के लिए आयातों पर निर्भर होंगे।
234. आगे यह नोट किया जाता है कि एसएफए और इसके डाउनस्ट्रीम उत्पाद, एथोक्सिलेट्स और एसएलएस/एसएलईएस दोनों पर आसियान एफटीए के तहत शून्य सीमा शुल्क लगता है। सीवीडी लगाने से संबद्ध देशों द्वारा प्रदान की जा रही अस्वीकार्य सब्सिडी के प्रभाव को हटाकर केवल कीमत में सुधार होगा। तथापि, यदि शुल्कों से बचने की दृष्टि से संबद्ध देशों में डाउनस्ट्रीम विनिर्माताओं को अस्वीकार्य सब्सिडी दी जाती है, तो भारतीय उद्योग इसके विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्राधिकरण ने यहां ऊपर पहले ही निर्धारित कर लिया है कि संबद्ध देश इंडोनेशिया और मलेशिया की सरकारों द्वारा एलटीएआर में विशेष रूप से कच्चे माल (सीपीकेओ) का प्रावधान अस्वीकार्य सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। यदि सब्सिडी जारी रहती है, और एसएलएस, एसएलईएस और एथोक्सिलेट्स के लिए कच्चे माल की आपूर्ति एलटीएआर में की जाती है, तो डाउनस्ट्रीम उत्पादकों के पास हमेशा इसके खिलाफ उचित उपाय खोजने का विकल्प होगा। हालांकि, एक अनुचित व्यापार व्यवहार को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इसका निवारण करने की आवश्यकता है।
235. डाउनस्ट्रीम उद्योगों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि एक कंपनी (अर्थात् याचिकाकर्ता) को अनेक डाउनस्ट्रीम उद्योगों की लागत पर संरक्षण देना लोक हित में नहीं होगा। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि सब्सिडी रोधी जांच का प्रयोजन संबद्ध देशों द्वारा प्रदान की जा रही गैर अनुमत सब्सिडी से समग्र रूप से घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करना है। अतः क्या घरेलू उद्योग वर्तमान में एक कंपनी है या अनेक कंपनियां हैं, यह असंगत विचार है। वास्तव में, पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने से यह संभव है कि इससे आगे निवेश आएगा। भारत, अपनी आबादी के कारण, संबद्ध वस्तुओं का एक प्रमुख ग्राहक है। अतः यह संभावना है कि गैर अनुमत सब्सिडी की प्रवंचना होने से और एक समान वातावरण मिलने से एसएफए का उत्पादन मांग बाजार अर्थात् भारत की ओर जा सकता है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीपीकेओ (कच्ची सामग्री) से एसएफए तक मूल्य वर्धन करीब 70% है, जबकि एसएफए से इथोलाइजेट/एसएलईएस के लिए करीब 10-11% है। अतः शुल्क लगाने से भारत में मूल्य वर्धन को बढ़ावा मिलेगा और यह व्यापक रूप से लोक हित में होगा।
236. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सामान्यतः प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने का प्रयोजन, भारतीय बाजार में खुली और उचित व्यापार प्रक्रिया द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करना है जो देश के सामान्य हित में है। प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने से किसी भी तरह से संबद्ध देश से आयात सीमित नहीं होंगे और इसीलिए, उपभोक्ताओं को उत्पादों की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

237. प्राधिकारी इस तथ्य को जानते हैं कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुओं की लागत पर प्रभाव पड़ सकता है। इसकी बजाय, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा होगी, विशेषकर, जब प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने से सब्सिडी प्राप्त संबद्ध वस्तुओं के आयातें द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए आवश्यक मात्रा को सीमित किया जाता है। वास्तव में प्रतिसंतुलनकारी उपायों से सब्सिडी द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ को हटाया जा सकेगा, घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट को रोका जा सकेगा और संबद्ध वस्तुओं के ग्राहकों को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिल सकेगी।

238. जहां तक भागीदार आयातकों/ प्रयोक्ता उद्योग पर उपायों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी ने यह विचार किया है कि उनका लाभ कुछ हद तक उपायों को लागू करने से प्रभावित हो सकता है। यह नोट किया जाता है कि आयात उद्योग की लाभप्रदता सिंगल डिजिट से डबल डिजिट के बीच है। उनके लाभ मार्जिन को देखते हुए, प्रभाव असमान होंगे, जिससे कीमत में वृद्धि का न्यूनतम हिस्सा उनके ग्राहकों को पारित किया जा सकेगा। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की अपर्याप्त लाभप्रदता और बाजार पर कीमत के ह्रास को देखते हुए, यह तर्कसंगत रूप से माना जा सकता है कि उपायों को लागू किए जाने से कीमतें बढ़ेंगी। फिर भी, प्रभाव के उपाय क्षिप्रतय प्रयोक्ताओं पर हो सकते हैं, जिससे घरेलू उद्योग के क्रियाकलाप बंद होने के जोखिम को संतुलित होंगे, क्योंकि वर्तमान स्थिति स्थायी नहीं है। उपायों को लागू नहीं करने से, भारतीय बाजार में कीमत वृद्धि के लिए कम विश्वसनीय और स्थायी आपूर्ति स्रोत होंगे। अतः प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि शुल्क लगाना व्यापक लोक हित में होगा।

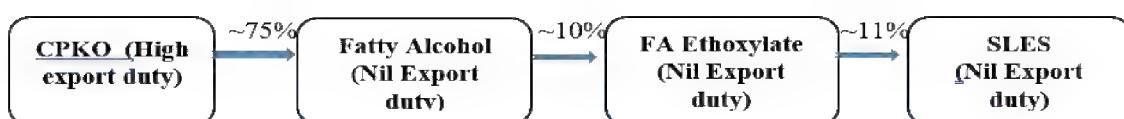
ड. निष्कर्ष

239. दिए गए तर्कों, प्रदान की गई सूचना और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों तथा उपरोक्त जांच परिणामों में दर्ज, प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि:

- विचाराधीन उत्पाद का सब्सिडी प्राप्त कीमतों पर संबद्ध देशों से भारत को निर्यात किया गया है। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण कीमत और मात्रा संबंधी क्षति हो रही है।
- इंडोनेशिया और मलेशिया सरकार ने कच्चे पाम कर्नेल ऑयल (सीपीकेओ) और उसके डेरिवेटिव के निर्यातों पर निर्यात कर और निर्यात उपकर के रूप में निर्यात प्रतिबंध लगाए हैं, जो कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए प्राथमिक कच्ची सामग्री है। यह रिकॉर्ड पर एक स्वीकृत तथ्य है कि इन निर्यात प्रतिबंधों के लगाने का प्रयोजन और उद्देश्य डाउनस्ट्रीम मूल्यवर्धन आँनशोर को प्रोत्साहित करना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऐसे डाउनस्ट्रीम उद्योगों की प्रतिस्थापनका में वृद्धि करना है। रिकॉर्ड पर साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि कथित निर्यात प्रतिबंधों के कारण सीपीकेओ के घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को वास्तव में प्राधिकारी द्वारा विचार की गई उपयुक्त बेंचमार्क से काफी कम विश्व बाजार कीमत पर सीपीकेओ की घरेलू आपूर्ति के लिए मजबूर किया। यह पाया गया है कि लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों और विश्व बाजार कीमत के यप पर सीपीकेओ की आपूर्ति में निजी सीपीकेओ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों के बीच प्रदर्शनीय संबंध है। अतः प्राधिकारी, ने यह पाया है कि सीपीकेओ की घरेलू कीमत और बेंचमार्क कीमत के बीच कीमत का अंतर उक्त देशों द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी के रूप में है।
- प्राधिकारी संबद्ध वस्तुओं पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की एक निर्णायक समीक्षा साथ-साथ कर रहे हैं। ओवरलैप से बचने के लिए, कोई निर्यात सब्सिडी, जिसके कारण निर्यात कीमत कम हो रही है न कि उत्पादन की लागत, अलग से उल्लिखित की गई है और तदनुसार, उपयुक्त शुल्क की सिफारिश की गई है।
- जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के दावे का संबंध है कि घरेलू उद्योग को क्षति इसकी उच्च वित्त लागत और पूंजी लागत की कमी के कारण से है, अतः प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति क्षति का कारण नहीं है, लेकिन यह वास्तव में उनके समक्ष आई क्षति के परिणामस्वरूप है। यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन एक नकदी व्यापक प्रक्रिया है, क्योंकि कच्ची सामग्री में ही करीब 70 प्रतिशत लागत शामिल है। अतः कंपनी की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता तुलनात्मक रूप से अधिक है। तथापि, चूंकि घरेलू उद्योग लाभकारी बिक्रियां करने में समर्थ नहीं रहा है, अतः यह कोई धनराशि उत्पन्न नहीं करता, जिसके कारण इसकी अधिक वित्तीय लागत आई है। किसी भी तरह से, वित्त लागत की तर्कसंगतता की जांच की गई है और केवल ऐसी वित्त लागत की जांच की गई है जो तर्कसंगत पाई थी, उस पर एनआईपी के निर्धारण के लिए विचार किया गया है। इस प्रकार, किसी असामान्य व्याज लागत के लिए क्षति पर, क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया गया है।

v. यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता मिड-कट अल्कोहल का एकमात्र भारतीय उत्पादक है, जिसके पास भारतीय बाजार में सबसे अधिक मांग (करीब 90 प्रतिशत) है। यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि याचिकाकर्ता की वित्तीय स्थिति खराब है और यह उन्हें पर्याप्त संरक्षण दिए बिना कायम नहीं रखा जा सकेगा। इस प्रकार, यदि संबद्ध देशों द्वारा प्रदान की जा रही अमान्य सब्सिडी को निष्प्रभावी नहीं किया जाता है, तो घरेलू उद्योग का मिड-कट अल्कोहल के लिए समान्य हो जाएगा, जिसके डाउनस्ट्रीम उद्योग पूरी तरह से उनकी कच्ची सामग्री की जरूरत के लिए आयातों पर निर्भर होगा। कच्ची सामग्री के व्यवहार्य घरेलू ख्रेत होना भारतीय डाउनस्ट्रीम उद्योग के बड़े हित में है।

vi. यह अनुरोध किया गया है कि संबद्ध देशों के नियांतक फावार्ड इंटिग्रेटेड हैं और एसएफए पर शुल्क लगाए जाने से डाउनस्ट्रीम उत्पादों जैसे इथोजाइलेट और एसएलईएस/एसएलईएस के आयातों में वृद्धि होगी। ओलियाकेमिकल उद्योग की वैल्यू चेन और उनकी वैल्यू चेन की प्रतिशतता इस प्रकार है:-



vii. उपरोक्त से यह देखा गया है कि सीपीकेओ समग्र वैल्यू चेन के लिए प्राथमिक कच्ची सामग्री है। प्राधिकारी ने यहां ऊपर पहले ही निर्धारित किया है कि संबद्ध देशों ने अमान्य सब्सिडी प्रदान की है, विशेष रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया की सरकारों द्वारा एलटीएआर पर कच्ची सामग्री (सीपीकेओ) का प्रावधान। यदि सब्सिडी जारी रहती है और एसएलईएस, एसएलईएस और इथोजाइलेट के लिए कच्ची सामग्री एलटीएआर पर आपूर्ति की जाती है; तो डाउनस्ट्रीम उत्पादकों के पास प्रायः इसके लिए उपयुक्त उपचार की मांग करने का एक विकल्प होगा। तथापि, एक अनुचित व्यापार प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती और इसे ठीक किए जाने की जरूरत है।

viii. यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के पास भारत में काफी मूल्यवर्धन हो रहा है, अतः यह व्यापक जन हित में होगा कि उन्हें संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा सब्सिडी को निष्प्रभाव बनाकर समान भागीदारी वातावरण प्रदान करना व्यापक जनहित में होगा।

ix. यह भी नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद एक औद्योगिक कच्ची सामग्री है। अतः डाउनस्ट्रीम उद्योग अंतिम उपभोताओं को कम से कम आंशिक शुल्क पारित करने के लिए सक्षम होंगे। यह नोट किया जाता है कि अंतिम उपभोक्ता पर यहां तक कि 35 प्रतिशत का प्रभाव भी नगण्य होगा।

८. सिफारिश

240. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और मलेशिया की सरकार, थाईलैंड की सरकार और इंडोनेशिया की सरकार सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और सब्सिडी, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू पर सूचना/साक्ष्य प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार सब्सिडी, क्षति और कारणात्मक संबंध में जांच करते हुए और ऐसे सब्सिडी प्राप्त आयातों से घरेलू उद्योग के सकारात्मक सब्सिडी मार्जिन और वास्तविक क्षति को स्थापित करते हुए, प्राधिकारी का यह विचार है कि सब्सिडी और क्षति को दूर करने के लिए निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना आवश्यक है। अतः प्राधिकारी यहां नीचे दिए गए रूप से और विनिर्दिष्ट तरीके से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं। प्राधिकारी ने दिनांक 02.02.2023 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना फा. सं. 7/01/2022-डीजीटीआर के तहत संबद्ध वस्तुओं (सी10 को छोड़कर) के संबंध में समानांतर निर्णयक समीक्षा जांच में पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने की सिफारिश की है। अनुशंसित एडीडी का समायोजन, जहां आवश्यक हो, नीचे ड्यूटी तालिका में प्रदान किया गया है। इसके अलावा, चूंकि नियांत सब्सिडी के कारण हुई क्षति को निर्णयक समीक्षा के अंतिम निष्कर्षों में पहले ही संबोधित कर लिया गया है, इसलिए नियांत सब्सिडी को यहां अनुशंसित शुल्कों में समायोजित किया गया है।

241. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए सब्सिडी के मार्जिन और क्षति के मार्जिन से कमतर के समान निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं। प्राधिकरण ने इस तथ्य को नोट किया है कि पीयूसी पर पहले से ही पाटनरोधी शुल्क

लग रहा है, तदनुसार, उसका समायोजन, जहां उपयुक्त हो, नीचे तालिका में प्रदान किया गया है। यह उल्लेख किया गया है कि कुछ उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, नीचे कॉलम संख्या 7 में उल्लिखित शुल्क कम शुल्क नियम के अनुसार क्षति मार्जिन पर आधारित है, और इसलिए कॉलम संख्या में निर्दिष्ट शुल्क के अंतर के बराबर काउंटरवेलिंग शुल्क है। नीचे 7 और उस पर देय पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई है। अन्य मामलों में, जहां क्षति मार्जिन कुल सब्सिडी मार्जिन और उस पर देय एंटी-डंपिंग शुल्क से अधिक पाया गया था, वहां एंटी-डंपिंग शुल्क का कोई समायोजन प्रदान नहीं किया गया है।

242. तदनुसार, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से नीचे शुल्क तालिका के कॉलम 7 में यथा उल्लिखित निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष/ उपशीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	सीआईएफ मूल्य के प्रतिशत के रूप में शुल्क राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	2905.17, 2905.19, 3823.70	सेचुरेटेड फेटी एल्कोहल कार्बन चेन लेंथ सी 10 से सी 18 और उनके मिश्रण	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई भी	मैसर्स पीटी इकोग्रीन ओलियोकेमिकल्स	14% *
2.	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई भी	मैसर्स पीटी मुजिम मास	20%*
3.	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई भी	मैसर्स पीटी विलमार नवाटी इंडोनेशिया	27%*
4.	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई भी	मैसर्स पीटी. एनर्जी सेजाहतेरा मास	4%*
5.	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई भी देश	उपरोक्त 1 से 4 के अलावा कोई अन्य	30%*
6.	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड के अलावा कोई अन्य देश	इंडोनेशिया	कोई भी	30%*
7.	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई भी	मैसर्स एफपीजी ओलियोकेमिकल्स एसडीएन बीएचडी	3%*

8.	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई भी	मैसर्स केएल- केपोंग ओलियोमास एसडीएन. बीएचडी	9% #
9.	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई भी देश	उपरोक्त 7 से 8 के अलावा कोई अन्य	11% #
10.	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड के अलावा कोई अन्य देश	मलेशिया	कोई भी	11% #
11.	-वही-	-वही-	थाइलैंड	थाइलैंड सहित कोई भी	मैसर्स थाई फेटी एल्कोहल कंपनी लिमिटेड	3% \$
12.	-वही-	-वही-	थाइलैंड	थाइलैंड सहित कोई भी देश	उपरोक्त 11 के अलावा कोई अन्य	5% \$
13.	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड के अलावा कोई अन्य देश	थाइलैंड	कोई भी	5% \$

* उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 7 के लिए, लगाए जाने वाले काउंटरवेलिंग शुल्क की राशि कॉलम संख्या 7 में उल्लिखित काउंटरवेलिंग शुल्क की मात्रा और देय एंटीडंपिंग शुल्क, यदि कोई हो, के बीच के अंतर के बराबर है। (अर्थात् सीवीडी = ऊपर कॉलम 7 में झूटी माइनस एडीडी, यदि कोई हो)

क्रम सं. 8 से 10 के लिए, लगाए जाने वाले काउंटरवेलिंग शुल्क की मात्रा देय एंटी-डंपिंग शुल्क, यदि कोई हो, के अतिरिक्त है, क्योंकि अनुशंसित सब्सिडी और डंपिंग मार्जिन अति मार्जिन से कम है। (यानी सीवीडी = उपरोक्त कॉलम 7 में झूटी)

\$ क्रम सं. 11 से 13 के लिए, लगाए जाने वाले सीवीडी की मात्रा स्तंभ संख्या 7 में उल्लिखित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क घटाकर देय पाठनरोधी शुल्क, यदि कोई हो, होगी। यदि अंतर राशि ऋणात्मक है, तो ऐसे मामले में कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं वसूला जाएगा। (अर्थात् सीवीडी = ऊपर कॉलम 7 में झूटी माइनस एडीडी, यदि कोई हो)

ण. आगे की प्रक्रिया

243. इस सिफारिश के कारण केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ की जाने वाली कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

अनन्त स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND NDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2023

FINAL FINDINGS

Sub: Final Findings in Anti-subsidy investigation concerning imports of “Saturated Fatty Alcohol” from Indonesia, Malaysia, and Thailand.

A. BACKGROUND OF THE CASE

F. No.6/18/2021-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time thereof:

1. Whereas, M/s. VVF India Ltd. (hereinafter referred as “petitioner” or “applicant”), has filed an application on behalf of the domestic industry before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”) for imposition of countervailing duty on imports of “Saturated Fatty Alcohol” with a carbon chain length of C10, C12, C14, C16 or C18 (not including branched isomers) including single saturated fatty alcohols (also referred to as ‘single cuts’) and their blends (hereinafter also referred to as the “subject goods” or “PUC” or “SFA”) from Indonesia, Malaysia and Thailand (hereinafter also referred to as the “subject countries”).
2. And, whereas, the Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the petitioner, issued a public notice vide Notification No. 6/18/2021 – DGTR dated 8th February, 2022 published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Rule 6 to determine the existence, degree and effect of the alleged subsidy and to recommend the amount of anti-subsidy/countervailing duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:
 - a) The Authority notified the Embassies of subject countries in India about the receipt of the present anti-subsidy application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 6 supra.
 - b) The Authority invited the Government of Indonesia, Malaysia, and Thailand for consultation with the aim of clarifying the situation and arriving at a mutually agreed solution in accordance with Article 13 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. The consultations were held on 21.01.2022 with the Government of Thailand and on 28.01.2022 with the Government of Indonesia and the Government of Malaysia, through video conferencing on account of Covid-19 pandemic. The consultations were attended by the representatives of the Governments of Indonesia, Malaysia, and Thailand. The concerned Governments denied existence of subsidy programs, however, no evidence for the same was provided.
 - c) The Authority issued a public notice dated 8th February, 2022 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating countervailing duty/anti-subsidy investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries.
 - d) The Authority sent a copy of the initiation notification dated 8th February, 2022 to the Embassies of the subject countries, known producers/exporters from the subject countries, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producer as per the addresses made available by the petitioner and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
 - e) In the initiation notification, the Authority had called for comments on the proposed PCN methodology from the interested parties in order to have fair comparison. The comments of the interested parties were considered and thereafter, vide letter dated 10th March, 2022, the interested parties were requested to file their questionnaire response in accordance with the PCN methodology.
 - f) The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 7(3) of the Rules.

g) The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.

h) The Authority sent questionnaires to the Governments of the subject countries in order to seek relevant facts/information with regard to various schemes/programs where countervailable benefit might have been conferred by the Governments.

i) The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject countries, in accordance with Rule 7(4) of the Rules:

- i. PT. Musim Mas, Indonesia
- ii. PT. Ecogreen Oleochemicals, Indonesia
- iii. PT. Energi Sejatera Mas, Indonesia
- iv. PT. Wilmar Nabati, Indonesia
- v. Emery Oleochemicals Sdn. Bhd., Malaysia
- vi. KLK Oleo, Malaysia
- vii. FPG Oleochemicals Sdn Bhd, Malaysia
- viii. Thai Fatty Alcohols Co. Ltd., Thailand

j) In response, the following exporters/producers from the subject countries filed exporter's questionnaire response in the prescribed format:

- i. PT. Musim Mas, Indonesia
Inter-Continental Oils & Fats Pte Ltd. Singapore
- ii. PT. Ecogreen Oleochemicals, Indonesia
EcoGreen Oleochemicals (Singapore) Pte Ltd
- iii. PT. Energi Sejatera Mas, Indonesia
Sinarmas Cepsa Pte. Ltd. Singaporea
- iv. PT. Wilmar Nabati, Indonesia
Natural Oleochemicals Sdn Bhd, Malaysia
Wilmar Trading Pte Ltd Singapore
- v. Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd., Malaysia
Emery Oleochemicals Rika (M) Sdn Bhd
- vi. KLK Oleo, Malaysia
- vii. FPG Oleochemicals Sdn Bhd, Malaysia
Procter and Gamble International Operations SA Singapore
- viii. Thai Fatty Alcohols Co. Ltd., Thailand
Global Green Chemicals Public Co., Ltd. Thailand
- ix. Unilever Asia Private Limited Singapore

k) Pursuant to the initiation notification, apart from the above producers/ exporters from the subject countries, Government of Indonesia, Malaysia, and Thailand have also filed the questionnaire response.

l) The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 7(4) of the Rules:

- i. M/s Galaxy Surfactants Limited
- ii. Viswaat Chemicals Limited
- iii. Rhodia Speciality Chemicals India Ltd
- iv. Indian Glycols Limited

- v. Sterling Auxiliaries Pvt. Ltd
- vi. Matangi Industries
- vii. Venus Ethoxylates Pvt. Ltd
- viii. Gujarat Chemicals
- ix. Aarti Surfactants Limited
- x. Kusa Chemicals Pvt Ltd
- xi. Krishna Antioxidants Pvt. Ltd.
- xii. BASF India

m) In response, the following importers/users have responded and filed importer's questionnaire response.

- i. Godrej Industries Limited
- ii. Galaxy Surfactants Limited
- iii. Viswaat Chemicals Limited
- iv. Indian Glycols Limited
- v. Clariant IGL Specialty Chemicals Pvt. Ltd.,
- vi. Hindustan Unilever Ltd.
- vii. Aarti Surfactants Limited

n) Apart from the respondent exporters and importers mentioned above, some legal submissions have been received on behalf of the following parties during the course of this investigation.

- (i) Indian Surfactant Association

o) Further information was sought from the applicant and the other interested parties to the extent deemed necessary.

p) Due to the ongoing global pandemic of COVID-19, all interested parties were asked to share the non-confidential versions of all their submissions with the other interested parties via emails. Submissions made by all the interested parties to the extent considered relevant have been taken into account in this final findings.

q) The petition was filed based on the import data obtained from Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) for the period 2018-19 to May' 2021. The petitioner had submitted that the data for the period June' 2021 to September' 2021 was not provided to them despite repeated requests. Accordingly, the petitioner had extrapolated the data for the period October' 2020 – May' 2021 for submitting data for the Period of investigation, i.e., October' 2020- September' 2021.

r) Request was made by the Authority to the Directorate General of Systems (DGS) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has considered data obtained from DGCI&S for the period April' 2018 to May' 2021 (corroborated with the DGS data) and DGS data for the period June' 21 to September' 21, for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.

s) The Non-Injurious Price (NIP) has been worked out based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-Dumping Rules has been worked out so as to ascertain whether countervailing duty lower than the subsidy margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

t) Physical inspection through on-spot verification of the information provided by the applicant domestic industry, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of the present final findings.

u) Verification of the information provided by the producers/exporters and Government of Thailand, Indonesia and Malaysia to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority and such verified information has been relied upon for the purpose of present final findings.

v) The Period of Investigation for the purpose of the present anti-subsidy investigation is from October' 2020 to September, 2021 (12 Months). The injury investigation period has however, been considered as the period

2018-19, 2019-20, 2020-21 and the POI. The overlap of six months between 2020-21 and the POI has been kept in consideration, while conducting the injury analysis.

- w) In accordance with Rule 7(6) of the CVD Rules and Trade Notice No. 01/2020 dated, 10th April 2020, the Authority conducted an oral hearing through video conferencing on 7th July, 2022, to provide opportunity to the interested parties to present relevant information orally before the Authority. All the parties attending the oral hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally. Non confidential versions of the written submissions were circulated to the interested parties by email, and opportunity was given to them for submitting rejoinder submissions, if any.
- x) The arguments made in the written submissions/rejoinders received from the interested parties have been considered in the present final findings.
- y) The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in these final findings.
- z) Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- aa) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the final findings on the basis of the facts available.
- bb) In accordance with Rule 18 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide disclosure statement dated 22nd September, 2022 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these Final Findings.
- cc) The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$1 = ₹74.6
- dd) In these final findings, *** represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as:

The product under consideration in the present investigation is "Saturated Fatty Alcohol" a carbon chain length of C 10, C12, C14, C 16 or C 18 (not including branched isomers) including single saturated fatty alcohols (also referred to as 'single cuts') and their blends.

C.1. Submissions made by the other interested parties

5. The submissions made by the exporters, importers, users and other interested parties with regard to the product under consideration and like article, and considered relevant by the Authority, are as follows:
 - a) The petitioner does not produce pure cuts i.e. C10, C12 and C14, and therefore, the same should be excluded from the scope of the PUC.
 - b) C12 and its blends are not commercially substitutable with higher cuts (C1618) being manufactured by the petitioner. They have distinct raw materials, production process and end uses.
 - c) The petitioner is manufacturing C12-14 alcohol from imported distilled fatty acid, which does not involve substantial value addition. The petitioner therefore, cannot be considered as a producer of C1214, and the same should be excluded from the scope of the PUC.
 - d) C12 and its blends are not commercially substitutable with higher cuts (C1618) being manufactured by the petitioner. They have distinct raw materials, production process and end uses.
 - e) The petitioner is manufacturing C12-14 alcohol from imported distilled fatty acid, which does not involve substantial value addition. The petitioner therefore, cannot be considered as a producer of C1214, and the same should be excluded from the scope of the PUC.
 - f) It has also been claimed that C1214 produced by blending pure C12 and C14 has different chemical specification and therefore is not like article to C1214 being imported.

- g) Reliance has been placed on the Anti-dumping Final Findings F. No. 14/51/2016-DGAD dated 23.04.2018, wherein C10 (pure) was held to be not a “like article” to the goods produced by the petitioner, for seeking exclusion of pure C10. It has been submitted that since the petitioner does not manufacture C10 in commercial quantity, it should not be included in the scope of the PUC.
- h) The petitioner is importing penultimate input i.e., C8-10 Fatty Acid from the subject countries and other countries to produce pure C10. Since they are importing penultimate input, they cannot be considered as domestic industry for that product as per the practice of the DGTR followed in recent investigation

C.2. Submissions made by the Domestic Industry

6. The submissions made by the domestic industry with regard to the product under consideration and like article and considered relevant by the Authority are as follows:
 - a) The product under consideration in the present petition is “Saturated Fatty Alcohol” (SFA) of Carbon Chain Length C10 to C18 and their blends. The PUC is used mainly as an intermediary product, for further processing into fatty alcohol sulphates, fatty alcohol ethoxylates and fatty alcohol ether sulphates, also called Surfactants.
 - b) The fatty alcohols are primarily used for the manufacture of surfactants, for personal care, home care, and pharmaceutical and agriculture-related end applications. They are also used in relation to processing of articles of leather, textile, fur, pulp, paper, petroleum products, fine chemicals, rubber products, plastics and fabricated metal products. Other applications include mining, offshore operations, construction work, and as a solvent for degreasing purposes. The PUC is also used as a synthetic intermediate or as anti-freeze and as an emulsifying agent. It also finds use in the production of paints, lubricants, cosmetics, food preparations, etc. The various grades of fatty alcohols can be used inter-changeably. The customer selects the fatty alcohol of a particular carbon chain length, based on its requirement, with regard to viscosity, solubility, foaming properties, etc.
 - c) That the production of various grades (carbon chain length) of SFA is through fractional distillation of CPKO. CPKO inherently consists of various carbon chain length, which are fractionated depending on the desired grade (carbon chain length) that the producer wants to extract.
 - d) The petitioner produces high quality natural saturated fatty alcohols under the registered trade name Vagarol. It has the capacity to manufacture entire range of fatty alcohols from short chain Vagarol C10 (Decyl alcohol) to Vagarol C22 (Behenyl Alcohol), and the decision as to which grade is to be manufactured is taken based on the customer preferences and the demand.
 - e) The majority of imports into India are of C1214/C1216 grade, as the said grade has the highest demand in India. In contrast, presently there is a very limited demand for pure cut C12 and C14 grades. The pure cuts C12 and C14 are interchangeable with the blend C1214.
 - f) In one of the production routes opted by the petitioner, C1214 grade is manufactured using split fatty acid. Split fatty acid (SCPKO) is produced by splitting palm kernel oil. The petitioner carries out fractional distillation of SCPKO to produce distilled fatty acid of the desired composition (i.e., C1214 fatty acid, in the instant case). The C1214 fatty acid is then converted to get C1214 fatty alcohol by using wax ester hydrogenolysis technology. As an alternative, C1214 blend can also be produced by producing pure C12 and C14 grades first and then blending them subsequently through simple process of mixing, without incurring any further cost.
 - g) The choice of manufacturing pure C12 and C14 fatty alcohols and then blending them or directly manufacturing the C1214 grade is dynamic and is decided based on the prevailing factors of market demand and margins. Moreover, in terms of end use, the grades C12, C14 pure cuts and their blend are interchangeable. Further, it is both technically and commercially feasible to simply blend the two pure cuts in a tank, with no additional cost. As such, exclusion of pure C12 and C14 from the product under consideration would defeat the entire purpose of levy of the duty on the PUC. The Petitioner, in this regard, also relies upon the Final Findings F. No. 14/51/2016-DGAD dated 23.04.2018, in the previous anti dumping investigation concerning imports of the subject goods, where the claim for exclusion of pure grade C12 and C14 was rejected by the Authority.
 - h) The petitioner had also submitted that it had produced and sold grade C10 in commercial quantities, therefore, the same cannot be excluded.

C.3. Examination by the Authority

7. The Authority has noted submissions made by the interested parties with regard to the scope of the product under consideration and like article offered by the domestic industry. With respect to the product under consideration, the Authority notes as follows:

- a) The very first step in an investigation is to identify the product under consideration. The product under consideration is the imported product which is allegedly causing injury to the domestic industry. On the basis of the submissions made by the various interested parties and the examination of import data, the Authority holds that the product under consideration in the present investigation is "**Saturated Fatty Alcohol of carbon chain length C10 to C18 and blends thereof**". The product under consideration includes pure C10, C12, C14, C16 and C18, and their blends. The product under consideration is classifiable under CTH 2905 17 (pure cuts) and 3823 70 (blends). Tariff classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.
- b) As regards the claim for exclusion of pure C12 and C14 on the ground that same was not manufactured by the domestic industry, it is noted that this issue has been examined in depth in the Anti-dumping Final Findings F. No. 14/51/2016-DGAD dated 23.04.2018 conducted in respect of the subject goods, wherein it was held as under:

"As regards exclusion of pure form of C12 and C14 alcohols, the Authority finds force in the argument of the domestic industry that it has produced and sold C12C14 alcohol. In fact, C12C14 has the most demand in India. When the domestic industry has sold the blended form of these alcohols, the pure forms cannot be excluded, as such exclusion would defeat the very purpose of the duty.....".

The above findings of the Authority have been confirmed by the Hon'ble CESTAT, New Delhi *vide* Final Order No. 50010-50013/2023 dated 06.01.2023, wherein it was observed as under:

"34. There is, therefore, no error in the finding recorded by the designated authority in including pure cuts C12 and C14 in the product under consideration."

- c) The petitioner had, during on-site verification, demonstrated that C1214 can be produced by a simple process of mixing pure C12 and C14, without incurring any additional cost. It is noted that the decision whether to manufacture C12-14 blend directly or by blending pure C12 and C14, is decided depending on the market demand and customer preferences. If duty is imposed on imports of C1214 blend only and not on pure C12 and C14, it would be possible to circumvent the duty by importing pure cuts C12 and C14 instead of C1214 blend, thereby defeating the very purpose of the imposition of duty. The Authority accordingly notes that pure C12, C14 and their blends are interchangeable and, therefore, cannot be excluded from the scope of the PUC.
- d) Further, the Authority notes that the claim of the interested parties that C1214 produced by blending pure C12 and C14 has a different chemical specification and therefore, is not a like product to C1214 being imported, is devoid of any merit. The interested party has submitted that the technical specification of imported C1214 which shows that it has pure C12 in the range of 70-77%, and pure C14 in the range of 21-30%, and has traces of other pure cuts (upto maximum of 2%) of other carbon chain length C8 & lower, C10 or C16 or above, cumulatively. In this regard, the Authority, at the outset, notes that the claim of the interested parties so far has only been that blending of C12 and C14 (pure cuts) to manufacture C1214 blend is not technically or commercially feasible. However, no evidence has been placed on record to support such a claim. It is only at this belated penultimate stage that a new argument is being made that C1214 produced by blending C12 and C14 (pure cuts) would have a different chemical specification as compared to the C1214 being imported into India. Though a chemical specification of C1214 (purportedly as being imported) has been provided, no such specification has been provided for C1214 (produced by blending C12 and C14). As such, the bald submissions made without any supporting evidence cannot be accepted.
- e) Notwithstanding the above, the Authority notes that the claim of the interested party is that the C1214 being imported into India has traces of SFA of other carbon chain length, which would not be there in C1214 produced by blending pure C12 and C14. In this regard, the Authority notes that, as is the case with most refinery products, any pure grade would inherently have certain residual components. The investigation has shown that even the pure grades manufactured by the domestic industry, such as C1698 or C1898, there is upto 2% trace of SFA of other carbon chain lengths present and hence same was being qualified by the domestic industry as C1698, i.e. C16 – of 98% purity. It is noted that the presence of these traces of SFA of different carbon chain length does not have any significant impact on the quality of the product. Moreover, it is noted that even C1214 produced by blending pure C12 and pure C14 would inherently have traces of other carbon chain length present in the said pure grades.
- f) Further, as regards the claim that the petitioner only does toll manufacturing of C10 and C1214 alcohol, wherein it imports C810 and C1214 fatty acid and then merely carries out the conversion of such fatty acids into C10 and C1214 alcohol respectively, the Authority notes that the said averment is not factually correct. The petitioner has provided evidence of manufacture of C1214 from base raw materials i.e., Palm Kernel Oil sources as well. It is noted that C10 is also generated during the production of C1214. As such, the claim that the petitioner is producing C10 or C1214 only from imported fatty acid is rejected. In any case, as the

petitioner has produced and sold C10 as well as C1214 in commercial quantities, their exclusion is not warranted.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions made by the Domestic Industry

8. The submissions made by the domestic industry during the course of the investigation with regard to the scope of domestic industry & standing are as follows:

- a) There are only two producers of the subject goods in India, viz. VVF (India) Ltd. (the petitioner herein) and Godrej Industries Ltd. ("Godrej").
- b) The petitioner accounts for more than 65% of the total Indian production and therefore has the requisite standing to file the present application as "domestic industry", in terms of Rule 2(b) of the CVD Rules.
- c) In any case, Godrej has been importing the PUC from the subject countries since the past few years. As such, in terms of Rule 2(b) it ought to be excluded from the determination of the petitioner's standing as domestic industry. Once Godrej is excluded, the petitioner would represent the entire eligible domestic production of the PUC in India, and therefore, has standing as a domestic industry.
- d) The petitioner has neither imported the subject goods nor is related to any of the importer or exporter of the subject goods

D.2. Submission of other interested parties

9. The standing of the petitioner as "domestic industry" has not been objected to by the interested parties.

D.3. Examination by the Authority

10. Rule 2(b) of the Rules provides as follows:

"domestic industry means the domestic producers as a whole of the like article or domestic producers whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged subsidized article, or are themselves importers thereof, in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry".

11. The petition is filed by M/s. VVF India Ltd. There are two producers of the subject goods in India, namely, M/s. VVF India Ltd. and M/s Godrej Industries Ltd. The Authority notes that Godrej has imported the subject goods from the subject countries in significant quantities during the period of investigation and thus becomes ineligible to be a part of the domestic Industry. Therefore, being the sole eligible Indian producer, VVF India Ltd. has the standing of the domestic industry. In any case, the petitioner accounts for approximately 65% of the total Indian production. Therefore, even after the inclusion of the production of the subject goods by Godrej Industries Ltd, the petitioner M/s VVF India Ltd. accounts for major share of the Indian production and therefore, for the purpose of this investigation, it satisfies the standing requirement and constitutes the domestic industry in terms of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules, and the Authority holds that M/s VVF India Ltd. constitutes the domestic industry.

E. ISSUES RELATING TO CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions by the Domestic Industry

12. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality issues:

- a) Excessive confidentiality has been claimed by the exporters and governments of the subject countries.
- b) The producers/exporters and the governments have not followed the instructions issued by the Authority while filing the questionnaires.
- c) The exporters have not provided relevant data in even indexed form.
- d) Merely because the domestic industry may not be precisely aware of the way schemes operate, eligibility criteria, application process, etc. does not imply that the same can be claimed confidential.

E.2. Submissions by the other interested parties

13. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality issues:

- a) The non-confidential version of the petition violates the requirements and standards laid down in Rule 7 and 8 of the CVD Rules and Trade Notice No 1/2013 dated December 09, 2013 issued by the DGTR.

- b) The petition does not comply with the Trade Notice no. 10/2018 dated 7th September 2018, which sets standards for disclosure of information in confidential version/non-confidential version of responses filed by the domestic industry and other interested parties with a view to streamlining the investigation process.
- c) The petitioner has claimed excessive confidentiality and filed an incomplete petition.
- d) The petitioner has failed to provide sufficient evidence to substantiate the claims of injuries suffered in terms of sales volume and value, captive consumption and trend of costing data has not been provided.
- e) The petitioner has not provided the minimum information in a non-confidential summary or in indices form for price undercutting and stocks to allow affected parties a meaningful understanding to raise appropriate defence.
- f) The information supplied by the petitioner in its application does not allow reasonable understanding of the magnitude of subsidy margin and injury suffered by the local industry.
- g) The petition does not contain necessary information, and therefore, the initiation of the present investigation is not valid.

E.3. Examination by the Authority

14. With regard to confidentiality of information, Rule 8 of Anti-Subsidy Rules provides as follows:

"Rule 8: Confidential information. (1) Notwithstanding anything contained in subrule (1), (2), (3) and (7) of rule 7, subrule (2) of rule 14, subrule (4) of rule 17 and subrule (3) of rule 19 copies of applications received under subrule (1) of rule 6 or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish nonconfidential summary thereof in sufficient details to permit a reasonable understanding of the substance of the confidential information and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in subrule (2), if the designated authority, is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.

15. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file was not accessible physically due to the ongoing COVID19 global pandemic

16. Submissions made by the domestic industry and the other opposing interested parties with regard to confidentiality to the extent considered relevant were examined by the Authority and addressed accordingly. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

Calculation Methodology

17. Article 14 of ASCM, provides guidelines and methodology for calculating the benefit to the recipient conferred pursuant to paragraph 1 of Article 1 and further provides that any method used by the investigating authority to calculate the benefit to the recipient shall be transparent and adequately explained. Further, any method used by the investigating authority to calculate the benefit to the recipient shall be provided for in their national legislation or implementing regulations of the Member concerned and its application to each particular case shall be transparent and adequately explained. In accordance with the requirement, the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 lays down the methodology of determination of quantum of subsidization. The determination in this investigation is in accordance with these guidelines.

F. DETERMINATION OF SUBSIDY AND SUBSIDY MARGIN

18. The petition filed by the domestic industry provided *prima facie* evidence of the existence of countervailable subsidies in the subject countries to initiate the instant investigation. Government of Indonesia, Malaysia, and Thailand were invited for consultation, with the aim of clarifying the situation and arriving at a mutually agreed solution in accordance with Article 13 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. The consultations were held on 21.01.2022 with Government of Thailand and on 28.01.2022 with Government of Indonesia and Government of Malaysia. The producers and exporters from Indonesia, Malaysia and Thailand were advised to file response to the questionnaire and were given adequate opportunity to provide verifiable evidence on the existence, degree and effect of alleged subsidy program for making an appropriate determination of existence and quantum of such subsidies, if any. Further information, as deemed relevant, was called from the interested parties. The verification of information submitted by the governments of subject countries was conducted on 07.09.2022.

19. The following producers/exporters from Indonesia, Malaysia, and Thailand in addition to the Governments of Indonesia, Malaysia, and Thailand have filed questionnaire responses.

- i. PT Wilmar Nabati Indonesia
Natural Oleochemicals Sdn Bhd, Malaysia
Wilmar Trading Pte Ltd Singapore
- ii. PT Musim Mas Indonesia
Inter-Continental Oils & Fats Pte Ltd. Singapore
- iii. PT. Ecogreen Oleochemicals, Indonesia
Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte Ltd
- iv. Pt. Energi Sejahtera Mas Indonesia
Sinarmas Cepsa Pte. Ltd. Singapore
- v. KL-Kepong Oleomas Sdn Bhd
- vi. Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd
Emery Oleochemicals Rika (M) Sdn. Bhd. Exporter Questionnaire
- vii. FPG Oleochemicals Sdn Bhd.
Procter & Gamble International Operations SA Singapore
- viii. Thai Fatty Alcohols Co. Ltd.
Global Green Chemicals Public Co., Ltd. Thailand
- ix. Unilever Asia Private Limited Singapore

General overview of the alleged Subsidy Programs

F.1. Submissions made by the Domestic Industry

20. The following submissions have been made by the domestic industry:

- i. Exporters have stated "not applicable" on all the schemes on the grounds that the company did not avail the specified programs. However, when a company is eligible for a program, there is no reason to believe it would not have benefited under the program. Thus, either the company should show absence of eligibility or must demonstrate why it has not availed benefit that is available under the program.
- ii. Apropos the subsidy given by the provision of raw material at Less than Adequate remuneration (LTAR), the subject countries as well as their exporters have merely contended that the imposition of export duties is WTO compliant and therefore, not a subsidy. The interested parties have failed to appreciate that the petitioner's allegation is not that the export duties imposed on the raw material is a subsidy, but that the provision of "raw material", such as CPKO at less than world market price is a subsidy. The object of imposition of export duties by the Government of Indonesia and Malaysia is admittedly to ensure supply of raw material to their domestic producers at below world market prices. Moreover, the said governments directly participate in the market and determine the price of raw material. As such, the subject governments have entrusted or directed the raw material suppliers to provide raw material to the local manufacturers at LTAR.

- iii. In respect of schemes granting exemption from import duties and taxes, the governments of subject countries and their exporters have merely contended that the said exemption was for manufacturing goods for exports, and therefore, not countervailable as per the footnote 1 to Article 1 of Agreement on Subsidy and Countervailing Measure (“SCM Agreement”). However, the interested parties have failed to provide any evidence of there being a verification mechanism to ensure that the exemption was not in excess of that required for the production of goods for export. In absence of such evidence being brought on record, the entire exemption availed by the interested parties is countervailable.
- iv. Most of the schemes alleged in the petition, other than provision of raw material at LTAR, has been countervailed by the Authority in previous investigations. The interested parties have not brought any evidence on record to suggest that there has been any change in the said schemes. As such, in the absence of any evidence to the contrary, benefit availed under such schemes ought to be countervailed.

F.2. Submissions made by the other interested parties

21. The following submissions have been made by the other interested parties:

- i. Article 11.3 of the SCM Agreement requires the investigating authority to review the accuracy and adequacy of the evidence provided in a petition in order to determine whether it is "sufficient" to justify the initiation of an investigation. The petitioner has failed to provide such "sufficient evidence". The present initiation therefore is not compliant with the SCM Agreement.
- ii. As regards the scheme relating to provision of primary raw material (CPKO) at LTAR, the petitioner has not substantiated what is the financial contribution that has been made; which is the public or government body that is administering the said program; and what are the legal or official instruments under which the said program has been made.
- iii. The subject countries have merely exercised its sovereign function of imposition of duties and taxes on the export of CPKO. Levy of an export tax or any other form of duty or charges on exports is a legitimate tool afforded to each WTO member under the GATT, 1995.
- iv. There is no entrustment or direction so as to warrant finding of "financial contribution" by the concerned governments. The exporters in this regard have, *inter alia*, relied upon the decision of WTO Panel in **United States – Measures Treating Exports Restraints as Subsidies (US Export Restraint Measures)**, to submit that merely because application of an export restraint measure results in, or has the 'effects of', increase in domestic supply of any goods, it cannot be inferred that the government has 'entrusted' or 'directed' a private body to supply such goods at a subsidised price in the domestic market.
- v. It has also been claimed by the exporters that even if the Authority considers imposition of export restraints as a subsidy, the appropriate benchmark for computation of benefit to the local producers would be the FOB export price of raw material after excluding export tax and/or levy.

22. The response of the interested parties in respect of each subsidy scheme is summarised below and examined under their respective heads.

F.3. Examination of the Subsidy programs alleged by the Petitioner

Indonesia

23. The Authority has examined the following programs provided by the Government of Indonesia:

- i. Program no. 1-Provision of Raw material for Less than Adequate remuneration (“LTAR”)
- ii. Program no. 2-Provision of Coal and Electricity at LTAR
- iii. Program no. 3- Pioneer Industry Status
- iv. Program No. 4- Schemes related to Special Economic Zones
- v. Program No. 5- Export financing and guarantees on preferential terms by the Indonesian Eximbank and Asuransi Asei
- vi. Program No. 6(a)- Bonded Zone
- vii. Program No. 6 (d) & (e)- Import duty exemption and drawback (KITE)
- viii. Program No. 7 - Free Trade Zone
- ix. Program No. 8 - Income tax benefit for listed Investments

- x. Program No. 9- Covid-19 relief packages
- xi. Program No. 10- Provision of Natural Gas at LTAR
- xii. Program No. 11 - Preferential lending rates

(i) Program 1: Provision of Raw material for Less than Adequate remuneration (“LTAR”)

a. Submission by the Petitioner

24. The petitioner has submitted that Crude Palm Kernel Oil (including its derivatives such as Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil (RBDPKO), Split CPKO etc., hereinafter collectively referred as “CPKO”), is the primary raw material used for manufacture of the subject goods and accounts for more than 70% of the total cost of production. The local price at which CPKO is made available in Indonesia is distorted because of direct intervention by the Government of Indonesia (“GOI”) in the market. In particular, the petitioner has indicated that the GOI has implemented a policy of imposing high export tax and levy on CPKO, to ensure that the raw material is available to the Indonesian domestic producers at below market price. It has been claimed by the petitioner that the Government of Indonesia, through provision of principal raw material at LTAR has provided subsidy in the form of “financial contribution”. In alternate, the petitioner has claimed that provision of raw material at LTAR also falls under the purview of “price or income support” as the very purpose of the imposition of export restraints is to ensure supply of raw material at LTAR, and therefore is a subsidy as defined under Section 9 of the Customs Tariff Act, 1975.
25. Indonesia along with Malaysia is the biggest supplier of CPKO, catering to more than 90% of the world’s demand of CPKO. Indonesia alone accounts for more than 65% of world’s CPKO production, and therefore, its policies have a major impact on global market price of CPKO.
26. The petitioner had submitted that the GOI has imposed export tax and export levy on export of CPKO and its derivatives to ensure their availability to its domestic downstream producers (such as SFA producers) at below world market prices. It has contended that the export tax and levy have increased significantly from December’ 2020 onwards. Consequently, the global price of the raw material has also increased significantly. However, the local price of raw material in Indonesia has remained significantly lower than global prices.
27. It has also been claimed by the petitioner that the GOI through a wholly owned body PT Perkebunan Nusantara (“PTPN”), a CPO/CPKO producer, directly participates in the market and acts as a price setter for the sale and purchases of CPKO and its derivatives in Indonesia. PTPN sets the domestic prices of the feedstock, and all local sales of CPKO in Indonesia are invariably at prices decided by PTPN or at lesser price, which is significantly lower than the world market price. It has therefore been submitted that the cost of raw material is heavily subsidised in Indonesia. The petitioner has relied upon the following documents in support of its allegations:

- i. Amending Regulation No. 128/PMK.011/2011
- ii. Presidential Regulation No. 61/2015
- iii. WTO Trade Policy review of Indonesia, 2020

b. Submission by the Government of Indonesia/ other interested parties

28. GOI has submitted that imposition of export tax/ levy is a sovereign function of the Government. Moreover, there is no evidence of oversupply of CPKO in Indonesia consequent to increase in export taxes, as it is fully absorbed in domestic and export market.
29. The application of export tax and levy on CPKO is to secure Indonesian public interest through ensuring availability of CPKO for local industries, and has nothing to do with the pricing policy of CPKO in Indonesia.
30. Export tax and levy applied by Indonesia for export of CPKO do not render any financial contribution nor does it constitute any government entrusted fund within the meaning of the WTO Agreement on Subsidy and Countervailing Measures (SCM Agreement/ASCM).
31. It is impossible for PTPN to control the CPKO’s price in Indonesia as it holds only 3% of the total CPKO production in Indonesia. Moreover, CPKO in Indonesia is sold based on fair and transparent auction and that the rest of CPKO producers i.e., 97% of the total CPKO production are free to determine their price based on its commercial decision having in mind the production cost and the competition among them.
32. According to them, there is no evidence that PTPN sets the price of the raw material. The tender price of PTPN is set considering various factors. PTPN sells to the highest bidder and the prices that PTPN can get in public tenders will not only depend on the price at which PTPN would like to sell, but also the price that purchasers are willing to pay.

33. The exporters have also claimed that the benefit computation, if at all, has to be made considering the export price of CPKO after excluding export duty and levy imposed on such exports.

c. Examination by Authority

34. The Authority notes that CPKO is the primary raw material used for manufacture of subject goods being exported to India. It has been claimed by the petitioner that the price of CPKO is distorted in Indonesia on account of government intervention. In particular, the petitioner has claimed that the raw material price distortion is a direct consequence of imposition of export taxes and export levy on exports of CPKO and its derivatives. It has been claimed that by imposing high export taxes and levies on CPKO, the GOI has a depressing effect on the domestic CPKO price in Indonesia, conferring a discernible benefit to the producers of subject goods who use CPKO as their primary raw material. Further, it has been submitted that through imposition of taxes on exports of CPKO, GOI encourages private CPKO producers to sell their products to Indonesian fatty alcohol producers at below world market price. In addition, the petitioner has alleged that the GOI directly interferes in the market through a state body, PTPN, which sets the domestic market price of CPKO. By consequence, the petitioner has alleged that the GOI entrusts or directs Indonesian palm oil producers to provide CPKO to SFA producers for less than adequate remuneration.

35. The Authority notes that CPKO alone accounts for about 70% of the cost of production of the subject goods. Indonesia and Malaysia together cater to almost 90% of the global demand of CPKO, with Indonesia capturing the bigger share. As such, these countries being almost exclusive supplier of the raw material dictate the world market price of CPKO and its derivatives.

36. The Authority further notes that the GOI has implemented a systematic and structured export tariff system for imposing export tax on Palm Oil, Palm Kernel Oil and their derivatives. The export tax on these products was first implemented in 1994. Since its introduction, it has been amended a number of times and was substantially restructured in 2011. This new tax structure provided for a wider duty difference between crude and refined oil, with a view to encourage more refining and value addition onshore. The legislation specifically stated that *'in the context of supporting the downstream efforts of the palm oil industry to increase added value downstream it is necessary to restructure export duty tariff'*.

37. The export tax on CPKO during the POI was regulated by Decree No 166/PMK.010/2020, which has amended Regulation PMK No. 13/PMK.010/2017. It is noted that in addition to the aforesaid export tax, the export of CPKO and their derivative are also subject to export levy under Regulation PMK 57/PMK.05/2020 as amended by PMK 76/PMK.05/2021. Under the amended regulation, export of CPKO is subject to export levy in the range of USD 55-USD 175 per ton, depending on the reference export price of CPKO. As per the Questionnaire response filed by GOI, the reference export price of CPKO is a weighted price computed on the (i) average CPKO price for CIF Rotterdam, (ii) average CPKO price of Malaysian Bursa and (iii) average CPKO price of Indonesia Bursa, with each accounting for 20%, 20% and 60% of weight respectively. The reference price so set, then determines the export tax and levy applicable for the month. As provided in Article 5 (1) of PMK No. 13/PMK.010/2017, the determination of which of the twelve columns in the tariff schedules applies is dependent on the reference export price of the product involved. It has been submitted by GOI that the export taxes are progressive in nature, i.e., higher export prices command higher tariff rates.

38. From the above, the Authority notes that the GOI has linked the export tax and levy clearly to a "reference price", which is based on the international price of CPKO. These export tax and levy are not related to any other concerns, such as public interest, production levels or environmental impact.

39. It is noted that though the Indonesian export tax regime has undergone several changes since 2011, however, the purpose and object of imposition of export taxes continue to be for promoting downstream industry of domestically processed products. In this context, it is noted that the WTO Trade Policy Review of Indonesia, 2020, had also concluded that the purpose for imposition of export taxes (including export levy) by the Government of Indonesia is for *fostering the development of downstream processing facilities, ensuring domestic supply of intermediate inputs at below world market prices*. Thus, evidently, the purpose and object behind imposition of export taxes by GOI is to ensure availability of raw material to its domestic industries.

40. It is also noted that the GOI in addition to imposition of export taxes, also directly participates in sale and purchase of the raw material in Indonesian market. The state-owned company PTPN, through its marketing arm "KPBN", conducts open auction to sell its CPKO at a "price idea". The tender price or the price idea set by PTPN is a public price, known to all market operators. It was found that the contracts between private companies also use the "price idea" set by PTPN. The investigation also revealed that even the contracts between related parties are broadly on the price set by PTPN. It has been observed that the price paid by the responding exporter to the CPKO supplier were lower or in the same range as PTPN price. Therefore, it has been found that the transactions concerning sale and purchase of CPKO and derivatives in Indonesia happen at or around the "price idea" set by PTPN. It is also noted that this "price idea" is substantially below the world market price of CPKO, such as export price from Indonesia or CIF Rotterdam prices (adjusted for freight and insurance). For the purpose of the

present final findings, the Authority has considered average CPKO CIF Rotterdam prices (adjusted for freight and insurance) as representative of undistorted market price of CPKO, and has been referred herein below as “world market price”.

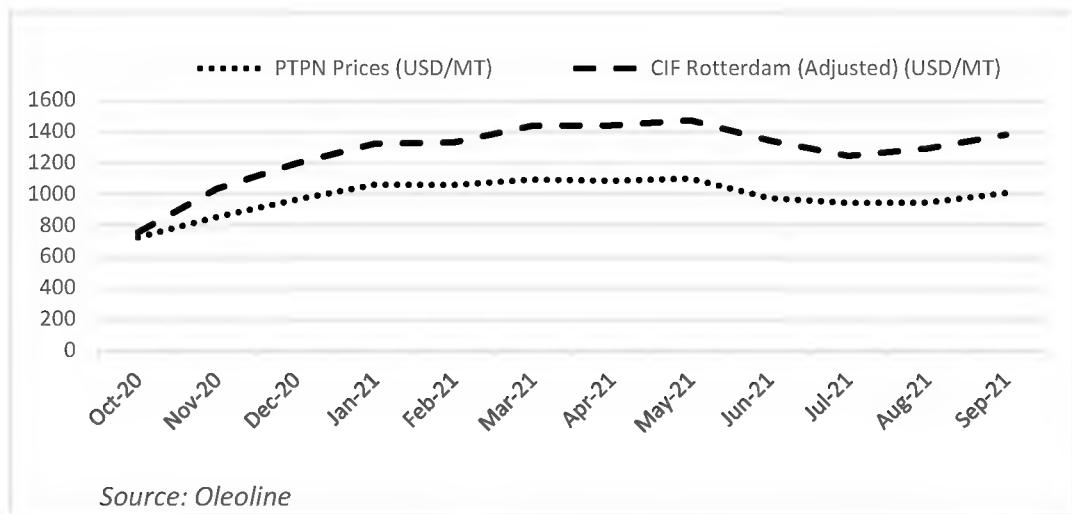
Financial contribution by GOI

41. Explanation to Section 9(1) of the Act read with Article 1.1 of the Agreement on Subsidy and Countervailing Measures (“ASCM”) provides that a “subsidy” is deemed to exist if there is “financial contribution” by the government or any public body in the exporting or producing country or territory, or when such government grants or maintains any form of “income or price support”, and a benefit is thereby conferred. Financial contribution by a government or public body is said to exist where:
 - i. Government practice involves a direct (or potential) transfer of funds,
 - ii. Government revenue that is otherwise due is foregone or not collected,
 - iii. Provision of goods or services, other than general infrastructure, or purchase of goods by Government, or
 - iv. Government makes a payment to a funding mechanism, or entrusts or directs a private body to carry out one or more of the type of functions specified in clause (i) to (iii) above.
42. “Financial contribution” by a government or public body is an essential component of a “subsidy” under the Section 9. A financial contribution, however, need not always be a direct contribution by the government but can also exist where a government indirectly, through its policy measures, entrusts or directs private parties to supply goods (raw material) at below world market prices. The Authority had in several past investigations, such as in anti-subsidy investigation concerning imports of “Continuous Cast Copper Wire Rods” *inter alia* from Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam, and “Certain Hot Rolled and Cold Rolled Stainless Steel Flat Products” from China, held that a countervailable subsidy in the form of “financial contribution” exists where the object and intent behind imposition of export restraints on raw material is to ensure availability of such raw material to downstream industries at LTAR.
43. The Authority notes that the export tax and export levy system was devised and enacted by the GOI precisely to support the downstream industries which use CPKO, such as producers of the subject goods. Through imposition of these export restraints, the GOI puts the suppliers of CPKO in an economically irrational situation, which induces them to sell their goods domestically for a lower price than they could obtain in absence of these export restraints. GOI effectively restricts the freedom of action of CPKO suppliers by *de facto* limiting their business decision at what price to sell their product and where. Absent these measures, the CPKO suppliers acting rationally would have tried to sell at competitive rate in international market and maximize their profits.
44. Further, Indonesia being one of the two main suppliers and price setter of CPKO, these export restraints also achieve the purpose of ensuring that the price at which CPKO is made available in Indonesia is substantially below world market price. It is thus, evident that through GOI’s policy measures, CPKO is being provided at less than adequate remuneration to Indonesian producers of SFA. The Authority notes that the lower raw material prices paid by the Indonesian SFA producers is not incidental but the direct and intended result of the measures designed by the GOI.
45. The GOI and also responding exporters have relied upon the decision of *WTO Panel in US Export Restraints* to argue that mere imposition of “export restraints” is not a subsidy, as there is no “financial contribution” by the Government. In the same vein, it has been argued that even if GOI’s export tax policy results in lowering of domestic price of CPKO, it is not a “financial contribution” as there is no entrustment or direction by the GOI to private CPKO suppliers to supply CPKO to its local SFA producers at less than adequate remuneration. It has been submitted that imposition of export tax is a sovereign exercise of power and therefore, cannot be considered as a subsidy. They have also relied on various other WTO case-laws to substantiate their argument that export restraints are not countervailable subsidies.
46. As regards the first leg of the said argument, the Authority notes that it does not consider imposition of export restraints *per se* to be a countervailable subsidy. However, the investigation has revealed that the imposition of export taxes and export levies are in fact a means or a tool being used by the GOI to provide CPKO for less than adequate to their domestic downstream industry. It is the provision of CPKO at less than adequate remuneration, through a systematic and targeted imposition of export tax and export levies, which has been found to be countervailable.
47. The Authority notes that the determination of whether there is a ‘financial contribution’ under Article 1.1(a)(1) of the ASCM should focus on the nature of the government action, rather than on the effects or the results of the government’s action. In other words, a government’s rights to interfere in its domestic market in regular exercise of its sovereign and regulatory powers cannot be categorised as a “subsidy”, even if such interference results in conferring of a benefit to its domestic producers. In this sense, a government may legitimately impose export

taxes for the purpose of generating revenue. In contrast, there is no such legitimate imposition of export restrictions when it becomes evident that the use of such an instrument together with other mechanisms is primarily to keep commodities in the domestic market, and to force suppliers to sell below world market prices. What is relevant to be examined is whether the government's policy is engineered in such a way that it focuses on supporting a particular industry or set of industries to boost their competitiveness in domestic and international markets. Thus, the nature of the government action, including its context, object and purpose, is relevant in assessing whether it would fall under the purview of 'financial contribution'.

48. As noted above, the scheme of export tax and levy implemented by GOI is structured in a way that it ensures availability of CPKO to the Indonesian downstream industries at LTAR, and is not a revenue generation measure. In fact, the purpose of restructuring of export taxes in 2011 itself was to enhance the competitiveness of the domestic processing industries in Indonesia. A presentation given by Dakut Dr. Choo Yuen May (the then Director General, Malaysian Palm Oil Control Board, Ministry of Plantation Industries and Commodities) on 2nd Feb, 2016¹, also records that the purpose restructuring of export taxes by Indonesia was to ensure availability of cheaper raw material to its downstream industries and to increase the competitiveness of such downstream industries. Thus, the Authority finds that the nature, context and object of the GOI's action is such that it squarely falls within the purview of "financial contribution".
49. As regards the second leg of the argument advanced, it needs to be seen whether through the above action, the GOI has entrusted or directed the private suppliers of CPKO, to provide goods at LTAR to their SFA producers. In this context, the interested parties have relied on the WTO panel decision in *US Export Restraints* wherein it was ruled that the ordinary meaning of the two words 'entrust' and 'direct' in Article 1.1(a)(1)(iv) of the ASCM require that the action of the government must contain a notion of delegation (in the case of entrustment) or command (in the case of direction). It rejected the US 'cause-and-effect argument' and asked for an explicit and affirmative action of delegation or command. However, it is noted that in the subsequent case of *United States-Countervailing Duty Investigation regarding Dynamic Random Access Memory Semiconductors (DRAMS) from Korea*, the Appellate Body disagreeing with Panel in US- Export restraints, held that the replacement of the words 'entrusts' and 'directs' by 'delegation' and 'command' is too rigid as a standard. It was held that the panel's interpretation of "entrustment" or "direction" in US- Export restraints case was unduly narrow.
50. On a perusal of the Appellate Body report, the Authority notes that for establishing "entrustment" or "direction", there must be some affirmative action or role by the government. It is noted that while ordinarily, one would expect entrustment or direction on a private body to involve some form of threat or inducement, which could, in turn, serve as evidence of such entrustment or direction, however, in the present day, such explicit tools may rarely be used, as governments have other means at their disposal to exercise authority over a private body some of which may be '*more subtle*' than a command or may not involve the same degree of compulsion. In such cases, entrustment and direction may be established by probative and compelling circumstantial evidence. There must, however, be '*a demonstrable link*' between the government act and the conduct of the private body. The Appellate Body had in fact held that in some circumstances, '*guidance*' by a government can also constitute a direction.
51. As per the said Appellate Body report, what needs to be examined is whether there is a demonstrable link between the measure at issue, and the conduct of the private bodies, i.e. whether there is any connection between imposition of export tax and levy by the GOI, and the price at which CPKO is being supplied locally by the private suppliers. In this regard, notwithstanding the fact that GOI directly participates in the market through its state body PTPN, which effectively acts as a CPKO price setter in the domestic market, the Authority notes that the imposition of export taxes with the objective of making raw material price cheaper in the domestic market, itself is a sufficient evidence of entrustment or direction. Further, it is noted that the low domestic price of CPKO in Indonesia is not merely a side-effect of the export restraints, but is in fact the very object and the intended consequence of imposition of these export restraints.
52. Moreover, the investigation has revealed that in practice, the export tax and levy have achieved their intended objective of depressing the domestic CPKO prices. It has been found that there is a significant price difference between the CPKO purchase price of the participating exporters and the world market price of CPKO. The Authority, therefore, notes that there is a demonstrable link between the export restraints imposed and the conduct of the private bodies. Thus, the examination of facts clearly show that imposition of export tariffs has in fact depressed the domestic prices of CPKO. This is also a clear indicator of the fact that the GOI, through its policy measures, has put the suppliers of CPKO in an economically irrational situation to sell in the domestic market at lower prices.

¹ <http://www.mpoct.org.my/upload/Domestic-Measures-to-Enhance-the-Competitiveness-of-the-Palm-Oil-Industry.pdf>



53. Additionally, the investigation has shown that GOI, through PTPN, directly participates in the market and sets the domestic price of the raw material. The price set by PTPN is distorted and below world market prices.
54. Given these facts, the Authority notes that the GOI through imposing of export restraints in the form of export tax and levy, has “entrusted” and “directed” private CPKO suppliers to supply raw material (CPKO and derivatives) to the downstream manufacturers at below world market price, i.e., at LTAR, resulting in a financial contribution.
55. The Authority notes that the program is also specific as it is applicable only to industries using CPKO or its derivatives as raw material. The Authority further notes that a discernible benefit is conferred by such financial contribution, as it directly results in lowering of raw material cost of the Indonesian producers. Therefore, the Authority holds this program as countervailable.

Computation of subsidy

56. The subsidy margin has been computed by comparing the purchase price of CPKO provided by the responding exporter, with the international benchmark price. In the disclosure statement, the Authority had considered CPKO export prices from Indonesia to the rest of the world as benchmark as they are set according to free market principles, reflect prevailing market conditions in Indonesia, and are not distorted by government intervention. The subsidies on this benchmark were found to be in the range of 20-50%. However, since CPKO CIF Rotterdam prices have been considered as benchmark for computing subsidy being provided by Government of Malaysia, for the purpose of present findings, the Authority finds it appropriate to use the same as a common benchmark for both Indonesia and Malaysia. It is noted that CPKO Rotterdam price is a global benchmark for trade in palm kernel oil. The Rotterdam price represents the undistorted price for CPKO, and is an index similar to London Metal Exchange for metal products. Even the GOI considers CIF Rotterdam prices for determining the “reference price” for the levy of export duty. In view thereof, and in order to adopt a uniform benchmark for both Indonesia and Malaysia, the Authority has considered the CPKO Rotterdam price, after adjusting freight and insurance, as the appropriate benchmark for both Indonesia and Malaysia, and the subsidy margin thereon has been determined accordingly.
57. Many interested parties have claimed that the export tax and export levy should be excluded from the CIF price, for determining the benchmark price. The Authority does not find any merit in the said submission, as what has been considered for comparison is the world market price of CPKO (as adjusted for freight and insurance) and the local price onshore Indonesia. The benchmark considered is reflective of the undistorted market price of CPKO. It has been noted that Government of Indonesia, by imposing export and export levy, has depressed the local price of CPKO below the world market price. It is noted that the difference in the world market price and the local Indonesian price of CPKO is primarily on account of such export tax and export levy. As such, deduction of export tax and export levy would defeat the very purpose of this comparison.

Schemes other than supply of CPKO at LTAR

58. It is noted that in case of Indonesia, the petitioner has alleged a total number of 12 subsidy schemes and accordingly the responses were received in respect thereof from the respective producers/exporters and the Government of Indonesia. However, during the examination, it is observed that the subsidy margin quantified for the Program I i.e., Provision of Raw Material at Less than Adequate Remuneration itself exceeds the injury margin worked out for the participating and non-participating producers/exporters from Indonesia. Since, India follows the principle of Lesser Duty Rule i.e., duty equal to the lesser of margin of subsidy and margin of injury is recommended, therefore, even if other schemes are examined in detail and held to be countervailable and thereby subsidy margins are quantified, it would have no impact on the quantum of duty to be recommended by

the Authority but would be merely an academic exercise in the facts and circumstances of the present investigation. In view of the above facts, the principle of judicial economy is applied and the examination is restricted to the abovesaid 1st scheme only.

Producers/exporters from Indonesia

PT. Wilmar Nabati, Indonesia, Natural Oleochemicals Sdn Bhd, Malaysia and Wilmar Trading Pte Ltd Singapore (WINA Group)

59. PT Wilmar Nabati ("Wilmar") is the producer-exporter of the subject goods. It has exported the subject goods to India through its related trader Wilmar Trading Pte Ltd Singapore. Wilmar has claimed that they have not received any subsidy. However, it is noted that Wilmar has used domestically procured CPKO at LTAR for manufacture of Methyl Ester which has been used for manufacturing PUC. The subsidy availed by Wilmar is as below:

Programs	Subsidy Margin	Range
Supply of CPKO at LTAR	***%	30-40%

PT. Musim Mas, Indonesia and Inter-Continental Oils & Fats Pte Ltd. Singapore (PTMM Group)

60. PT. Musim Mas ("PTMM") is producer of the subject goods. It has exported to India through Inter-Continental Oils & Fats Pte Ltd. Singapore. It is noted that PTMM has used domestically procured CPKO at LTAR for manufacture of subject goods. PTMM has received benefit is as below:

Programs	Subsidy Margin	Range
Supply of CPKO at LTAR	***%	25-35%

PT. Ecogreen Oleochemicals, Indonesia and Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte Ltd (PTEO Group)

61. PT Ecogreen Oleochemicals ("PTEO"), is the producer of subject goods and has exported to India through its related trader Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte. Ltd. It is noted that PTEO has procured CPKO locally at LTAR, which it has consumed in manufacture of the subject goods. Subsidy margin determined for PTEO group is as under:

Programs	Subsidy Margin	Range
Provision of CPKO at LTAR	***%	20-30%

PT. Energi Sejatera Mas, Indonesia and Sinarmas Cepsa Pte. Ltd. Singapore (ESM)

62. Pt. Energi Sejatera Mas ("ESM") is the producer of the subject goods and has exported to India through its related trader Sinarmas Cepsa Pte.Ltd. (SCPL). It is noted that ESM has procured CPKO at LTAR, for production of the subject goods. Subsidy margin determined for ESM group is as under:

Programs	Subsidy Margin	Range
Provision of CPKO at LTAR	***%	20-30%

Summary of Subsidy Program for Indonesia

63. Countervailing duty for all other producers/exporters from Indonesia has been determined based on the highest of the subsidy margins for the cooperating parties for the subsidy availed by them:

Name of the Program	Subsidy Margin %	Range%
Provision of CPKO at LTAR	***%	30-40%

*no export subsidy considered for Indonesian producers/exporters

MALAYSIA

64. The Authority has examined the following programs provided by the Government of Malaysia:

i.	Program no. 1	Provision of CPKO at less than adequate remuneration
ii.	Program no. 2	Schemes identified as “grants” <ul style="list-style-type: none"> a) Market Development Grant (MDG) b) Export Credit and Export Financing c) Buyer Credit Guarantee d) Techno fund e) Inno fund f) Cradle Investment Program
iii.	Program no. 3	Business/industry excellence award
iv.	Program no. 4	Schemes identified as Tax incentives <ul style="list-style-type: none"> a) Pioneer status b) Investment Tax Policies/ Allowance c) Re-investment Allowance d) Accelerated Capital Allowance
v.	Program no. 5	Group Relief
vi.	Program no. 7	Industrial Building Allowance
vii.	Program no. 8	Incentive for Small and Medium enterprise
viii.	Program no. 9	Tax Incentive for in house R&D
ix.	Program no. 10	Double Deduction for Research and Development
x.	Program no. 11	Double Deduction for promotion of Malaysian brand
xi.	Program no. 17	Double Deduction for promotion of exports
xii.	Program no. 18	Allowance for increased Export
xiii.	Program no. 19	Tax exemption for Free Trade Zone
xiv.	Program no. 20	Schemes identified as Loans <ul style="list-style-type: none"> a) Research and Development Fund b) Soft Loans to Small and Medium Enterprise
xv.	Program no. 22	Schemes for provisions of land at LTAR
xvi.	Program no. 23	Schemes for provision of electricity at LTAR
xvii.	Program no. 24	Sales Tax Exemption on Raw Materials / Packaging Material
xviii.	Program no. 25	Exemption from import duty and Sales tax on machinery, equipment and spare parts
xix.	Program no. 26	Accelerated Capital Allowance on Information and Communication Technology Equipment and qualified plant expenditure, and Special Allowance for small value assets
xx.	Program no. 27	Deduction for Audit Expenditure, Secretarial fee and filing fee
xxi.	Program no. 28	Balancing Allowance
xxii.	Program no. 29	Grant for promotion of production of Oleo derivatives
xxiii.	Program no. 30	Covid -19 relief measures
xxiv.	Program no. 31	Preferential lending

F.4. Examination of the Subsidy programs alleged by the Petitioner

(i) Program No. 1 - Provision of raw material (CPKO and its derivatives) at LTAR

a. Submission by the Petitioner

65. The petitioner has submitted that the Government of Malaysia (“GOM”) imposes export tax on the export of CPKO. The primary objective of these export taxes is to depress the domestic price of CPKO in Malaysia, thereby making it available to the domestic producers at less than adequate remuneration. Accordingly, it has been submitted that the raw material price in Malaysia is distorted and is below the market prices. It has been alleged by the petitioner that the object behind imposition of export tax on raw material is to subsidize the cost of production of the Malaysian SFA producers, so that they are able to match the subsidized production cost of the Indonesian manufacturers. For achieving the said object, the GOM has imposed export duty of 10% on exports of CPKO from January, 2021

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

66. The GOM has submitted that the object and purpose of imposition of export duty on CPKO is to encourage palm industry players to produce high value-added downstream products as well as to boost its exports through new companies and existing industry players. It has been claimed that the export duty is a revenue collection measure and therefore, is not a countervailable subsidy.

67. The GOM as also responding exporters have relied upon the decision of WTO Panel in **US – Export Restraints** to argue that mere imposition of “export restraints” is not a subsidy, as there is no “financial contribution” by the Government.

c. Examination by the Authority

68. The Authority notes that the GOM imposes export duty on export of CPKO and its derivatives. In its Questionnaire Response, GOM has admitted that the object and purpose of imposition of export duty is to encourage manufacturing of value added downstream products. The Authority notes that Malaysia, after Indonesia, is the second largest supplier of CPKO. GOM, by imposing export tax on CPKO, distorts the raw material prices in Malaysia and thus, ensures that the same is available to the Malaysian SFA producers below market price.

69. It is noted that the export tax regime in Malaysia is structured in such a way that increases the competitiveness of the Malaysian downstream industries and provides them the same advantage as being enjoyed by the Indonesian downstream producers. In the presentation given by Tan Sri Datuk Dr. Yusof Basiron, the then Chief Executive officer, Malaysian Palm Oil Council², the object behind imposition of export tax by Malaysia was noted (in Slide 13) as under:

- i. to help Malaysian oleochemical (which includes SFA) industry to compete better, the Indonesian advantage (on account of export taxes) must be neutralised.
- ii. In an oligopolistic market, with few suppliers (only two), **if one player subsidised the three sectors, the other player must do the same to maintain market share**

70. Thus, evidently, the purpose of the export tax imposed by Malaysia on exports of CPKO is to replicate the subsidy provided by GOI to its downstream manufacturers, so as to ensure that the Malaysian downstream producers have the same advantage as their Indonesian counterparts. The Authority has in depth examined the “financial contribution” being provided by GOI by supplying CPKO at LTAR. The Authority holds that the reasoning provided therein squarely applies to the present scheme and the same is not being reproduced here for the sake of brevity.

71. The Authority notes that export duty imposed on CPKO by GOM is specifically designed to promote manufacture of downstream products like SFA by making raw material available below world market prices and is not a revenue generation measure. Through imposition of export tax, the GOM has put its domestic suppliers of CPKO in an irrational situation to sell CPKO to domestic manufacturers at below world market prices. The Authority notes that, similar to Indonesia, there is a demonstrable link between the imposition of export tax and the price at which CPKO is being sold to the SFA producers by the private bodies. The comparison of the CPKO purchase price with the world market prices (CIF Rotterdam, adjusted for freight and insurance) clearly show that CPKO was being sold to the Malaysian producers at less than adequate remuneration. The act of the private CPKO supplier to supply CPKO at a price lower than world market price is in line with the GOM’s policy of ensuring increased competitiveness of domestic downstream producers. It is therefore noted that the GOM, through imposition of export restraints, entrusts or directs the private suppliers of CPKO to sell CPKO at less than adequate remuneration to downstream SFA manufacturers.

72. As regards, reliance placed by the interested parties on the decision of the WTO panel in *US-Exports restraints*, the Authority has already noted above that the same was considered by the WTO Appellate Body in **United States- Countervailing Duty Investigation regarding Dynamic Random Access Memory Semiconductors (DRAMs) from Korea**, wherein it was noted that for entrustment or direction, the action of private bodies cannot be inadvertent or a mere by-product of governmental regulation. There must be a demonstrable link between the government and the conduct of the private body. It was noted by the Appellate body that even a “guidance” by the Government may constitute entrustment. The Appellate Body had also noted that the interpretation made by the Panel in US- Export Restraints was unduly “narrow”.

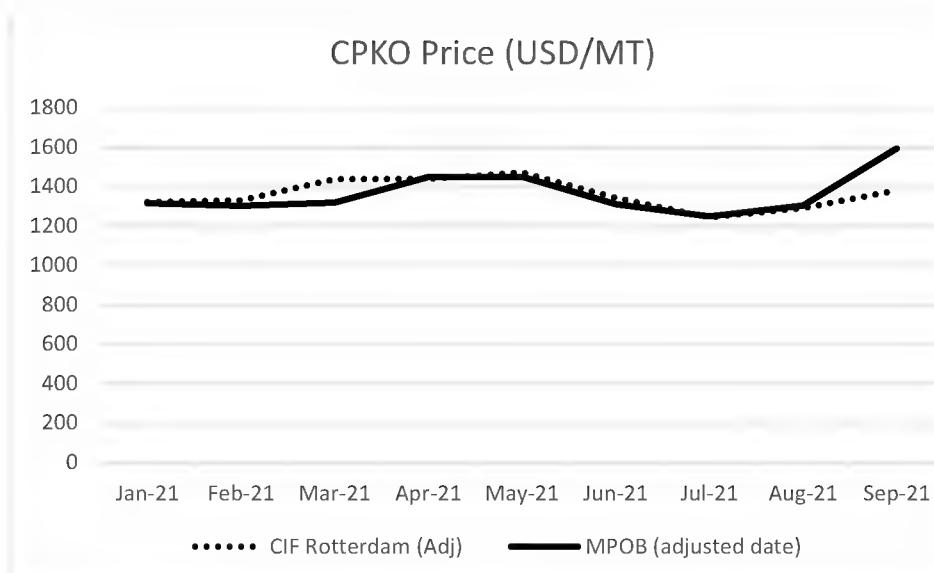
73. The Authority therefore notes that the GOM has provided financial contribution in the form of provision of CPKO at LTAR and a benefit is thereby conferred as it directly reduces the raw material cost of the Malaysian SFA producers. The Program is also specific as it is applicable to industries using CPKO as raw material. The Authority accordingly holds the program countervailable.

² <http://www.mpoc.org.my/upload/P1%20-%20Tan%20Sri%20Yusof%20Basiron.pdf>

Computation of Subsidy

74. The Authority has considered CPKO Rotterdam price as the appropriate benchmark for computation of subsidy. It is noted that export taxes were re-introduced in Malaysia from January, 2021 onwards. Accordingly, the Authority has considered CPKO purchases made by Malaysian exporters for computation of subsidy margin. It is noted that CIF Rotterdam is a global benchmark for trade in palm kernel oil. The Rotterdam price represents the undistorted price for CPKO, and is an index similar to London Metal Exchange for metal products. In fact, domestic industry as well as many exporters have stated that they use CIF Rotterdam prices for negotiating their contracts in regular course of business.

75. Moreover, the Authority notes that CIF Rotterdam prices are the contract date prices and therefore, are more appropriate benchmark, considering that the export tax on CPKO in Malaysia was Nil in the beginning period of the POI. Since the export tax was reimposed only in January, 2021, the shipments made in the beginning period would not have factored in the export tax component. On examination, it is found that there is generally a 30–45 days' time lag between finalisation of the contract and its shipment. A comparison of CIF Rotterdam price (adjusted for freight and insurance) and MPOB export prices (adjusted by one month to arrive at contract month price, i.e. considering Feb'21 export price as the rate for Jan'21), it is noted that the said prices are moving in tandem. The adjusted MPOB export price and CIF Rotterdam prices (adjusted) for January- September' 2021 are as below:



It is also noted that the average adjusted MPOB export price and CIF Rotterdam for January- September' 2021 are USD 1361/MT and USD 1364/MT respectively. The Authority has therefore found it appropriate to compare purchase order month-wise domestic purchase price with the contract month-wise CIF Rotterdam price, for determining the subsidy amount.

Schemes other than supply of raw material at LTAR

76. The petitioner has alleged a total number of 31 subsidy schemes and accordingly the responses were received in respect thereof from the respective producers/exporters and the government of Malaysia. It is noted that the gravamen of petitioner's claim is the provision of raw material at LTAR, which has been examined in depth herein above. In addition, the petitioner has also alleged certain other subsidy schemes, primarily on the ground that these schemes were found to be countervailable in the past investigations. However, on investigation, in respect of the most of such schemes, it is found that either no benefit has been availed by the producers of the subject goods or benefit availed is negligible/not-quantifiable. Accordingly, the Authority has examined the following schemes, for the purpose of the present investigation:

Program no.	Name of grant/program
Program no. 17	Double deduction for promotion of exports
Program no. 23	Schemes for provision of Natural Gas and Electricity at LTAR
Program no. 24	Sales Tax Exemption on Raw Materials / Packaging Material
Program no. 25	Exemption from import duty and Sales tax on machinery, equipment and spare parts

Program no. 29	Grant for promotion of production of Oleo derivatives
----------------	---

(ii) Program No. 17- Double deduction for promotion of exports

a. Submission by the Petitioner

77. Section 41 of the Promotion of Investment Act and Rule 4 (2) of the Income Tax (Promotion of Exports) Rules, 1986 provides for double deduction to exporters for expenses incurred for promotion of exports such as cost of maintaining office overseas, publicity and advertisements in any medium outside Malaysia for export promotion etc. The program was held to be countervailable by the Authority in its Final Findings concerning imports of 'Continuous Cast Copper Wire Rods', 'Aluminium Wire/ Wire Roads above 7mm dia', 'Clear Float Glass' and 'Fiberboards'.

b. Submission by the Government of Malaysia & other interested parties

78. The program under section 41 of the Promotion of Investments Act (PIA) 1986 (Act 327) read together with rule 4(2) of the Income Tax (Promotion of Exports) Rules 1986 is applicable to all resident trading, manufacturing or agricultural companies in respect of expenses incurred in the basis period primarily and principally for the purpose of seeking opportunities, or in creating or increasing a demand for the export of Malaysian manufactured goods or agricultural products.

79. This program focuses on supporting Malaysian companies' participation in eligible export promotional activities, not on their goods' export performance or on the use of domestic good. All firms which can meet the eligibility criteria can benefit from this program. The companies under investigation will be eligible to claim the deductions if they fulfil the criteria. There are no anticipated changes to the program. The deduction can be carried forward. Some of the producers of subject goods have availed benefit under this program.

80. Applicant companies are required to make the claim for the incentive by completing forms and substantiate the claims together with copies of business receipts pertaining to the expenses incurred overseas for advertising, travelling and related export promotional expenditure. The original supporting documents must be retained by the company for audit purposes by the IRB. Some of the producers of subject goods have availed benefit under this program.

c. Examination by the Authority

81. The Authority notes that the program is governed by Section 41 of the Promotion of Investments Act (PIA) 1986 (Act 327) & Rule 4(2) of the Income Tax (Promotion of Exports) Rules 1986. Under this program double deduction from income to enterprise involved in manufacturing, trading and agricultural activities is available for expenses incurred for promotion of export. Expenses incurred by a company for increasing demand for exports are allowed for double deduction.

82. The Authority notes that the program provides for financial contribution the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. The benefit is the difference between the amount of income tax paid after double deduction and the amount of income tax that would have been payable in absence of such double deduction. The program is also specific because it is contingent on export performance and is limited to enterprise engaged in export promotion activity. The Authority therefore holds the program countervailable. The Authority notes that KL-Kepong Olechemicals has received benefit under this program.

(iii) Program 23- Provision of Natural Gas and Electricity at LTAR

a. Submission by the Petitioner

83. The petitioner had in the petition claimed that electricity in Malaysia is provided at LTAR. Thereafter, in its written submissions post oral hearing, the petitioner additionally submitted that GoM, through Petronas and Gas Malaysia Berhad supply gas to industrial consumers at LTAR. Gas Supply Act, 1993 directs the aforesaid companies to sell natural gas at regulated lower prices to industries, including electricity sector. The difference in market price and regulated price is recovered by the said companies from the GoM. Natural gas, which is one of the main consumables required for the production of the subject goods, is supplied to domestic manufacturers of SFA at LTAR.

84. It has been further submitted by the petitioner that electricity in Malaysia is produced from natural gas. As the natural gas is subsidised in Malaysia, such subsidy is also passed through to the SFA producers by provision of electricity at LTAR.

85. The petitioner had relied upon the Final findings dated 31st Jan, 2022 issued in investigations concerning Copper Tube and Pipes from Malaysia to submit that supply of natural gas and electricity to the industrial consumers in Malaysia is a countervailable subsidy.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

86. The Authority had issued supplementary questionnaire to GoM and participating exporters to give details of purchase and supply of natural gas and electricity. In its supplementary response, the GoM has submitted that the natural gas is provided by Petronas at “willing buyer-willing seller” rates.

c. Examination by the Authority

87. The Authority notes that this program is governed by Gas Supply Act, 1993. The subsidy program allows regulated rates of natural gas prices for industrial sector including the electricity sector. It is noted that the GOM provides subsidies to the gas supplying companies namely, PETRONAS and Gas Malaysia Berhad (GMB), which in turn supplies gas to the exporter at reduced rates. The GOM during verification consultation held on 07.09.2022 had admitted that the price of natural gas in Malaysia is regulated by the GOM. The Authority notes that the producers of the subject goods in their manufacturing process use natural gas which they have purchased at the regulated rates. The Authority, therefore, holds the program countervailable as it results in financial contribution by the GoM by provision of natural gas below the market price and benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is limited to industrial consumers using “natural gas”.

88. The Authority further notes that electricity in Malaysia is produced from natural gas. The electricity distribution in Malaysia is regulated under the Electricity Supply Act, 1990. Under the Act only entities licensed by the Energy Commission shall supply electricity. Hence, such bodies are entrusted with governmental functions and act as public bodies. It has been noted that electricity is being offered by such public bodies at below market price. It has been found that the benefit on natural gas is being passed on for generation of electricity as ICPT (Imbalance Cost Pass Through) Charges. The Authority therefore holds the program countervailable.

Other Program

(iv) Program 24- Sales Tax Exemption on Raw Materials / Packaging Material

a. Submission by the Petitioner

89. No submission has been made by the petitioner in respect of this program.

b. Submission by the Government of Malaysia/other interested parties

90. No submission has been made by GOM. Other interested parties have submitted that the GOM vide Sales Tax (Goods exempted from Tax) order, 2018, has exempted sales tax on most of the raw materials used for manufacture of subject goods. It has been submitted that the said exemption is like general duty exemption which is applicable to all imports.

91. In addition, the GOM has issued Sales Tax (Persons exempted from payment of Tax) Order, 2018. Sl. No. 4 of the Schedule B of the said Order provides exemption to any manufacturer approved by the Director General from sales tax on raw materials, components and packaging materials when imported or purchased from a registered manufacturer. It prescribes the following conditions that are required be fulfilled in order to be eligible for availing the exemption—

- i. that the raw materials and components are imported or purchased from a registered manufacturer;
- ii. that the raw materials and components are used and the goods produced thereof are exported within twelve months from the date of import or purchase or such further period as approved by the Director General;
- iii. that the raw materials and components and the goods produced thereof shall not be sold or otherwise disposed of in Malaysia except as sanctioned by the Director General and upon payment of the appropriate amount of tax;
- iv. that the raw materials and components shall be used solely for the manufacture of exempted goods for export;
- v. that the person approved shall pay the sales tax on any raw materials and components that cannot be accounted for;
- vi. that if the raw materials and components are not used and the goods produced thereof are not exported within twelve months from the date of import or purchase or such other period as approved by the Director General, the person approved shall be liable to pay the sales tax on the raw materials and components purchased or imported.

92. Exemption from Sales tax on Capital goods is also provided to the qualifying manufacturers under Sr. 55 of the Sales Tax (Persons exempted from payment of Tax) Order, 2018.

93. The exemption is not countervailable in terms of Footnote 1 to the SCM Agreement, as it is solely for the manufacture of exempted goods which are meant for export. There is a proper mechanism in place to ensure that no additional sales tax has been exempted.

c. Examination by the Authority

94. The Authority notes that Sales Tax (Goods exempted from Tax) Order, 2018 provides exemption of Sales tax on goods itself and is a general exemption applicable to anyone. As such, the program is not specific and therefore, not countervailable.

95. Sales Tax (Persons exempted from payment of Tax) Order, 2018 on the other hand provides sales tax exemption to qualified manufacturer on raw material / component used in export goods. The Authority notes that Sales Tax (Persons exempted from payment of Tax) Order, 2018 provides financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due. The program is specific because it is limited to enterprise that purchase raw materials/packing material/ spares from registered manufacturers. The program does not qualify to be permissible duty remission program under Footnote 1 of the SCM Agreement because no evidence has been provided to show the verification mechanism adopted by GOM for determining nature and quantum of inputs, packing material etc. required for manufacturing goods for export. Moreover, exemption has also been provided on Capital goods. The Authority holds that countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

(v) Program 25- Exemption from import duty and Sales tax on machinery, equipment and spare parts

a. Submission by the Petitioner

96. No submission has been made by the petitioner in respect of this scheme.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

97. No submission has been made by the GOM. Other interested parties have submitted that under the Customs Act, 1967, the GOM has issued the Customs Duties (Exemption) Order 2017 under which qualifying manufacturers as listed in the schedule provided in the said order are eligible for exemption from customs duty when they import certain goods.

98. Sl. No. 112 of Part I of the schedule provides exemption from customs duty to manufacturers in Principal Customs Area ("PCA") that are endorsed by Malaysian Investment Development Authority ("MDA"). Such exemption is provided on import/purchase of machinery and equipment that has been approved by the Secretary General of Treasury.

99. It has been claimed that the programs are general in nature. These are not specific to any enterprise or group of enterprises, or to any industry or group of industry or sector. Any manufacturer located in PCA which has been endorsed by MIDA and intends to import/locally purchase machinery and equipment, can avail this exemption, subject to the condition that the goods belong to a category that has been approved by the Secretary General of Treasury.

c. Examination by the Authority

100. The Authority notes that the Customs Duties (Exemption) Order 2017 provides exemption from import duty to the eligible producers on import/purchase of machinery and equipment that has been approved by the Secretary General of Treasury.

101. The Authority notes that exemption provided under Customs Duties (Exemption) Order, 2017, provides financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due. The program is also specific as it is applicable to only certain eligible manufacturers. The program does not qualify to be permissible duty remission program as the exemption is provided on capital goods and machineries and therefore, is not covered by Footnote 1 of the SCM Agreement. The Authority holds that countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

(vi) Program 29- Grant for promotion of production of Oleo derivatives

a. Submission by Petitioner

102. No submission has been made by the petitioner.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

103. No submission has been made by the GOM. The other interested parties have submitted that a grant has been provided by the Performance and Management Delivery unit ("PEMANDU"), Prime Minister's Department, pursuant to Economic Transformation Programme ("ETP"), which is an economic development program of GOM. One of the objectives of ETP is to prioritise investments and support certain areas of growth. There are 12 areas of growth i.e., the National Key Economic Areas (NKEA) which have been identified. One of the

NKEAs is “Palm Oil”. Under this NKEA, the ETP has identified the promotion of production of oleo derivatives as an action point.

104. Grants have been given to oleochemical producers under the ETP.

c. Examination by Authority

105. The Authority notes that the program provides for grants under the Economic Transformation Policy. Grant is available to manufacturers of subject goods as palm oil is one of the 12 identified National Key Economic Areas. The Program aims to promote production of subject goods by supporting, through financial contribution, investments into projects for capacity generation.

106. The Authority notes that the program provides “financial contribution”. The program is also specific as it is applicable only to companies falling under one of the 12 identified National Key Economic Areas. The Authority therefore, hold the program countervailable. M/s KLK Oleo Sdn. Bhd. has received grants under this scheme.

107. The Authority notes that other than the schemes examined above, the Authority had computed subsidy under certain other schemes at the time of issuing disclosure statement. Considering the submissions made on the disclosure statement, and also the fact that the margins finally determined were either negative or minuscule, therefore, the Authority has not considered those schemes for subsidy margin determination.

Producer/Exporters from Malaysia

FPG Oleochemicals Sdn Bhd, Malaysia and Procter and Gamble International Operations SA Singapore (FPG Group)

108. FPG Oleochemicals Sdn. Bhd. (FPG) is a producer of the subject goods in India. It has exported to India through its related trader Procter and Gamble International Operations SA Singapore (PGIO). It is noted that FPG has mainly used domestically procured CPKO for manufacture of subject goods. In addition, it has also used locally procured RBDPKO and imported CPKO/RBDPKO for producing subject goods. The Authority notes that the benefit availed on locally procured inputs, to the extent used for manufacturing subject goods, is countervailable. Subsidy margin determined for FPG group is as under:

Programs	Subsidy Margin	Range
CPKO at LTAR	***%	10-15%
Sales tax Exemption on Raw Material	***%	0-5%
Natural Gas at LTAR	***%	0-5%
Preferential Lending Rates	***%	0-5%
Subsidy %	***%	10-15%

*no export subsidies availed by FPG

KL-Kepong Oleomas Sdn. Bhd, Malaysia (KLK Group)

109. KL-Kepong Oleomas Sdn. Bhd (KLK) is a producer-exporter of the subject goods. In addition to direct exports to India, it has also exported through unrelated trader Unilever Asia Private Limited Singapore (“UAPL”). KLK has claimed that it has received grant from GoM. It is also noted that KLK has manufactured subject goods using RBDPKO, Fatty Acid and Split Palm Kernel Fatty Acid, procured locally as well as imported. The Authority holds the benefit availed on locally procured raw material at LTAR as countervailable. The subsidy margin determined for KLK group is as under:

Programs	Subsidy Margin (%)	Range
CPKO at LTAR	***%	5-15%
Natural Gas at LTAR	***%	0-5%
Exemption from import duties on import of machinery and equipment	***%	0-5%
Sales tax exemption on raw material/packing material	***%	0-5%
Grants	***%	0-5%
Preferential Lending Rates	***%	0-5%

Export subsidy			
Double Deduction for Exports		***%	0-5%
Subsidy %		***%	5-15%

Edenor Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. (formerly, Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd) and Edenor Oleochemicals Rika (M) Sdn. Bhd. (formerly, Emery Oleochemicals Rika (M) Sdn. Bhd)

110. Edenor Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. (“EOM”) is producer-exporter of the subject goods to India. The Authority notes that EOM manufactures subject goods using domestically produced CPKO. In addition, it is noted that it has also availed benefit under other schemes as well. Edenor Oleochemicals Rika (M) Sdn. Bhd. (“Rika”) is a related entity of EOM, which also produces the subject goods. However, Rika has not directly exported the PUC to India during the POI. The Authority also notes that EOM has exported only a very small quantity of the PUC to India during the POI. Considering the insignificant exports of the Edenor Group, in the parallel sunset review investigation of the anti-dumping duty imposed on the PUC (excluding C10), the Authority vide Final Findings dated 02.02.2023 did not determine individual margins for the said group. Keeping the same view, the Authority has herein as well not determined individual subsidy and injury margins for Edenor Group.

Others

Summary of Subsidy Programs for Malaysia

111. Countervailing duty for all other producers/exporters from Malaysia has been determined based on the highest of the subsidy margins for the cooperating parties for the subsidies availed by them and based on facts available for other subsidy programs.

Program no.	Name of grant/program	Subsidy margin (%)	Range (%)
Program no. 1	Provision of CPKO at less than adequate remuneration	***%	10-15%
Program no. 23	Schemes for provision of natural gas and electricity at LTAR	***%	0-5%
Program no. 24	Sales Tax Exemption on Raw Materials / Packaging Material	***%	0-5%
Program no. 25	Exemption from import duty and Sales tax on machinery, equipment and spare parts	***%	0-5%
Program no. 31	Preferential lending	***%	0-5%
Program no. 29	Grant for promotion of production of Oleo derivatives	***%	0-5%
Export Subsidy			
Program no. 17	Double Deduction for promotion of exports	***%	0-5%
	Total	***%	10-20%

Government of Thailand (“GOT”)

112. **List of Schemes identified for Thailand**

- i. Program 1 Schemes on regulation of raw material prices
- ii. Program 2 Schemes under the Bio – Economy policy relating to palm oil downstream industries
- iii. Program 3 Schemes on investment promotion
- iv. Program 4 Schemes to promote product export (credit insurance)
- v. Program 5 Tax Compensation or Coupons on exports
- vi. Program 6 Duty drawback

F.5. Examination of the Subsidy programs alleged by the Petitioner

(i) Program No. 1 & 2 –Raw material at LTAR and Export promotion of Fatty Alcohol and Bio-economy Policy

a. Submission by the Petitioner

- 113. The Thailand Oil Palm Board (the "TOPB") closely monitors and controls the production of 15 million tons of palm oil on an average every year. *The 2021 Palm Oil Export Boost to Reduce Excess Product Project* (the "Export Boost Project"), designed to subsidize the export of palm oil derivatives. It is managed by a "Subcommittee" which on 21.10.2019 announced that, any juristic person whose main business is to manufacture, use, sell, store, or export palm oil or palm oil products may be eligible for additional support from the government.
- 114. A "Second Announcement" dated 07.06.2021, further extended the benefits provided and more benefits were expected to be officially announced in December 2021. Bio-economy is only a general concept/vision which has been included in the Twelfth National Economic and Social Development Plan (2017-21) and the Biodiversity-Based Economy Development Framework (2017-36), instead of one independent scheme to promote bio-economy.

b. Submission by the Government of Thailand/other interested parties

- 115. There is no regulation or law relating to this scheme. The scheme is intended to boost exports of raw material and therefore, no benefit provided to the SFA manufacturers.

c. Examination by the Authority

- 116. The Authority finds that the scheme is merely a policy of the GOT to encourage exports of palm oil and its derivatives. No evidence has been placed on record by any of the interested parties with regard to operation of this scheme in relation to the product under consideration. The Authority has therefore not examined it in further detail and accordingly, does not hold the scheme countervailable.

(ii) Program No. 3- Schemes on investment promotion

a. Submission by the Petitioner

- 117. The petitioner has submitted that the investment promotion incentives offered by GoT, vary depending on various factors, including (i) the type of promoted activity, (ii) location of the project, and (iii) eligibility for special investment promotion policies. Certain business activities may be eligible to apply for additional incentives, which are considered based on various factors such as, the merits of the project, investment in research and development ("R&D"), and the use of advanced technology in the project

- 118. Two main types of investment promotion incentives offered by the Board on Investment are **tax incentives** and **non-tax incentives**. Tax incentives include

- (i) exemption of corporate income tax ("CIT") on profit derived from the sale of the promoted product for a period of up to 10 years;
- (ii) exemption of import duty on machinery used in the promoted project; and
- (iii) exemption of import duty on raw materials used in products manufactured for export;

- 119. The non-tax incentives include

- (i) permission for foreign nationals to enter Thailand, for the purpose of studying investment opportunities;
- (ii) permission for foreign skilled workers and experts to enter Thailand and work for the promoted business;
- (iii) permission to own land for operation of the promoted business for foreigner; and
- (iv) permission to bring out or remit money outside Thailand in foreign currency.

- 120. The Authority had countervailed this scheme in past investigations.

b. Submission by the Government of Thailand/other interested parties

- 121. The purpose of this program is to facilitate companies that are entitled to receive benefits under Section 28 of the Investment Promotion Act (IPA) by exempting import duties of certain imported machinery that is needed for the Board of Investment (BOI)-promoted projects.

- 122. Companies that wish to apply for BOI investment promotion must submit one application form for each project. If the project meets the approval criteria, the BOI will grant rights and benefits as a package. BOI investment promotion will not be granted on the incentive program basis. In other words, the BOI does not grant incentives program-by-program, but rather as a package of IPA benefits the companies are entitled to receive. However, when (or if) a BOI-promoted company actually decides to utilize particular benefits granted under the IPA package, the company must submit a request separately for utilizing each benefit. Thai Fatty Alcohols Co. Ltd. (TFA) has applied for BOI investment promotion for production of subject goods. It has been claimed by TFA that even though it was eligible to receive the benefits under the program. However, no benefits have been received by TFA during the year.

c. Examination by the Authority

123. Authority notes that Investment Promotion Act. 2002 (the Act) provides for certain rights and benefits to promoted entities/projects/activities (Investment Promotion Package Scheme). Section 16 of the Act prescribes that the Board of Investment (BOI) will make an announcement designating the types and sizes of investment activity eligible for benefit specified under the Act.
124. Section 28 of the Act provides exemption from payment of import duties on machinery under approved investment projects and not for reduction of import duties on machinery. Section 30 of the Act provides for reduction (not exceeding ninety percent) of import duty on raw materials and not for exemption/ reduction of import duty on machinery.
125. Program provides for a financial contribution in the form of revenue foregone which is otherwise due and a benefit is thereby conferred. Subsidy is also specific because it is limited to promoted enterprise carrying out promoted activity. The Authority, therefore, holds the program countervailable.

(iii) Program No. 4 – Credit Insurance

a. Submission by the Petitioner

126. The petitioner has submitted that the Export-Import Bank of Thailand ("EXIM Thailand"), is a Thai state owned specialized financial institution under the Ministry of Finance's supervision, designed to promote and support Thai export, import, and investment for the purpose of national development, by providing guarantees, credit facilities, and insurance against risks.
127. EXIM Thailand offers short term as well as medium- and long-term export credit insurance (i.e. a facility protecting exporters' foreign receivables against non-payment risks).
128. EXIM Thailand provides several short-term export credit insurance policies for both SMEs and larger corporate exporters whereby, the terms of payment on the transaction must not exceed 180 days after the shipment date. The short-term export credit insurance covers against default of payment caused by both commercial and political losses, relating to overseas trade transactions such as export of goods and services. The indemnity rate for commercial losses is up to 85 to 90 percent of loss realized and the indemnity rate for political losses is up to 90 percent of loss realized. Policies include:
 - (i) EXIM for SMEs
 - (ii) EXIM Flexi
 - (iii) EXIM Sure
 - (iv) EXIM sMart Insurance.

Similar to the short term export credit insurance, the medium and long term export credit insurance covers against default of payment caused by commercial and political losses relating to overseas trade transactions.

b. Submission by the Government of Thailand/other interested parties

129. Export credit insurance facilities protect exporter's foreign receivables against non-payment risks. In case of payment defaults caused by overseas buyers, EXIM Thailand compensate for the loss according to conditions specified in the insurance policy.
130. The Producers/exporters of the subject goods have not availed any benefit under this scheme.

c. Examination by the Authority

131. The Authority notes that the program provides for export credit insurance to the exporters against non-payment risk. However, as the sole producer of the subject goods has not availed benefit under this program, the Authority has not examined this scheme in further detail.

(iv) Program No. 5 - Tax compensation and coupons

a. Submission by the Petitioner

132. Tax compensation is a measure to lower the production cost of goods which are produced in Thailand for export. The compensation is subject to certain criteria and conditions and is available only to eligible industries under the Tax and Duty Compensation of Exported Goods Produced in the Kingdom Act, B.E. 2524 (1981).
133. The tax compensation is determined according to the FOB price for export and the rate applicable to each type of exported goods and is compensated in the form of a tax coupon. The export of fatty alcohol is eligible for the tax compensation under this scheme.

b. Submission by the Government of Thailand/other interested parties

134. The Ministry of Finance ("MOF") and the Thai Customs Department administer a tax coupon system for exporters. The tax coupon system is authorized under the 1981 Tax and Duty Compensation of Exported Goods Produced in the Kingdom Act. The value of a tax coupon is calculated by multiplying a product-specific coupon rate by the FOB value of a company's exported goods. To derive the coupon rate for a particular exported good, the MOF examines the import duties and indirect taxes paid for the raw materials

and other inputs used to produce the exported good. The tax coupon system refunds the import duties and indirect taxes paid for the raw materials and other inputs used in the production of exported goods.

c. Examination by the Authority

135. This program is established pursuant to the Tax and Duty Compensation of Exported Goods produced in the Kingdom Act B.E. 2524 (1981) and became effective on August 15, 1981. Under this subsidy program, import duties and indirect taxes paid for the raw material and other inputs used in the production of exported goods are refunded.
136. To administer this program, the Ministry of Finance and the Thai Customs Department administer a tax coupon system for exporters. The value of a tax coupon is calculated by multiplying a product-specific coupon rate by the FOB value of a company's exported goods. Coupon rate for a particular exported good is determined by the import duties and indirect taxes paid for the raw materials and other inputs used to produce the exported goods. Exporting companies may also use tax coupons as credits against corporate income taxes.
137. The Authority notes that the Government of Thailand has not provided any evidence or established the existence of a mechanism to ensure that value of tax coupon does not exceed the amount of import duties and other taxes paid on the raw material used in the production of exported goods. Therefore, the program provides financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. The Program is deemed specific as it is linked to exports.
138. The Authority finds that the sole producer/exporter M/s Thai Fatty Alcohols Co. Ltd. has availed benefit on the exports of subject goods. The Authority therefore, has imposed countervailing duty against the said scheme.

(v) Program No. 6 - Duty Drawback under Section 19 of the Customs Laws

a. Submission by the Petitioner

139. The petitioner submits that under this program exporting companies obtain a refund of customs duty paid on imported goods where those goods will have undergone production, mixing, assembling, or packing and then exported
- b. Submission by the Government of Thailand/Other interested parties**
140. Duty drawback under Section 29 of the Customs Act means the refund of import duty already paid or the return of guarantee placed on imports which have undergone production, mixing, assembling, or packing and then exported.
141. Eligible goods for duty drawback are:

- i. Raw materials which are obviously seen in the exports e.g. fabrics, buttons, zippers and thread in garments, plastic sheeting in plastic products, etc.
- ii. Raw materials used directly in the manufacturing process and contained in the exports but not obviously seen e.g. preservatives in canned food, stiffening agents in garments, solvents for glue in cellophane and anti-rust agents in electronic circuits, etc.
- iii. Raw materials required in the manufacturing process e.g. sizing materials and bleaching agents used in textile products, sand paper, scouring powder, varnish, velvet, scouring agents, chalk, carbon paper and pattern.

c. Examination by the Authority

142. The Authority notes that Section 29 of the Customs Act provides for duty drawback. The subsidy program provides for refund of import duty paid on raw materials which have undergone production, mixing, assembling, or packing and then exported. The Authority has sought information as to whether GoT maintains any verification mechanism to ensure that the duty drawback provided is not in excess of those required for export production. However, no evidence has been placed before the Authority about any such mechanism, which ensures that there is no excess remission of import duty and that amount of duty drawback will not exceed the amount of duty paid on raw material used in production of exported goods.
143. Thus, the Authority notes that the subsidy program provides for financial contribution in the form of revenue foregone and the benefit is thereby conferred. The subsidy program is also specific because it is contingent on export. Therefore, the Authority determines that the subsidy program is countervailable.

Other Program

(vi) Preferential Lending rate

a. Submission by the Petitioner

144. No submission has been made by the Petitioner

b. Submission by Government of Thailand/Other interested parties

145. In the Supplementary Questionnaire response, the Government of Thailand has provided details of average lending rates as well as the details of loan provided by Government bank to the Global Green Chemicals

Public Co. ("GGC"), raw material supplier and the holding company of the sole SFA producer in Thailand, i.e. Thai Fatty Alcohols Co. Ltd.

c. Examination by Authority

146. The Authority notes that loan has been provided by one of the government banks to GGC at significantly lower rate as compared to the applicable lending rates. The program provides financial contribution in the form of revenue forgone (reduced rate of interest paid). Benefit is conferred on the recipient in the form of difference between the interest charged by bank and the applicable interest rate as provided by GOT in its response. The Program is also specific as concessional lending rate is applicable only to the specific company. The Authority therefore holds the program countervailable.

Thai Fatty Alcohols Co. Ltd., Thailand and Global Green Chemicals Public Co., Ltd. Thailand TFA

147. Thai Fatty Alcohol Co. Ltd. (TFA) is the producer-exporter of the subject goods to India. Global Green Chemicals Public Co. (GCC) is the holding company of TFA. It is noted that GCC is also the supplier of raw material to TFA. TFA has admitted to have received tax compensation as well as duty drawback. It has been claimed that the Drawback is not countervailable in terms of Footnote 1 to Article 1 of the ASCM. The Authority in the supplementary questionnaire responses had called for information from both TFA as well as the GOT to explain the verification mechanism followed by it for ensuring that there is no excess remission of import charges. The Authority, in the disclosure statement had, in absence of any evidence of a verification mechanism provided by GoT, noted the entire drawback amount as a subsidy. However, post disclosure, the participating exporter (TFA) has submitted detailed working to substantiate that they have not received any excess remission. The Authority has considered the submission made by the participating exporter, and re-determined the amount of subsidy under drawback scheme. The Authority therefore, holds the program countervailable. Subsidy margin determined for TFA group is as under:

Programs	Subsidy Margin %	Range
Preferential lending	***%	0-5%
Exemption under Investment promotion Act	***%	0-5%
Export subsidy		
Tax compensation or Coupons on exports	***%	0-5%
Duty Drawback	***%	0-10%
Subsidy %	***%	0-10%

Summary of Subsidy Programs for Thailand

148. Countervailing duty for all other producers/exporters from Thailand has been determined based facts available and subsidy margin of TFA

Programs	Subsidy Margin %	Range
Preferential lending	***%	0-5%
Exemption under Investment promotion Act	***%	0-5%
Export subsidy		
Tax compensation or Coupons on exports	***%	0-5%
Duty Drawback	***%	0-10%
Subsidy %	***%	0-10%

H. INJURY ASSESSMENT AND CAUSAL LINK

H.1. Submission made by the Domestic Industry

149. The submissions made by the domestic industry are as follows:

- The Government of Indonesia has significantly increased the export tax on the principal raw material (Crude Palm Kernel Oil) from December 2020 onwards. The quantum of increase can be gauged from the fact that approximately **USD 400 per MT** export tax was paid on export of CPKO in September, 2021, as against **nil** in September, 2020. The increase in export tax is primarily with the object to ensure excess supply of raw material to the domestic manufacturers in Indonesia, and that such supply is available to them at below world

market prices. It may be noted here that CPKO forms more than 70% of the cost of production of the subject goods, as such, this subsidy alone has significantly reduced their cost of production.

- b. Following Indonesia, Government of Malaysia had also increased the export tax on export of CPKO to 10% in January, 2021, as against 0% in December, 2020. The purpose of the said export tax is to ensure that the domestic manufacturers in Malaysia get assured supply of CPKO at lower prices, so as to be able to match the subsidized production cost of Indonesia.
- c. Given the fact that Malaysia and Indonesia account for more than 90% of the global CPKO production, the said countries have, by imposition of export tax, limited the availability of CPKO in global market and increased its world market price, as also have ensured the availability of CPKO at cheap prices for their domestic manufacturers. Thus, the cost of production of the subject goods in the said countries is heavily subsidized, thereby causing serious injury to Indian domestic industry.
- d. There has been a flood of imports from the subject countries over the injury period, which has increased by 54% compared to the base year. In contrast, the production of the petitioner has remained at the same level as compared to the base year.
- e. The subject imports in relation to production have increased throughout the injury period and have reached to 154 index points in the POI as compared to the base year.
- f. The share of the subject countries in total imports to India and in the Indian demand has shown a steady and steep increase throughout the injury period. The imports have increased not only in absolute terms but also in relation to production.
- g. The demand for the subject goods has increased throughout the injury period. There was an increase of 22% in demand in the POI as compared to the base year. However, the entire incremental demand has been captured by the imports from the subject countries, which have increased by more than 30 indexed points in the POI as compared to the base year. In contrast, the domestic industry has lost almost 25% of its market share during the same period.
- h. The subject imports have not only captured the incremental demand but have also eaten into the market share of the Indian industry.
- i. The losses of the domestic industry continue to be at high levels on account of continued increase in subsidized imports from the subject countries.
- j. Import prices from the subject countries are suppressing and depressing the domestic prices.
- k. Imports are resulting in significant price underselling, as evidenced by the difference between non-injurious price and landed price of the imports.
- l. The Indian producers have the capacity to cater to the entire domestic demand, yet, almost 75% of the domestic demand is being met by the imports from the subject countries on account of their low prices.
- m. The profitability and ROI of the domestic industry has continued to remain in red, despite the petitioner's best efforts to reduce its cost and increase its sales.

H.2. Submission by the other interested parties

150. The submissions made by the other interested parties with regard to injury and causal link, are as follows:

- a) The petitioner has submitted import data only for the part of the POI (i.e. till May, 2021). As such, the price undercutting, price suppression, price depression and injury margin claimed by the petitioner based on such extrapolated data of imports of the PUC cannot be considered for injury analysis.
- b) The injury to the petitioner is on account of its bad investment decisions. Petitioner's significant investments in Indonesia have led to an adverse impact on the petitioner in terms of high procurement costs and high-interest costs.
- c) Only the interest costs from various borrowings (including for the Indonesian investment) have led to a situation of net loss. Any additional costs incurred by the petitioner as a result of unforeseen policies of the Indonesian government cannot be included while determining injury and non-injurious price.
- d) The injury to the petitioner is also on account of investment made in its plant at Kutch, which has resulted in additional cost of Rs. 2200/MT. Subsequently, the fiscal benefit given by Government of India for the said investment was withdrawn. In 2020, the Hon'ble Supreme Court in its decision in Union of India vs. M/S V.V.F. Ltd [(2020) 20 SCC 57] upheld the Government of India's decision to modify the fiscal benefits that VVF was entitled to. This has created a potential liability of Rs. 304 million against the petitioner.
- e) The petitioner's auditors have noted concerns over petitioner's ability to remain a "going concern".

- f) The petitioner, through local presence in Indonesia, is itself benefitting from the subsidy, if any, provided on the procurement of raw material.
- g) There is absence of causal link as the profitability parameters during the POI have nearly doubled from the previous year and are at the base year's level, despite increase in the subject imports.
- h) Injury to the petitioner is on account of inverted duty structure, i.e. high import duty of 37.5% imposed on the imports of raw material (CPO/CPKO).
- i) The petitioner does not have access to feedstock, and is dependent on imports. As such, unviability of its production is mainly on account of non-availability of raw material.
- j) The petitioner does not manufacture pure grade C12 and has limited supply of C1214.
- k) The petitioner has not been able to increase its production capacity and production level despite increase in demand, which clearly shows that the injury to the petitioner is on its own account.
- l) Further, volume injury, if any, is on account of petitioner's own captive consumption and exports.

H.3. Examination by the Authority

151. In consideration of the various submissions made by the interested parties and the domestic industry in this regard, the Authority has examined injury to the domestic industry on account of subsidized imports from the subject countries.

152. Rule 13 of the Subsidy Rules deals with the principles governing the determination of injury which provide as follows:

13. Determination of injury-

- (1) *In the case of imports from specified countries, the designated authority shall give a further finding that the import of such article into India causes or threatens material injury to any industry established in India, or materially retards the establishment of an industry in India.*
- (2) *Except when a finding of injury is made under sub-rule (3), the designated authority shall determine the injury, threat of injury, material retardation to the establishment of an industry and the causal link between the subsidized import and the injury, taking into account inter alia, the principle laid down in Annexure I to the rule.*
- (3) *The designated authority may, in exceptional cases, give a finding as to the existence of injury even where a substantial portion of the domestic industry is not injured if—*
 - (i) *there is a concentration of subsidized imports into an isolated market, and*
 - (ii) *the subsidized imports are causing injury to the producers of almost all of the production within such market.*

153. Article 15.1 of the SCM Agreement and Annexure I to the CVD Rules provide for objective examination of both, (a) the volume of subsidised imports and the effect of the subsidised imports on prices in the domestic market for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The Authority is required to examine whether there has been a significant increase in imports, either in absolute term or relative to production or consumption in the importing member. With regard to the price effect of the subsidised imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the subsidized imports as compared to the price of the like product in the importing country, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree, or prevent price increase, which would have otherwise occurred to a significant degree.

The Authority has taken note of the arguments of the interested parties on injury examination aspects and addressed the issues raised at appropriate places in these final findings to the extent relevant.

I. Volume Effect of subsidized imports and Impact on domestic Industry

i. Assessment of Demand

154. Demand or apparent consumption of the product under consideration in India is defined as the sum of domestic sales of all Indian producers and imports from all other countries. It is seen that demand has increased over the injury period. The demand so assessed is as follows-

Sl.No.	Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
2	Sales of Other Producer	MT	***	***	***	***
3	Imports from Subject Countries	MT	***	***	***	***

4	Import from Other Countries	MT	***	***	***	***
5	Total Demand	MT	***	***	***	***
	Trend		100	113	119	122

ii. Imports volumes and share of the imports from subject country

155. With regard to volume of the subject imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in subsidized imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports of the subject goods from the subject countries have been analysed as under-

Sl.No.	Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
A	Indonesia	MT	18,085	27,169	46,907	55,273
B	Malaysia	MT	40,251	35,136	43,004	40,282
C	Thailand	MT	11,784	12,366	8,466	9,637
1	Subject Countries	MT	70,120	74,671	98,377	1,05,192
2	Other Countries	MT	10,760	12,803	3,952	395
3	Total	MT	80,880	87,473	1,02,329	1,05,587

156. It is seen that:

- a. There has been a significant increase in the absolute volume of imports from the subject countries by 50% in POI from the base year.
- b. The imports have increased sharply in relation to production of the domestic industry from ***% in 2018-19 to ***% in the POI.
- c. During the POI, the imports from the subject countries accounted for almost 100% of total imports to India.

II. Price effect of subject imports and impact on domestic industry

157. With regard to the effect of subsidized imports on prices, the Authority has considered whether there has been a significant price undercutting by the subsidized imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such subsidized imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

i. Price Undercutting

158. Price undercutting has been worked out by comparing the landed price of the imports with the selling price of the domestic industry for the investigation period. The price undercutting has been determined separately for each PCN produced by the domestic industry and thereafter for the product under consideration as a whole. The weighted average undercutting computation is as under:

POI	QTY	LV Rs/ Kg	NSR Rs/Kg	Undercutting (Rs/Kg)
Indonesia	55,273	129	***	***
Malaysia	40,282	129	***	(***)
Thailand	9,637	139	***	(***)
Subject Countries	1,05,192	130	***	(***)

159. The Authority notes that the undercutting is positive for certain grades. On a weighted average basis there is nil/negligible undercutting. However, the negative/ negligible undercutting is required to be appreciated in the backdrop that the sales of domestic industry is at significantly lower prices compared to its cost of production and the domestic industry has been forced to sell at loss to match the prices of the imports from the subject countries.

ii. Price underselling / Injury Margin

160. The Authority has worked out non-injurious prices of the subject goods and compared the same with the landed value of the imported goods to arrive at the extent of price underselling. The price underselling/ injury margin has been determined separately for each PCN and thereafter for the product under consideration as a whole. The price underselling from the subject countries is as below:

POI	QTY	LV Rs/ Kg	NIP Rs/Kg	Underselling Rs/Kg	Underselling %
Indonesia	55,273	129	***	***	20-30%
Malaysia	40,282	129	***	***	20-30%
Thailand	9,637	139	***	***	10-20%

161. It is noted from the below table that the price underselling/ injury margin is positive, indicating that the imports have entered the market at injurious prices. The injury margin for cooperative producers/exporters are evaluated as under:-

Country	Producer	NIP	Landed Price	Injury Margin	Injury Margin	Injury Margin
	Wt. Avg.	USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range
Indonesia	PTEO	***	***	***	***	10-20%
	PTMM	***	***	***	***	15-25%
	WINA	***	***	***	***	20-30%
	ESM	***	***	***	***	0-10%
	Others	***	***	***	***	25-35%
Malaysia	FPG	***	***	***	***	0-10%
	KLK	***	***	***	***	20-30%
	Others	***	***	***	***	20-30%
Thailand	TFA	***	***	***	***	10-20%
	Others	***	***	***	***	10-20%

* EOM has exported insignificant quantities during the POI and therefore, separate injury margin is not computed for it.

iii. Price suppression and depression

162. In order to determine whether the effect of imports is to depress prices or prevent price increases which otherwise would have occurred, the Authority has examined the changes in the landed price of imports, and costs & prices of the domestic industry over the injury period.

Sl.No.	Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI*
1	Cost of sales	Rs./Kg	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	99	94	115
3	Selling price	Rs./Kg	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	88	96	115
5	Landed Price	Rs./Kg	107	89	102	130
6	Trend	Indexed	100	83	95	121

163. It is seen that the cost of sales of the domestic industry has increased on account of significant increase in cost of raw material. However, there has not been commensurate increase in landed price of the subject imports. Landed price has remained significantly below the cost of production throughout the injury period.

III. Economic parameters relating to the domestic industry

164. The Rules require that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of

the imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The Authority has accordingly, herein under examined the performance of the domestic industry over the injury period.

i. Production, capacity, capacity utilization and sales

165. The position of the domestic industry over the injury period with regard to production, capacity, capacity utilization, domestic sales and export is as under:

Sl.No.	Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Capacity	MT	***	***	***	***
	Trend		100	100	100	100
2	Production	MT	***	***	***	***
	Trend		100	112	103	100
3	Capacity Utilization	%	***	***	***	***
	Trend		100	112	103	100
4	Domestic Sales	MT	***	***	***	***
	Trend		100	126	98	92
5	Export Sales	MT	***	***	***	***
	Trend		100	103	111	111

166. The Authority notes that-

- a. The capacity and capacity utilization of the domestic industry has remained at the same level over the injury period, as it was not able to increase its production despite increase in Indian demand. The entire incremental demand has been met by the imports from subject countries.
- b. The domestic industry has significant idle capacity however, it could not increase its production on account of continued price pressure from the imports. The Authority further notes that even though the capacities of the DI were primarily set up for C1214 grade, which has the maximum demand in India. However, in the current scenario, the demand for C1214 is primarily being met by imports and the DI's capacity utilization for C1214 grade is minuscule.

ii. Market Share

167. The market share of the domestic industry and domestic producers over the injury period is as under:

Sl.No.	Market Share	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Sales of Domestic Industry	%	***	***	***	***
	Range		20-30	20-30	10-20	10-20
2	Sale of Other Producers	%	***	***	***	***
	Range		0-10	0-10	0-10	0-10
3	Subject Countries	%	59%	55%	69%	72%
	Range		50-60	50-60	60-70	70-80
4	Other Countries	%	9%	9%	3%	0%
	Range		0-10	0-10	0-10	0-10
5	Total Demand	%	100%	100%	100%	100%

168. The market share of subject imports has increased significantly, from 59% to 72 % of demand of the country, whereas that of the petitioner has declined from ***% to ***% during the same period. It can be seen that the market share of the domestic industry has declined in the POI whereas share of subject countries' import has increased. The share of import from other countries has also declined.

169. The petitioner has not been able to benefit from increase in demand and its production has remained at the same level, despite having significant idle capacity.

iii. Profit or loss, cash profits and return on capital employed

170. The position of the domestic industry in terms of profit or loss, cash profits and return on investment is as under:

Sl.No.	Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Cost of sales	₹/kg	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	98	94	116
3	Selling price	₹/kg	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	89	96	115
5	Profit/(Loss)	₹/kg	(***)	(***)	(***)	(***)
6	Trend	Indexed	(100)	(138)	(83)	(118)
7	Profit/(Loss)	Rs.Lacs	(***)	(***)	(***)	(***)
8	Trend	Indexed	(100)	(173)	(83)	(106)
9	PBIT	Rs.Lacs	(***)	(***)	(***)	(***)
10	Trend	Indexed	(100)	(203)	(41)	(93)
11	Cash Profits	Rs.Lacs	(***)	(***)	(***)	(***)
12	Trend	Indexed	(100)	(219)	(28)	(91)
13	ROCE	%	(***)	(***)	(***)	(***)
14	Trend	Range	(10-20)	(20-30)	(0-10)	(20-30)

171. The Authority notes that:

- a. The losses suffered by the domestic industry has increased over the injury period. The domestic industry is consistently in loss on account of cheap imports from subject countries. The domestic industry was not able to benefit from the anti-dumping duty granted to it.
- b. Cash profits, PBIT and return on capital employed of the domestic industry have followed the similar trend.

iv. Inventories

172. The data relating to inventories of the subject goods is as follows-

Sl.No.	Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Average Stock	MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	112	115	113

173. It is noted that the average inventories have increased over the period.

v. Employment, wages and productivity

174. The situation of the domestic industry with regard to employment, wages and productivity during the injury period was as under:

Sl.No.	Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Wages	Rs Lacs	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	127	121	124

3	Employment	Nos	***	***	***	***
4	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	101	98	99
5	Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
6	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	112	103	100
7	Productivity per employee	Per No	***	***	***	***
8	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	111	105	101

175. It is seen that the wages, employees and productivity have remained at the same level.

vi. Growth

176. The trends of volume and profit parameters of the domestic industry showed as under-

Sl.No.	Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Production	%	-	12%	-8%	-3%
2	Domestic sales	%	-	26%	-22%	-6%
3	Loss per unit	%	-	38%	-39%	36%

177. It is noted that there is negative growth in production and domestic sales of the domestic industry. The losses of the domestic industry have increased significantly compared to previous year and base year. The market share of the domestic industry has declined. The profits, cash profit and return on capital employed have also shown decline over the injury period.

vii. Factors affecting domestic prices

178. The Authority notes that the domestic industry has been forced to sell significantly below its cost in order to match the low import prices. The market share of subject imports has increased over the period, whereas that of the domestic producers has declined. This shows that the imports are penetrating the market with low prices.

viii. Ability to raise capital investment

179. It is seen that the domestic industry has significant idle capacity, and it is continuously facing losses. It is noted that the domestic industry is facing both volume and price injury, and therefore, its ability to raise capital investment is significantly impacted.

180. The Authority further notes that the petitioner is suffering losses during the entire injury period due to high per unit capital and fixed cost, which is primarily on account of high interest cost. Even though the petitioner has substantial capacity to meet more than 80% of the demand, but due to subsidized imports from the subject countries at lower landed price, the petitioner is not able to compete and thereby it utilises less than 50% of its capacity. Low capacity utilization is the main cause of high interest cost. It is also observed that the domestic industry is not able to timely service its existing debts and hence it has been facing difficulties to arrange working capital for carrying out its day-to-day operations. The Authority therefore notes that the financial condition of the domestic industry is not the cause but the consequence of the injury due to the subsidized imports.

I. Conclusions on Injury

181. The Authority notes that the imports from the subject countries have increased significantly in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India. The import price has remained significantly below the cost of production throughout the injury analysis period, and the price underselling is also positive. While the market share of subject imports has increased significantly, that of domestic producers has declined. It is seen that the domestic industry is suffering severely from underutilized capacities and has not been able to utilize even half of its installed capacity. It is also noted that the inventory with the domestic industry has increased considerably compared to base year. Further, the losses incurred by the domestic industry have increased during the POI and its cash profits, PBIT and return on investment have followed the same trend. Accordingly, the Authority provisionally concludes that the domestic industry has suffered material injury.

182. It is noted that the domestic industry is facing both volume and price injury.

J. Causal Link

183. The Authority has examined as under whether other known factors could have caused injury to the domestic industry:

a. Volume and prices of imports from third countries

184. The imports from other countries are not causing injury to the domestic industry as the same are negligible.

b. Contraction of demand and changes in the pattern of consumption

185. The Authority notes that there is no contraction of demand. Further, there has been no change in the consumption pattern.

c. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

186. There is no known trade restrictive practice.

d. Developments in technology

187. None of the interested parties has furnished any evidence to demonstrate any change in the technology.

e. Export performance of the domestic industry

188. It is noted that injury analysis is based on domestic performance of the petitioner.

f. Performance of other products being produced and sold by the domestic industry

189. The Authority has considered data only in relation to the product under consideration.

g. Other Factors alleged by the interested parties

190. Some of the interested parties have alleged that the injury, if any, being faced by the domestic industry is on account of other factors such as investments made by the domestic industry in setting up a splitting facility in Indonesia, or in Kutch. It has also been submitted by the interested parties that the injury to the domestic industry is on account of its high interest cost. In response, the domestic industry has submitted that its investment in Indonesia has significantly helped it in mitigating its raw material cost. As regards the investment made in Kutch, it has been submitted that the Kutch plant has been closed since 2011 and therefore, it has practically no impact on the present cost.

191. As regards the submission that the injury to the domestic industry is on account of inverted duty structure i.e. high import tariff on CPKO (raw material), the petitioner has submitted that it does not import CPKO for manufacture of the product under consideration, as such, injury being faced by VVF is not on account of the inverted duty structure. The petitioner has submitted that it imports raw material such as Split CPKO, Fatty acid distillates etc., on which import duty of 7.5% is applicable.

192. The Authority notes that the above submissions of the interested parties mainly relate to the interest cost of the petitioner. The Authority has examined the interest being claimed by the petitioner, and only such interest cost, as found reasonable, has been taken in consideration for determination of NIP. The Authority notes that NIP is determined as per the provision of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), Annexure III to the Anti-Dumping Rules and consistent practice of DGTR. The principles of reasonability as provided in the said rules are followed to ensure that no abnormal expenditure on account of interest has been incurred while allowing interest amount for determining NIP. Besides reasonability aspect, the Authority looks into the details of assets deployed to manufacture the PUC and also factors optimum capacity in order to determine per unit cost of interest.

K. Post Disclosure comments

193. The Authority issued a disclosure statement on 22nd September, 2022 disclosing essential facts inviting comment from all the interested parties. The post disclosure submissions have been received from the interested parties. Majority of the issues raised had already been raised earlier and also addressed appropriately. Additional submissions to the extent deemed relevant have been examined as under:

K.1. Submissions made by the Petitioner:

194. Determination of NIP only on cost of sales, without allowing recovery of any return/profit, is contrary to legal provisions and past practices of the directorate. The petitioner has accordingly submitted that NIP be re-determined after allowing a reasonable “return”. It has also been submitted that reduction of interest cost is without any basis and therefore cannot be justified.

195. In respect of the subsidy determination on supply of CPKO at less than adequate remuneration, the petitioner has submitted that Indonesia is the world's biggest supplier of CPKO, catering to about 65% of the world's total CPKO demand. The Indonesian export price, therefore, represents the undistorted market price of CPKO, and the same should be considered as benchmark for both Indonesia and Malaysia.

196. Export price from Malaysia was not based on market conditions due to ban imposed by the USA (one the main purchasers of palm kernel oil from Malaysia) on imports of Palm Kernel Oil produced by some of the biggest plantations in Malaysia.

K.2. Views of the other interested parties

Indonesian Subsidy Programs

197. Imposition of export tax and/or export levy by the Government of Indonesia is a sovereign function for revenue collection and does not amount to subsidy.

198. Sale of CPKO and its derivatives between the private players is conducted at the market prices, without GOI's interference. There is no entrustment or direction by the GOI to the private suppliers to supply CPKO at LTAR. In absence of there being any evidence of "direct transfer of fund", "direct supply of goods by Government for LTAR", "revenue foregone which was otherwise due" or "entrustment or direction to the private players", a finding of subsidy cannot be made.

199. Alternatively, even if it is determined that subsidy has been provided by GOI by provision of CPKO at LTAR, the appropriate benchmark for computing "benefit" received would be the "export price" of CPKO after deducting export tax and export levy component, as the same are export duties collected by the government and not a consideration paid for purchase of CPKO.

200. The interest rates in Indonesia are market determined and based on the credit rating of each customer. A credit worthy customer would always get a better lending rate than the general bank lending rate. The loans taken from Government banks at the same rate as the Private banks cannot be countervailed.

201. One of the interested parties has also submitted that the landed CIF value considered for them in the disclosure statement is different from its claimed landed value.

Malaysia Subsidy Programs

202. Imposition of export duty on CPKO is not a subsidy, as it is not a 'direct transfer of funds' as there is no outflow of funds like in the case of a grant. It is also not a 'foregoing of government revenue' as no revenue is being foregone by the GOM. On the other hand, the GOM is collecting revenue by the imposition of export tax.

203. Further, there is no 'government provision of goods or services' as the GOM through the levy of export tax, is not providing CPKO. The mechanism by which export tax is imposed by the GOM does not envisage any mechanism or supply of CPKO by the GOM. Thus, the alleged measure does not confer a "financial contribution" of any form.

204. It has been submitted that even if the Authority was to hold supply of CPKO at LTAR countervailable, the appropriate benchmark for the subsidy computation would be the export price from Malaysia, as reported on MPOB website. It has been submitted that under CVD Rules, while determining whether goods have been supplied at less than adequate remuneration, the adequacy of remuneration is required to be determined in relation to the prevailing market conditions for the product or service in question in the country of provision or purchase.

205. CIF Rotterdam price of CPKO is highly unreliable as benchmark since it is not based on the actual shipments of CPKO from Malaysia. It is based on inquiries on seller's /broker's quotations on daily basis which may or may not convert to actual export shipments to Netherland (Rotterdam).

206. CIF Rotterdam price is a blend of Indonesia and Malaysia export price quotations for Rotterdam supply in forward trade for one- and two-months supplies.

207. Malaysian producers cannot be punished for high export duty and levied by Govt of Indonesia. Therefore, it does not reflect the actual price of CPKO exports from Malaysia. Indonesia ships annually around 1.5 to 1.8 million tons of palm oil (crude / refined) and Malaysia ships only 0.3 million tons yearly.

208. The Authority cannot take contrary stand for CPKO benchmark for Malaysia when it has taken FOB export prices for Indonesia and FOB export prices for RBDPKO from Malaysia.

Thailand Subsidy Programs

209. Countervailing duty cannot be imposed on the drawback provided by the GoT as the same is a permissible duty remission in terms of Footnote 1 to Article 1 of the ASCM. It has been submitted that duty drawback provided under Section 9 of the Thai Customs Act is not a subsidy as only provides duty exemption on inputs used for export production.

210. It has been claimed that the interested parties have demonstrated the existence of verification mechanism adopted by the GoT to ensure that there is no excess remission.

K.3. Examination by the Authority

211. The Authority notes that most of the submissions made by the interested parties have already been dealt with the preceding paras. As regards the claim of the petitioner that a “reasonable return” be granted to them for determination of the NIP, the Authority notes that NIP has been determined as per the Annexure III of the AD Rules and the consistent practice of the directorate.
212. As regards the submissions in respect of benchmark price adopted for Indonesia, it is noted that the Authority had considered CPKO export prices from Indonesia to the rest of the world as an appropriate benchmark as they are set according to free market principles, reflect prevailing market conditions in Indonesia, and are not distorted by government intervention. Many interested parties have claimed that the export tax and export levy applicable on such exports should be excluded from the export price, for determining the benchmark price. The Authority does not find any merit in the said submission, as what has been considered for benchmark comparison is the average “export price” of the CPKO from Indonesia since that is the price at which CPKO has been sold to foreign customer. It is the difference between this price charged from the foreign customers, vis-à-vis purchase price of the domestic consumers, that has been considered for subsidy computation. The benefit that accrues to a domestic purchaser of CPKO is the price difference between its CPKO purchase price and the undistorted export price.
213. The Authority notes that Rotterdam price is a global benchmark for trade in palm kernel oil. The Rotterdam price represents the undistorted price for CPKO, and is an index similar to London Metal Exchange for metal products. It is the common submission of both the exporters and the domestic industry that “CIF Rotterdam price” indicates the price at which contracts are being entered into on a particular date. It has been seen that many exporters as well as the domestic industry use CIF Rotterdam price as a reference for entering into contract for CPKO. Even as per GOI’s submission, the CIF Rotterdam price of CPKO is taken in consideration for determining “reference price” for determining export tax and export levy on CPKO.
214. It has been claimed by the Malaysian exporters that MPOB price should be considered as the same is representative of undistorted Malaysian price. In this regard, the Authority notes that where CIF Rotterdam price indicates the price existing on a particular date, in contrast, MPOB prices are the price as on the shipment date, i.e. the date on which exports have happened. It is seen that there is usually a time difference of few months between contract date (when the price is fixed) and the shipment date. As noted earlier, the export levy was reimposed by Malaysia from January’2021 onwards, and prior thereto there was no export tax on exports of CPKO. Consequently, the contracts entered into prior to January’ 2021, which would have been shipped in subsequent months, are not likely to have factored in the export tax component. This is also evident from a comparison of MPOB export price and CIF Rotterdam price, from which it can be seen that the MPOB’s CPKO export price for initial few months was lower than CIF Rotterdam prices, whereas in the subsequent months it was either higher or in the same range. Therefore, in order to make a fair comparison, CIF Rotterdam price (adjusted for freight and insurance) has been considered as the appropriate benchmark for both Indonesia and Malaysia and the subsidy margin thereon has been determined accordingly.
215. As regards the benchmark price for Refined Bleached Deodorised Palm Kernel Oil (“RBDPKO”), the petitioner had submitted RBDPKO export price from Malaysia, as reported on Oleoline. It has been submitted that there is no alternate benchmark available for the same, as it is not recorded either at Rotterdam or at Indonesia. The interested parties have also not provided any alternate benchmark for the same. The Authority has, therefore, considered export price of RBDPKO as the appropriate benchmark for subsidy computation.
216. As regards submissions made on computation of the subsidy margins, the same have been considered in these final findings and changes, as found appropriate, have been made in the subsidy margins determined above.
217. As regards the submission regarding change in the landed value, the Authority notes that the landed value has been considered by the Authority as per the information provided by the interested parties.
218. Some of the interested parties have also claimed that since the loans have been given to them by the Government banks and private banks at the same rate, therefore there is no subsidy. The Authority notes that the fact that private banks are also providing loans at a significantly lower lending rate, as compared to the applicable prime lending rate, is in itself a clear indication of “entrustment or direction” by the governments of the subject countries to the private banks, to provide financial contribution in the form of preferential lending. The same has therefore been held to be countervailable.
219. In response to the benchmark disclosure, it has been claimed by some of the participating exporters from Indonesia that while determining the benchmark price of CPKO, deduction of export tax, export levy and other port expenses is required to be made. The Authority has already noted above that the deduction of export tax and levy would defeat the very purpose of the examination. As regards claim for deduction of port expenses, it is noted that what has been considered is the price at which CPKO is being supplied to importers at Rotterdam. A standard deduction of USD 50/MT has been made to exclude all expenses relating shipment cost. No

evidence has been provided by the said exporters to support the claim that these port expenses are part of the CIF value or that they are over and above USD 50/MT being deducted. In absence thereof, the Authority does not find any merit in the claim being made by the interested parties.

220. Further, it is noted that one of the Malaysian exporter has provided one of its invoices to substantiate that the freight charges from Malaysia to Rotterdam is around USD 70/MT. It is noted that the said invoice is of a shipment of around 1500-2000 MT of SFA and not of CPKO. The Authority notes that the freight cost for SFA and CPKO are not identical as, firstly, SFA is a chemical product and therefore is imported in a very protected environment such as in Stainless steel tanks with nitrogen blanketing to ensure that the chemical properties do not get affected. On the other hand, CPKO being a crude natural oil, it is usually imported in Mild Steel tanks. Secondly, SFA is imported in smaller quantities, whereas CPKO is usually imported in bulk quantities of 15,000 to 20,000 MT. Moreover, the Authority notes that the European Chemical Agency (ECHA) as per the REACH registrations, considers SFA to be hazardous as being very toxic to aquatic life and is toxic to aquatic life with long lasting effects³. On the other hand, CPKO is not considered as a hazardous product⁴. Therefore, the shipment cost of CPKO cannot be compared with that of SFA. The Authority, accordingly, rejects the said claim of the exporter.

L. Indian industry's interests and other issues

L.1. Submission by the other interested parties

221. It has been claimed by the other interested parties that imposition of countervailing duty, if any, on the subject goods would not be in public interest due to following reasons:

- i. because of its raw material dependency, high interest cost and other inefficiencies, the petitioner would not be able to meet the Indian demand for the PUC.
- ii. increase in the cost of the PUC would lead to an increase in the costs of products such as soap, detergents etc., which are routinely used by the public at large.
- iii. a levy of duty on the PUC would lead to an increase in imports of the downstream products of the PUC, such as ethoxylates, SLES, and SLS, which are currently subject to 0% basic customs duty under the ASEAN Free Trade Agreement. Imposition of duty would lead to an inverted duty structure for the downstream industries, thereby leading to increase in the imports of downstream goods. This will in turn lead to loss of business and employment for the downstream industries.
- iv. There has been a significant increase in the production capacity of the downstream products in subject countries. It is very likely that the exporters would start exporting downstream products (SLS/SLES or Ethoxylates) if duties are imposed on SFA.
- v. The capacity of the petitioner is not sufficient to meet the Indian demand and imposition of duty, if any, would lead to demand supply gap in the Indian market.

L.2. Submissions made by the Petitioner

222. Imposition of the duty would be in the interest of the downstream industries as well as the public at large.

223. The installed capacity of the petitioner alone is sufficient to meet about 80% of the Indian demand. As such, imposition of duty is not likely to cause any demand supply gap in the Indian market.

224. The purpose of imposition of countervailing duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices and restore fair competition in the Indian market.

225. There would be a negligible (0.3%) impact of duty on the cost of consumer products.

226. If the protection of duties is not granted to the domestic industry forthwith, it would not be able to survive and consequently, the entire downstream industries would become dependent on imports for their raw material (SFA) requirement.

227. The increase in capacity of downstream products (SLS/SLES) in the subject countries, significantly in excess of the local demand, clearly indicates that once the petitioner, that is the Indian domestic industry is wiped out, the subject countries would encourage exports of downstream products.

228. Moreover, if the Petitioner is wiped out, the downstream producers would become dependent solely on imports for their raw material (SFA) requirement, which would not be in their larger interest.

³ <https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.105.704>

⁴ <https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.029.473>

L.3. Examination by the Authority

229. The Authority has examined whether the imposition of the anti-subsidy duty on imports of the product under investigation would be against the larger public interest. This determination is based on consideration of information on record and interests of stakeholders, including the domestic industry, importers and consumers of the product.

230. The Authority notes that the total production capacity of the petitioner is *** MT and that of Godrej Industries is around *** MT, as against the demand of approximately 1,45,000 MT. Evidently, the Indian production capacity is sufficient to meet almost the entire Indian demand by itself. As such, the question of there being a demand supply gap does not arise in the present fact of the case. The Authority also notes that the claim of the interested parties that the petitioner has a limited capacity to produce C1214 blend is factually incorrect. The Authority notes that the petitioner had significant unutilised capacity during the POI, which is not the cause rather the consequence of the material injury being caused by the subsidized imports. As regards allegation regarding high finance cost of the Domestic industry, the same has been factored in while determining non-injurious price of the domestic industry, and interest cost has been moderated to arrive at a reasonable interest cost.

231. The Authority further finds that the PUC is an industrial raw material primarily used in manufacture of SLS, SLES or Ethoxylates etc., which are in turn used for manufacturing FMCG products such as soap, shampoos, detergents etc. Being an industrial raw material, it is noted that the duty imposed on the PUC would get passed through to the ultimate end consumer. Therefore, the impact of duty on end consumer is required to be seen. The petitioner has provided a quantified working of the impact of duty on the end consumer, which has not been controverted by the interested parties. It is seen that the impact of average duties on the price of the end product would be negligible.

232. The importers/users of the subject goods have claimed that the imposition of duty would lead to an inverted duty structure for downstream products such as SLS, SLES and Ethoxylates, as they attract nil import duty under ASEAN FTA. It has been submitted by them that the exporters of the subject countries are forwardly integrated and are expanding their downstream production capacity, significantly in excess of local demand. In these facts, the Authority notes that if the domestic industry is wiped out, the downstream industry would become completely dependent upon imports for their raw material requirement. As the exporters from subject countries are expanding their downstream capacity, it is imminent that the exports of SFA would, in absence of a domestic SFA supplier, be replaced by exports of value added downstream products, i.e. SLS, SLES and Ethoxylates. Being dependent on imports for raw material requirement might in fact put the Indian downstream industries in the same situation as that of the domestic industry, where they might have to compete with the cheap downstream products from the subject countries.

233. The uncontroverted fact that has emerged from the investigation is that the domestic industry would not survive unless adequate protection is provided to them. It is noted that if the domestic industry is wound up, in absence of any local source of raw material, the downstream manufacturers will be at the complete mercy of exporters who would then be in a position to dictate prices and can simply increase the prices of SFA. Further, given the fact that the subject countries are actively encouraging exports of value added products through provision of inadmissible subsidies, making the downstream industry completely dependent on imports for their raw material requirement would be catastrophic.

234. It is further noted that both SFA and its downstream products, Ethoxylates and SLS/SLES attract Nil customs duty under the ASEAN FTA. The imposition of CVD would merely correct the price, by removing impact of inadmissible subsidies being provided by the subject countries. In case, however, if the inadmissible subsidies are passed on to downstream manufacturers in the subject countries with a view to circumvent the duties, the Indian industries would be eligible to seek protection against the same. It may be noted that the Authority has herein above already determined that the subject countries are providing inadmissible subsidies, particularly provision of raw material (CPKO) at LTAR by the Governments of Indonesia and Malaysia. If the subsidies are continued, and the raw material for SLS, SLES and Ethoxylates is supplied at LTAR, the downstream producers would always have an option to seek appropriate remedy against the same. However, an unfair trade practice cannot be allowed to be perpetuated and the same needs to be redressed.

235. It has also been submitted by the downstream industries that protecting one company (i.e. the Petitioner) at the cost of multiple downstream companies, would not be in public interest. In this regard, it is noted that the purpose of anti-subsidy investigation is to grant protection to the domestic industry as a whole by neutralising inadmissible subsidies being provided by the subject countries. As such, whether the domestic industry currently comprises of one company or multiple companies is an irrelevant consideration. In fact, once adequate protection is granted, it is possible that it would attract further investment. India, owing to its population, is one of the key consumers of the subject goods. It is, therefore, likely that once the inadmissible subsidies are countervailed and a level playing field is established, the production of SFA would move towards the demand

market, i.e. India. Moreover, the Authority notes that value addition from CPKO (raw material) to SFA is about 70%, whereas from SFA to Ethoxylates/SLES is about 10-11%. As such, imposition of duties would encourage value addition in India and would, thus, be in the larger public interest.

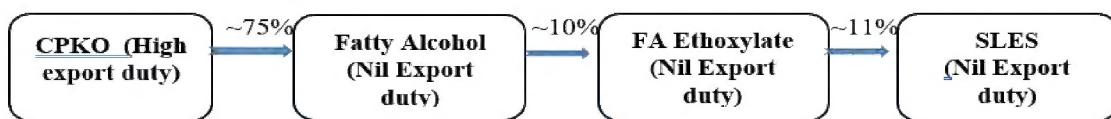
236. The Authority further notes that the purpose of imposition of countervailing duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of subsidization so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of countervailing duty would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.
237. The Authority is mindful of the fact that the imposition of countervailing duty might affect the cost of the subject goods. Rather, the imposition of the countervailing measures ensures fair competition in the Indian market, particularly when the levy of the countervailing duty is restricted to an amount necessary to redress the injury caused to the domestic industry by the imports of subsidized subject goods. Imposition of countervailing measures would in fact remove the unfair advantages gained by subsidization, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.
238. As regard the effect of the measures on the participating importers/user industry, the Authority has considered that their profits may be somewhat affected by the imposition of measures. It is noted that the importer industry's profitability ranges between single digit to double digits. In view of their profit margins, the effect would not be disproportionate, as, at least part of the increase in price, could be passed on to their customers. Further, given the inadequate profitability of the domestic industry and price depression on the market, it can reasonably be assumed that prices will increase after measures are imposed. Nevertheless, the impact measures may have on certain users should be balanced against the risk of a discontinuation of the domestic industry activity as the current situation is not sustainable. Not imposing measures will lead to less reliable and stable sources of supply and inevitably to price increases in the Indian market. The Authority therefore, concludes that imposition of duty would be in the larger public interest.

M. Conclusion

239. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in the above findings, the Authority concludes that:
 - i. The product under consideration has been exported to India from subject countries at subsidized prices. It is noted that the subject imports are causing significant price and volume injury to the domestic industry.
 - ii. The Governments of Indonesia and Malaysia have imposed export restraints in the form of export tax and export levy on the exports of crude palm kernel oil (CPKO) and its derivatives, which is the primary raw material for producing the PUC. It is an admitted position on record that the purpose and object of imposition of these export restraints is to encourage the downstream value addition onshore and to increase competitiveness of such downstream industries in the international market. The evidence on record has shown that the said export restraints have in fact compelled the domestic suppliers of CPKO to supply CPKO domestically at prices significantly below the appropriate benchmark world market price considered by the Authority. It is found that there is a demonstrable link between the export restraints imposed and the conduct of private CPKO suppliers in supplying CPKO at below world market price. The Authority, therefore, holds that price difference between domestic price of CPKO and the benchmark price as a subsidy being provided by the said countries.
 - iii. The Authority is simultaneously conducting a sunset review of the Anti-dumping duty imposed on the subject goods. In order to avoid overlap, any export subsidy which results in lowering of the export price and not the cost of production, is separately mentioned, and appropriate duties have been recommended accordingly.
 - iv. As regards the claim of the interested parties that the injury to the domestic industry is on account of its high finance cost and lack of working capital, the Authority notes that the financial condition of the domestic industry is not the cause of the injury but is in fact a consequence of the injury being faced by them. It is noted that the production of PUC is a cash intensive process, as the raw material itself accounts for approximately 70% of the cost. As such the working capital requirement of the company is comparatively higher. However, since the domestic industry has not been able to make profitable sales, it did not generate any funds, which has resulted in its high finance cost. In any case, reasonability of finance cost has been examined and only such finance cost that was found to be reasonable has been considered for NIP determination. Thus, injury attributable to any abnormal interest cost has not been considered in the injury margin determination.

v. It is noted that the petitioner is the sole Indian producer of mid-cut alcohol, which has the highest demand (about 90%) in the Indian market. It is an admitted fact that the financial condition of the petitioner is abysmal, and it would not survive unless adequate protection is granted to them. Thus, if the inadmissible subsidies being provided by the subject countries is not neutralised, the domestic industry for mid-cut alcohol would be wiped out, thereby making the downstream industries completely dependent on imports for their raw material requirement. Having a viable domestic source of raw material is in the greater interest of the Indian downstream industry.

vi. It has been submitted that the exporters of the subject countries are forwardly integrated and imposition of duty on SFA would lead to increase in imports of downstream products such as Ethoxylates and SLS/SLES. The value chain of oleochemical industry and their value addition percentage is as below:



vii. From the above, it is seen that the CPKO is primary raw material for the entire value chain. The Authority has herein above already determined that the subject countries have provided inadmissible subsidies, particularly provision of raw material (CPKO) at LTAR by the Governments of Indonesia and Malaysia. If the subsidies are continued, and the raw material for SLS, SLES and Ethoxylates is supplied at LTAR, the downstream producers would always have an option to seek appropriate remedy against the same. However, an unfair trade practice cannot be allowed to be perpetuated and the same needs to be redressed.

viii. It is further noted that the domestic industry is carrying out significant value addition in India, as such it would be in larger public interest to give them a level playing field by neutralising the subsidy being enjoyed by the producers in the subject countries.

ix. It is also noted that the PUC is an industrial raw material. As such, the downstream industries would be able to pass on at least a part of duty to the end consumers. It is noted that the impact of even a 35% duty, on the end consumer would be negligible.

N. Recommendation

240. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties including Government of Malaysia, Government of Thailand , and Government of Indonesia and adequate opportunity was given to provide information/evidence on the aspect of subsidization, injury and causal link. . Having initiated and conducted the investigation into subsidization, injury and causal link in terms of the Rules laid down and having established positive subsidy margin as well as material injury to the domestic industry caused by such subsidized imports, the Authority is of the view that imposition of definitive countervailing duty is required to offset subsidization and injury. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive countervailing duty on the imports of the subject goods from the subject countries in the form and manner described hereunder. The Authority has recommended continuation of the anti-dumping duties in the parallel sunset review investigation concerning the subject goods (excluding C10) vide its Final Findings F.No. 7/01/2022-DGTR dated 02.02.2023. The adjustment of the recommended ADD, where warranted, has been provided in the duty table below. Further, since the injury on account of export subsidies are already addressed in the sunset review final findings, therefore, the export subsidies have been adjusted in the duties recommended herein.

241. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive countervailing duty equal to the lesser of margin of subsidy and margin of injury for a period of five (5) years, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, so as to remove the injury to the domestic industry. The Authority has noted the fact that the PUC is already attracting anti-dumping duty, accordingly, the adjustment of the same, where appropriate, has been provided in the table below. It is mentioned that for some of the producers/exporters, the duty mentioned in Col. No. 7 below is based on the injury margin as per lesser duty rule, and therefore, countervailing duty equal to the difference of duty specified in Col. No. 7 below and anti-dumping duty payable thereon, has been recommended. In other cases, where the injury margin was found higher than the total of subsidy margin and anti-dumping duty payable thereon, no adjustment of the anti-dumping duty has been provided.

242. Accordingly, definitive countervailing duty as mentioned in Col No. 7 of the duty table below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government on all imports of the subject goods from the subject countries.

DUTY TABLE

Sl. No.	Heading/ Subheading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty amount as % of CIF value
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	2905.17, 2905.19, 3823.70	Saturated Fatty Alcohol of Carbon chain length C10 to C18 and their blends	Indonesia	Any including Indonesia	M/s PT Ecogreen Oleochemicals	14% *
2.	-do-	-do-	Indonesia	Any including Indonesia	M/s PT Musim Mas	20%*
3.	-do-	-do-	Indonesia	Any including Indonesia	M/s PT Wilmar Nabati Indonesia	27%*
4.	-do-	-do-	Indonesia	Any including Indonesia	M/s PT. ENERGI SEJAHTERA MAS	4%*
5.	-do-	-do-	Indonesia	Any country including Indonesia	Any other than 1 to 4 above	30%*
6.	-do-	-do-	Any country other than Indonesia, Malaysia & Thailand	Indonesia	Any	30%*
7.	-do-	-do-	Malaysia	Any including Malaysia	M/s FPG Oleochemicals Sdn. Bhd.	3%*
8.	-do-	-do-	Malaysia	Any including Malaysia	M/s KL - Kepong Oleomas Sdn. Bhd.	9% #
9.	-do-	-do-	Malaysia	Any country including Malaysia	Any other than 7 to 8 above	11% #
10.	-do-	-do-	Any country other than Indonesia, Malaysia & Thailand	Malaysia	Any	11% #
11.	-do-	-do-	Thailand	Any including Thailand	M/s Global Green Chemicals Public Company Limited	3% \$
12.	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	Any other than 11 above	5% \$
13.	-do-	-do-	Any country other than Indonesia Malaysia & Thailand	Thailand	Any	5% \$

* For Serial No. 1 to 7 above, the amount of countervailing duty to be imposed is equivalent to the difference between the quantum of countervailing duty mentioned in Col No.7 and antidumping duty payable, if any. (i.e. **CVD= Duty in Col 7 above minus ADD, if any**)

For Serial No. 8 to 10, the quantum of countervailing duty to be imposed is in addition to the anti-dumping duty payable, if any, as recommended subsidy and dumping margins are less than the injury margin. (i.e. **CVD = Duty in Col. 7 above**)

\$ For Serial No. 11 to 13, the quantum of CVD to be imposed would be the Countervailing duty mentioned in Col No.7 minus antidumping duty payable, if any. If the differential amount is negative, no countervailing duty shall be collected in such case. (i.e. **CVD= Duty in Col 7 above minus ADD, if any**)

O. FURTHER PROCEDURE

243. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Jt. Secy. & Designated Authority